हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 जुलाई, 1998

खण्ड - 2, अंक - 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 28 जुलाई, 1998

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)28
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं	(6)36
वाक आउट	(6)47
वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनाओं से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(6)47
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(6)50
बैठक का समय बढ़ाना	(6)77
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)77
बैठक का समय बढ़ाना	(6)89
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)90
बैठक का समय बढ़ाना	(6)97
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)97

बैठक का समय बढ़ाना (6)113
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (6)113
बैठक का समय बढ़ाना (6)116
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (6)116
बैठक का समय बढ़ाना (6)125
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) (6)125
विल्स—
(i) हरियाणा सहकारी सोसायटी (संशोधन), विधेयक, 1998 (6)134
(ii) पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1998 (6)136

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 जुलाई, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर्ज साहेबान, अब सवाल होंगे।

Seepage in Loharu Canal

***757. Shri Satpal Sangwan :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the several thousand acreage of land of Achina, Rawaldhi, Loharwala, Khatiwas, Dhikra, Charkhi, Khera Bura, Biri, Barsana, Manakwas and Ghasola etc. villages has become uncultivable due to the seepage in Loharu Canal; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to make the aforesaid land cultivable ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) जी हां, श्रीमान जी।

(ख) लोहारू नहर में रिसाव को कम करने के लिए क्षति ग्रस्त लाईनिंग का काम किया गया। 6,500 फुट लाईनिंग रुपये 6 लाख की लागत से पहले ही मरम्मत की जा चुकी है। धन की उपलब्धता पर बाकी बचे कार्य को फेजों में दो साल के अन्दर-अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके इलावा लोहारू नहर के साथ एक "सीपेज ड्रेन" का निर्माण प्रस्तावित है, ताकि साथ लगते खेतों में रिसाव के पानी का प्रवेश पर नियन्त्रण किया जा सके।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, इस पर मेन्टीनेंस का जो काम हुआ है यह बहुत अच्छा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह का मेन्टीनेंस का जो काम अभी चलाया पड़ा है वह भी करवा जाये क्योंकि इससे पहले इस नहर की आज तक कभी भी मेन्टीनेंस वगैरा नहीं की गई थी और उसमें बड़े बड़े होल थे इसलिए अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से कम्पलीट करवाया जाये।

श्री हर्ष कुमार : स्पीकर साहब, ठीक है, हम इस काम को और जल्दी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जब वर्ष 1995 में बाढ़ आई थी तो उस वक्त उससे दादरी, कलानौर, जीन्द मिसाथल के एरियाज में काफी हालत खराब हुई थी। वहां पर 10-10 फुट पानी खड़ा रहा जिस वजह से आज वह जमीन काबिले काश्त नहीं रही। सीपेज की वजह से यह सब हुआ है। जूई कैनाल के साथ लगते एरिया में यह सीपेज की समस्या अधिक बढ़ी है। वर्ष 1995-96 में उस वक्त की सरकार ने मैनुवल लेबर से काम करवाने की बजाये मशीन से करवाया गया था जिससे वहां सीपेज ज्यादा हो रहा है। क्या अब आप उस काम को दुबारा ठीक ढंग से करायेंगे ताकि सीपेज को रोका जा सके ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि हमने सफाई का काम शुरू किया हुआ है। मेन्टीनेंस का काम चल रहा है। सतपाल सांगवान उस वक्त मेरे साथ थे जब हमने इनके एरियाज का निरीक्षण किया था। जिस ढंग से अब काम हो रहा है उसकी काफी अच्छी प्रोग्रेस है। जहां-जहां पर काम हो रहा है उसकी डिटेल्ज मैं आपको भिजवा दूंगा। आप भी इस काम को देख लेना और मैं भी स्वयं जाकर देख लूंगा।

Evening College

***671. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Evening College of Maharshi Dayanand University, Rohtak has been closed; if so, the reasons thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : जी हां। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय सांध्यकालीन महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक अनुरक्षित महाविद्यालय था। विश्वविद्यालय ने यह निरीक्षण करने हेतु कि क्या सांध्यकालीन महाविद्यालय को चालू रखना आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से उचित है, विशेषज्ञ तथा अनुभवी शिक्षकों/अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने एक चेतनात्मक सन्तुति की कि इतने बड़े खर्चे से सांध्यकालीन महाविद्यालय को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे तुरन्त प्रभाव से बन्द किए जाने से कोई लोक अहित नहीं होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने तदानुसार निर्णय लिया।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या इस सांध्यकालीन महाविद्यालय में निरंतर 3 वर्षों से शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या घट रही थी या बढ़ रही थी ? इस प्रकार के और भी बहुत से कालेज हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है लेकिन वहां पर अभी यह सुविधा उपलब्ध है। फिर इस महाविद्यालय को ही बन्द क्यों किया गया ?

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय में दिन में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या रही है उसकी 5 प्रतिशत से अधिक संख्या सांध्यकालीन कक्षाओं में बच्चों की नहीं रही। दिन में जो लोग मजदूरी करते हैं या नौकरी पेशा करते हैं उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे चलाया गया था। यह सुविधा कई और जगहों पर भी है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सांध्यकालीन एल०एल०बी० की व दूसरे कोर्सिज की कक्षाएं लगती हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से आई०ए०एस० और बाकी दूसरे लोग उसमें एल०एल०बी० करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यह भी विद्यालय रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस में भी प्रारंभ किया गया था परंतु इस महाविद्यालय में नौकरी

पेशे वालों की संख्या 5%से अधिक नहीं थी दूसरे प्राईवेट लोग ज्यादा थे। अध्यक्ष महोदय, श्री माजरा जी ने कहा कि कई जगहों पर इस महाविद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या से कम के भी और महाविद्यालय हैं। उनकी यह बात बिल्कुल सही है, जैसे दुबलधन में है, नगीना में है। अध्यक्ष महोदय, नगीना महाविद्यालय में तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि प्राध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या से बढ़ जाती है। मेवात का इलाका है, मोरनी का इलाका है इन इलाकों में भी ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें छात्रों की संख्या यूनिवर्सिटी के कैम्पस में चलने वाले कालेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कम है फिर भी हम उनको चला रहे हैं। इन सबको हम जन हित के लिए चला रहे हैं। इनके एरियाज के पिछड़ेपन को देखते हुए चला रहे हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी के कैम्पस में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैम्पस में 2600 की कैपेसिटी का महाविद्यालय चल रहा है और उसमें हम कितने भी छात्रों को दाखिल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कदम एकदम नहीं उठाया गया बल्कि वहां के छात्रों की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से जब इस बारे में बात आई उसके बाद ही इस मामले को यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटीव कांउसिल में रखा गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटीव कांउसिल ने एक उपसमिति बनाई। उस उपसमिति ने इन सारी बातों का निरीक्षण किया, जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यहां पर इतने बड़े खर्चे से सांध्यकालीन महाविद्यालय चलाने के बजाय इसका समायोजन कैम्पस में जो बड़े कालेज हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत है, छात्र संख्या के हिसाब से अध्यापकों के हिसाब से उनमें कर दिया जाए। इसलिए सर, बाद में यह निर्णय लिया गया।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में एक बात कही है कि दुबलधन और नगीना में सांध्यकालीन महाविद्यालय उन इलाकों के पिछड़ेपन को देखते हुए चला रखे हैं, क्या रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस के सांध्यकालीन महाविद्यालय में गांव के छात्र पढ़ने के लिए नहीं आते ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस के सांध्यकालीन महाविद्यालय में 5% लोग ही ऐसे पढ़ने आते थे जो नौकरी-पेशे वाले थे। क्या इन्होंने इस बात का सर्वे कराया है ? मैं नहीं मानता कि वहां पर नौकरी पेशे वाले सिर्फ 5 % लोग ही पढ़ने आते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा आते हैं। फिर इस महाविद्यालय को क्यों बंद किया जा रहा है इस बात पर मंत्री महोदय क्या कुछ रोशनी डालेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बलवंत सिंह मायना जी ने गांव के छात्रों के बारे में जो बात कही है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक उन छात्रों के पढ़ने का सवाल है वे छात्र रात में पढ़ने के लिए नहीं आते, वे दिन में ही आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय में ऐसे छात्रों की संख्या ज्यादा थी जो कई वर्षों से फेल हो रहे थे या किसी और कारण से महाविद्यालय में रहना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है तब से हम इस यूनिवर्सिटी के वातावरण को पढ़ाई योग्य और अनुशासित बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस में जो वास्ट इंस्टिच्यूट्स हैं उसमें सब तरह के कोर्सिज हैं जैसे पॉलिटैक्निक, इंजीनियरिंग, बी०एड० आदि। अकेले एक संस्थान में 20-22 हजार छात्रों की संख्या है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस यूनिवर्सिटी में कोई कालेज बंद नहीं किया बल्कि जो सांध्यकालीन महाविद्यालय था उसका समायोजन दिन में चलने वाले बड़े संस्थान में कर दिया।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने प्रश्न के लिखित जवाब में और बाद में जो सप्लीमैंट्रीज़ की गई हैं उनके जवाब में अलग-अलग बात कही है। मैं आपके द्वारा इनको यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट आदि जनता से जुड़े हुए

[श्री धीरपाल सिंह]

विभाग हैं इसलिए इन के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान होना होता है। अध्यक्ष महोदय, जो इवनिंग क्लासिज़ बन्द की गई हैं वह इस इलाके के लोगों के साथ द्वेष की भावना के कारण बन्द की गई हैं। श्री राम विलास जी बहुत योग्य मन्त्री हैं इसलिए उनसे मेरी पुरज़ोर गुजारिश है कि वे इस पर फिर से गौर करें। इसमें केवल स्टाफ का समायोजन किया गया है, उसमें 5% या 10% बच्चों की बात नहीं है बल्कि यह मामला हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए इस बारे में क्या वे दोबारा विचार करेंगे ? मेरा एक प्रश्न तो यह है। इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल महिलाओं की शिक्षा के बारे में है। यहां पर महिलाओं की चर्चा हो रही है। अग्रसेन कॉलेज झज्जर के अन्दर साईंस की क्लासिज़ चल रही थी वह भी बन्द कर दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर देहात की बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। भले ही झज्जर को जिला बना दिया गया है लेकिन वह अभी एक कस्बा ही है और वहां पर पढ़ने आने वाली 100% लड़कियां देहात से आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे देहात की बच्चियों को साईंस के सब्जैक्ट से अलग रखने की कुचेष्टा नहीं कर रहे हैं ? इस बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री धीरपाल सिंह जी से कहना चाहूंगा कि जो जवाब लिखित रूप में दिया गया है उसके तदानुरूप ही मैंने अपनी बात कही है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं। (विघ्न) झज्जर का वैश्य कॉलेज इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी मैं चौधरी धीरपाल सिंह जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के कुछ नियम होते हैं उनके अनुसार यूनिवर्सिटी हर कालेज का सर्वेक्षण करती है। वैश्य कॉलेज झज्जर के बारे में लोगों की शिकायत थी कि वहां पर ट्रेंड प्राध्यापक नहीं हैं फिर भी वहां पर विज्ञान की क्लासिज़ चलाई जा रही हैं। इस बात की जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने एक दल वहां पर भेजा जिसने वहां पर विज्ञान की क्लासों को देखा और यह पाया कि वहां पर विज्ञान की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन क्लासों को बन्द करने की सिफारिश कर दी। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं अपने भाई धीरपाल सिंह जी को एडवाईस करूंगा कि वे वहां की मैनेजमैंट से मिल लें और उनसे कहें कि विज्ञान क्लासिज़ चलाने के लिए वहां पर योग्य प्राध्यापकों का प्रबन्ध करें। उनको आश्वासन देता हूं कि यदि मैनेजमैंट ऐसा कर देती है तो हम वहां पर ये क्लासें शुरू करने के लिए फिर से विचार कर सकते हैं।

श्री विजेन्द्र सिंह कादवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे यहां थर्मल पावर प्लांट कॉलोनी में एक दम जमा दो का स्कूल है जो कि यह सोच कर खोला गया था कि यहां के इम्पलाईज़ के बच्चे यहां पर पढ़ सकेंगे। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यह स्कूल खोला गया था लेकिन उनको वहां पर यह सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल है वह अपनी मनमर्जी करता है। एक ही स्कूल उस ऐरिया में होने के कारण उसने अपनी मोनोपली बना रखी है। (विघ्न) मैं चाहूंगा कि इस स्कूल की चैकिंग की जाए। इसके साथ ही वहां पर एक हाई स्कूल भी है मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको 10 जमा 2 में अपग्रेड किया जाए ताकि इस स्कूल की मोनोपली न रहे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक डी०ए०वी० स्कूल कांट्रैक्ट बेसिज़ पर क्लासिज़ चला रहा है जिससे वहां के बिजली बोर्ड के इम्पलाईज़ बड़े परेशान हैं। क्या इस बारे में मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे ? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे सवाल से इस सप्लीमेंट्री का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं अपने भाई बिजेन्द्र सिंह कादयान जी को बताना चाहूंगा कि एच०एम०ई०बी० कालौनी पानीपत के डी०ए०वी० स्कूल के बारे में कुछ शिकायतें मुझे भी मिली हैं और इस बारे में हम जांच करवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी ने बताया है कि यूनिवर्सिटी के सांध्यकालीन कॉलेज के कुछेक विद्यार्थी थे जो लगातार फेल होते जा रहे थे इसलिए भी इसको बन्द करना पड़ा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी तो 1 या 2% होंगे। यदि किसी कॉलेज में 5-7 विद्यार्थी अपना कोई स्वार्थ पूरा कर रहे हैं तो उनको निकालने की बजाए इन्होंने कॉलेज ही बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 5-7 विद्यार्थियों को कॉलेज से निकालने की बजाए कॉलेज को ही बन्द कर देना वहां के लोगों को परेशान करना है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि इस कॉलेज को बन्द करने की बजाए उन्होंने शरारती तत्वों को इस कॉलेज से निकालने की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी सिरी कृष्ण हुड्डा को बताना चाहूंगा कि यह हमने नहीं किया है। वैसे इसको बंद करने से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बचत भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला कई वर्षों से चल रहा था और डेढ़ साल पहले ही एग्जिक्यूटिव काउंसिल बनाई गई और उसकी एक उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लिया गया। (विघ्न)

Construction of a Link Road from Village Kailashpur to Sonipat City

***635. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is no proper link road/passage from village Kailashpur to Sonipat City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the aforesaid village with Sonipat-Bahalgarh road or sector-15 of Sonipat CIty ?

Public Works Minister (Sh. Dharam Vir Yadav) :

(a) Yes. Sir.

(b) There is no such proposal at present.

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के दो गांव हैं जिनका नाम बईयांपुर खुर्द और कैलाशपुर है। वहां पर रास्ता न होने के कारण लोग खेतों में से होकर मेन सड़क पर पहुंचते हैं जिसकी वजह से वहां पर कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों गांवों का रास्ता जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। मंत्री जी यह भी बताएं कि ये रास्ते कब तक बन जाएंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये गांव नान-डायरेक्टरी में आते हैं। जिन गांवों की आबादी 250 से कम हो वहां पर सड़कें बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रिप्लाई दी है उसमें तो इन्होंने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया है कि there is no such proposal at present. एट प्रैजन्ट नहीं तो क्या फ्यूचर में ऐसी प्रपोजल ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लेटस्ट पोजीशन की असैसमैंट करवा लेंगे और अगर जरूरत होगी तो वहां पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, चईथपुर खुर्द गांव की 3,000 की आबादी है और कैलाशपुर की 4000 की आबादी है। मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि वहां की 250 की आबादी नहीं है। मेरा इनसे अनुरोध है कि वहां पर जल्दी सड़कें बनवायें ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम पहले लेटस्ट पोजिशन की असैसमैंट करवा लेंगे और उसके हिसाब से जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको हम करेंगे।

Construction of Small Dam on Krishnawati River

***645. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in Narnaul Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct small bandh (Dam) on Krishnawati river at Nangal Choudhary, Maandi and Kojinda villages to solve the problem of the drinking water of the said area ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन नाथ) :

(क) 26 गांवों में कुछ कमी है परन्तु बहुत कमी नहीं।

(ख) 26 पानी की कमी वाले गांवों में जल वितरण में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। कृष्णावती एक बरसाती नाला है। इस पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर सर, मैं नारनौल या महेन्द्रगढ़ के लिए पीने के पानी की समस्या के बारे में बार-बार इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि वहां पर कोई भी नहर बेस्ड स्कीम नहीं है। इसलिए वहां पर पीने के पानी या तो ट्यूबवैल से दिया जाता है या बोरिंग करके दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, नारनौल में तो एक कैनाल बेस्ड स्कीम है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ नारनौल में ही है बाकी उस पूरे हल्के में कहीं पर भी नहर बेस्ड स्कीम नहीं है। मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में 26 गांवों में पीने के पानी की कुछ कमी बतायी है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वे 26 गांव कौन कौन से हैं ? क्या मंत्री जी उन गांवों के नाम बताने का कष्ट करेंगे जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ायी जा रही है।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, ये 26 गांव इस प्रकार हैं—खतौली कलां, खतोली खुर्द, खोरमा, जरखी, थम्परोली, नंगल कथा, जैलफ मोहम्मदपुर, डोहर कलां, डोहर खुर्द, गोद बलाव कलां, गोद

बलाब खुर्द, जाडूपुर, भांकरी, मकसुसपुर, पचनोटा, मसनोटा, गोल्वा, अमरपुर, जोगनी, ताजीपुर, छिलरो, घटेशर, रसूलपुर, थाने और लुतेफपुर।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है और स्वयं माना है कि नारनौल के आसपास के 26 गांवों में पीने के पानी की कमी है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अटेली के आसपास के भी कुछ गांवों में ऐसी ही दिक्कत है। क्या मंत्री जी इन हल्कों में कोई कैनाल बेस्ड स्कीम या बोरिंग करके पीने के पानी की सुविधा करने जा रहे हैं और ये कितने गांवों को इस योजना के अंदर ऐसी सुविधा देंगे ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इन 26 गांवों में से 19 गांवों के अंदर तीन योजनाएं बनायी जा रही हैं जिनका ऐस्टीमेट्स वगैरह बन चुका है। ये तीनों ही योजनाएं कैनाल बेस्ड होंगी। इसके अलावा सात गांवों के और ऐस्टीमेट्स तैयार हो रहे हैं। सन् दो हजार तक हम इन सारे गांवों को कवर कर लेंगे। लेकिन शर्मा जी ने जैसे कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में 93 गांव हैं और इन 93 गांवों में से 65 गांव ऐसे हैं जिनमें चालीस लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा आठ गांव ऐसे हैं जहां पर तीस लीटर प्रति व्यक्ति से चालीस लीटर प्रति व्यक्ति तक पानी दिया जा रहा है और 20 गांव ऐसे हैं जहां पर 20 लीटर प्रति व्यक्ति से ऊपर पानी दिया जा रहा है। इस तरह से शर्मा जी यह नहीं कह सकते कि वहां के गांवों में पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है। 20 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम पानी कहीं पर भी नहीं दिया जा रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिजली के फेल हो जाने से या दूसरी किसी दिक्कत की वजह से समस्या हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इनका कुछ एरिया पहाड़ी है हम वहां पर पहाड़ों के अंदर भी गहराई तक जाकर बोरिंग करके देखते हैं लेकिन वहां पर पानी कम ही मिलता है और कुछ समय के बाद वह कम पानी भी खत्म हो जाता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, सन् दो हजार के बाद हम सभी जगह पर पूरा पानी देंगे।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। सर, मेरे चुनाव क्षेत्र नीलोखेड़ी में तीन गांव यानी भुकापूर, बुढेड़ा और पथताना ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है क्या मंत्री जी इन गांवों को पीने के पानी की सुविधा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह क्वैश्चन रैलेवैन्ट नहीं है आप बैठें।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिन गांवों में पीने के पानी की कमी बता रहे हैं उनमें से दुचाना और डोहर कलां के बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर पानी बहुत नीचे है। जब वहां सरकारी अधिकारी बोरिंग लगाने जाते हैं तो वह केवल दो सौ फुट तक बोर करके ही अपनी मशीन उखाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि वहां पानी नहीं है। जबकि उन्हीं गांवों में जब प्राईवेट आदमियों ने मशीन से चार सौ फुट तक बोरिंग करवाया तो वहां पर पानी निकल जाता है। सरकारी अधिकारी नीचे तक बोरिंग नहीं करते और वे पानी की गहराई को नापने में दिक्कत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में हमने बोर करके चार सौ फुट पर पानी निकाला है और अब इन दोनों गांवों को प्राईवेट पार्टीज द्वारा पीने का पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। सरकारी अधिकारी दो घंटे में ही अपनी मशीन उखाड़ कर चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही हमारी समस्या है।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इन सबकी चैक करवा लेंगे। बाकी राणा साहब ने जो सवाल किया था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम सारे हरियाणा में सभी गांवों में पीने का पानी दे रहे हैं। कभी किसी गांव में दिक्कत पड़ जाती है तो वह इसलिए पड़ती है कि या तो नहर में पानी नहीं आता या बिजली फेल हो जाए तो हम पीने का पानी नहीं दे पाते वरना तो जहां पर 100 आदमियों की बस्ती है वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को पीने का पानी मिले।

श्री जय सिंह राणा : मैंने जिन गांवों के नाम बताए हैं उनमें आज भी पानी नहीं है। (इस सवाल का जवाब नहीं आया।)

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधू : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी राणा साहब के सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि सभी गांवों में पीने का पानी दे रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के के गुमथला गढ़ी की तीनों पंचायतों डेरा फतेहसिंह, डेरा मदनपुर में आज भी पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है इनके बारे में बताएं कि वहां कौन कब तक लगवा देंगे और पानी कब तक दे देंगे ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। 26 महीने हो गए हैं इन 26 महीनों में न इन्होंने इस बारे कोई सवाल पूछा, न लिखकर दिया और न कोई कार्यवाही थी इसमें तो इनकी खुद की ही लापरवाही है। अगर इन डेरों में पानी की कमी है तो मेरे को इस बारे में लिखकर नोटिस दें, पूरा काम कर देंगे।

Samples of Insecticides

*776. **Shri Narpender Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the number of samples taken by the Joint Directors, Agriculture and Additional Directors, Agriculture, who have been appointed as Insecticide Inspectors during the year 1997-98 and 1998-99 i.e. upto 30th June, 1998; and

(b) number of samples taken by the Insecticide Inspectors in the presence of the Joint Directors and Additional Directors during the above said period togetherwith the number of samples out of them which has been certified by the Joint Directors and Additional Directors ?

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) संयुक्त कृषि निदेशकों एवं अपर निदेशकों द्वारा स्वयं कोई नमूने नहीं लिये गए थे।

(ख) अन्य कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा भरे गये नमूनों को अपर कृषि निदेशकों/संयुक्त कृषि निदेशकों द्वारा प्रमाणीकरण करने की कोई प्रथा नहीं है।

फिर भी अपर निदेशकों/संयुक्त कृषि निदेशकों की उपस्थिति में कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा भरे गये नमूनों का विवरण इस प्रकार से है :—

वर्ष	भरे गए नमूनों की संख्या
1997-98	133
1998-99 (6/98 तक)	137

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सवाल के भाग-3 में कहा है However, the number of samples drawn by the insecticides Inspectors in the presence of Additional Directors/Joint Directors of Agriculture are as under. उससे पहले ये कहते हैं there is no system of certification by Additional Directors/Joint Directors of Agriculture in respect of samples drawn by other Insecticides Inspectors. मैं जानना चाहता हूं कि जब सैम्पल इनकी प्रैजैन्स में लिए गए तो सर्टिफिकेशन न करने के पीछे क्या कारण हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनमें किसी प्रकार की कोई खामियां न हों, किसानों को किसी तरीके से उनसे नुकसान न हो, उसके लिए हमारे विभाग ने व्यापक तौर पर अभियान चलाया। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कई दफा फील्ड से शिकायतें आती हैं कि हमारे निरीक्षक प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं करते, इसलिए हमने हैड आफिस से ज्वॉइंट डायरैक्टर और ऐडीशनल डायरैक्टर को भेजा ताकि इनकी देखरेख में सैम्पल लिए जा सकें। हालांकि इनकी उपस्थिति में निरीक्षण हुआ था लेकिन उसके सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए इस बारे में मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं। जब हमारे सीनियर आफिसर्ज सैम्पल की देखरेख के लिए जाते हैं और मामलों में जब फर्मों के खिलाफ अदालती कार्यवाही होती है तो यदि ज्वाइंट डायरैक्टर और ऐडीशनल डायरैक्टर ने दस्तखत किए हों तो इनको अदालतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे हमारे विभाग की कार्यवाही रुक जाती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इनके विभाग ने जो सैम्पल लिए थे उनमें क्या कोई कीटनाशक दवाइयां नकली पाई गई हैं यदि पाई गई हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई केस रजिस्टर किए गए हैं ? क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात है कि सरसों की फसल जो पिछली दफा हुई थी उसमें एक जैडीन और एक पैनवका जैल दो किस्म की दवाइयां डाली गई थी जिससे उनकी पत्तियां जल गईं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैप्टन साहब ने नकली दवाईयों के बारे में जिक्र 10.00 बजे किया है मैं उसके बारे में इनको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों निर्सिंग के अन्दर एक आदमी नकली दवाई बेच रहा था, उसके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की है। मैं हर वर्ष लिए गए सैम्पलज् के बारे में इस सदन को बता देता हूं। 1996-97 में विभाग ने 1588 सैम्पलज् लिए और उनका अनालेसिस करवाया तो उनमें से 207 मिक्स ब्रांडिड पाये गये। इनमें से 196 के खिलाफ हमने प्रोसीक्यूशन किया। यह कार्यवाही इंसैक्टिसाईडज एक्ट 1968 के 1971 रूल्ज के तहत की जाती है। जो दवाईयों के सैम्पलज मिक्स ब्रांडिड पाये जाते हैं उनके खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई की जाती है। कुछ सैम्पलज् को सैन्ट्रल लैब में भेजा जाता है जहां पर उनको ठीक करार दे भी दिया जाता है। 1997-98 में 1819 सैम्पल लिये गये। जब इन सब का विश्लेषण करवाया गया तो इनमें से 227 सैम्पलज् मिक्सड ब्रांडिड पाये गये जिनमें से 177 के खिलाफ प्रोसीक्यूशन किया गया, एक के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की गई और चार को वार्निंग दी गई। 1998-99 में अभी तक 336 सैम्पलज् लिये गये हैं जिनमें

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

से 129 का विश्लेषण करवाया गया है इनमें से 18 सैम्पलज़ मिक्स ब्रांडिड पाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूं कि दवाईयों के बारे में हमारा विभाग पूरी तरह से सजग है। पिछले दिनों हमने पूरे विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इस बारे में निर्देश दिए हैं कि किसानों से संबंधित जितनी भी दवाईयां या पैस्टीसाईड हैं उनका गंभीरता के साथ निरीक्षण करवायें।

Outstanding Payment of Sugarcane

*631. @**Shri Sampat Singh**
Shri Krishan Lal } : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the total quantity of sugarcane crushed by each Cooperative Sugar Mill during the year 1997-98 in the State togetherwith the rate at which it was purchased; and

(b) whether the payment to the farmers who supplied sugarcane during the year referred to in part (a) above is outstanding against the Haryana State Cooperative Sugar Mills; if so, the millwise details thereof ?

Minister of Cooperation (Shri Narbir Singh) : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) The total quantity of sugarcane crushed by each Cooperative Sugar Mill during 1997-98 is given here as under :—

S.No.	Name of Mill	Quantity of cane crushed during the season 1997-98
		(in lac qtls.)
1.	Panipat	10.26
2.	Rohtak	20.42
3.	Karnal	28.62
4.	Sonipat	18.00
5.	Shahabad	41.42
6.	Jind	21.51
7.	Palwal	21.76
8.	Meham	21.65
9.	Kaithal	25.20
10.	Bhuna	11.48
	Total	**220.32**

@Put by Shri Sampat Singh

The rate of the cane for different varieties at which the cane was purchased by the Cooperative Sugar Mills is as under :—

Varieties	Rate as per qtl.
COJ-64 & COH-56	Rs. 82
CO-7717, COH-99 & CO-8436	Rs. 80
Other varieties	Rs. 78

(b) The Karnal, Sonipat, Shahabad, Jind, Palwal, Meham and Kaithal Sugar Mills have made the entire payment of the amount referred to in part (a). The outstanding amount as on 13-7-98 in respect of other Mills is as follows :—

Name of Mill	Amount
Panipat	0.65
Rohtak	0.55
Bhuna	2.43
Total	3.63

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो गन्ने की बकाया राशि 3.63 लाख रुपये किसानों को देय है वह बकाया राशि उनको कब तक दे देंगे तथा उस राशि पर क्या 15 प्रतिशत ब्याज देने का भी प्रावधान है क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट का निर्देश है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई है उसमें बकाया राशि 3.63 लाख दिखाई गई है परन्तु आज तक की पोजीशन यह है कि किसानों की बकाया राशि 2.81 लाख रुपये बाकी है। सम्पत सिंह जी ने जो 15 प्रतिशत ब्याज के बारे में बात की है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे गन्ने का रेट फिक्स किया गया 45 रुपये प्रति क्विंटल और बाद में उसको बढ़ा दिया गया 48.90 पैसे प्रति क्विंटल तो इस बढ़ी हुई राशि पर तो हम ब्याज दे सकते हैं परन्तु बकाया राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो बकाया राशि है उसकी पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दी जायेगी।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते ही हैं और मुख्यमंत्री महोदय भी जानते होंगे क्योंकि वे खुद एक किसान हैं कि जब किसान गन्ना बोता है तब वह बाहर से लोन लेकर गन्ना बोता है। चाहे वह थड़ लोन किसी साहूकार से ले या सहकारी समिति से ले या निजी बैंक से ले लेकिन इसे लोन लेना ही पड़ता है और उसके बाद गन्ने की पैदावार करके वह शुगर मिल में अपना गन्ना बेचता है। अगर उस किसान की पेमेंट समय पर नहीं होगी तो उस पर तो ब्याज लगता रहेगा परन्तु सरकार उसको ब्याज दे नहीं रही है जबकि उसकी पेमेंट बकाया है ऐसा क्यों है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पानीपत और रोहतक शुगर मिल्ज की पेमेंट किसानों को जल्दी से जल्दी कर दी जायेगी। परन्तु भूना शुगर मिल जो 1989-90 में शुरू की गई थी और 1992 में बनकर पूरी हुई है वह तभी से घाटे में चल रही है और उसकी किसानों को देय बकाया राशि 2.43 लाख रुपये है। अध्यक्ष महोदय, उसी समय दो शुगर मिल महम और कैथल में भी लगे थे। पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद ये मिल इस साल प्रोफिट में आए हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रस्ट की बात कर रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टैक्स लग रहा है तो मेल पर क्यों नहीं ? (विघ्न) कोर्ट केस भी पब्लिक इंट्रस्ट में नल एंड वाएड कर दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इंट्रस्ट में तो बिल्ज वगैरह में भी अमैंडमैंट की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मिल घाटे में है और वे किसानों को इंट्रस्ट देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। चाहे वह बोनस के रूप में हो अथवा किसी और तरीके से हो, किसी न किसी तरीके से सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो गन्ने का रेट फिक्स करती है लेकिन जो इन्होंने ब्याज देने की बात कही है, मैं इन को बताना चाहूंगा कि ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पानीपत शूगर मिल की तरफ किसानों की पिछले दो सीज़न की कुल कितनी राशि बकाया है ? दूसरा मेरा मुख्य सवाल यह था कि जब शूगर मिलों ने गन्ना लेना शुरू कर दिया था, उस समय सरकार ने गन्ने के रेट्स भी फिक्स नहीं किए थे। बाद में जब रेट्स फिक्स किए गए तो प्रति क्विंटल गन्ने के भाव में 18 रुपए का अंतर आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों को जो पेमैंट की गई है क्या वे 18 रुपए भी उसमें इन्क्ल्यूड किए गए थे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पानीपत शूगर मिल में आज के दिन किसानों की कुल एक लाख रुपए की राशि बकाया है तथा किसानों को कोई भी पेमैंट कटौती कर के नहीं दी जा रही है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पानीपत शूगर मिल में गया था, वे किसानों को कटौती करके कोई पेमैंट नहीं दे रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पानीपत शूगर मिल में आज के दिन किसानों की एक लाख रुपए की राशि ही बकाया है जबकि रिप्लाई में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन के मुताबिक यह राशि 65 लाख रुपए है। कृपया मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ठीक फरमा रहे हैं कि 65 लाख रुपए की राशि दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार बकाया है, लेकिन यह बकाया राशि तो 13-7-98 को थी। आज के दिन जो किसानों की पानीपत शूगर मिल में राशि बकाया है, वह एक लाख रुपए है।

Ottu Bridge

***690. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the bridge on Ottu Lake on Sirsa-Rania road is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) पुल जीर्णवस्था में नहीं है।

(ख) फिर भी, ओटू बांध के जीर्णोद्धार/नया रूप देने वाले प्रस्ताव, पुल जिसका एक भाग है, तकनीकी सलाह के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है, क्योंकि यह एक शताब्दी पुराना ढांचा है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है कि यह पुल शताब्दी पुराना है, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आपने तकनीकी सलाह के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी है, वह किस तारीख को भेजी है और कब से उनके पास यह विचाराधीन है ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि इस पुल की छत बहुत पुरानी होने की वजह से टूट चुकी है तथा टैम्पोरेरी तौर पर इसको चालू रखने के लिए फिर से बनाया गया था ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, कल भी भागी राम जी ने सदन में इस पुल के बारे में बात कही थी। यह ठीक बात है कि यह पुल सौ साल पुराना है और ओटू झील का एक हिस्सा है। जहां तक रिपोर्ट की बात कही गई है, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग की टैक्नीकल कमेटी को रिपोर्ट सिर्फ भेजी ही नहीं गई है, बल्कि 27-5-98 को कमेटी द्वारा मौके का मुआयना भी किया जा चुका है। अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था कि यह पुल बहुत पुराना होने की वजह से टूट चुका था।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए। भाषण न दीजिए।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इनके नोटिस में क्या यह बात है कि उस ओटू झील के पुल की छत कई साल पहले टूट चुकी थी ? लगभग 2-3 महीने तक वहां पूरे एरिया का रास्ता बन्द हो गया था और उस पुल पर दोबारा टैम्पोरेरी तौर पर छत डाली गई थी।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भागीराम जी को बताना चाहता हूं कि यह ओटू पुल कोई अलग नहीं है यह उस स्ट्रैक्चर का हिस्सा है। यह जिस हालत में है इसकी 10 साल पहले, 15 साल पहले और 5 साल पहले भी यही हालत थी। भागीराम जी स्वयं बताते हैं कि वे 4 दफा से इस सदन में आ रहे हैं। यह पुल सिकुड़ा है। इसकी चौड़ाई 12 फुट है। हर तरह से कोई खतरे वाली बात नहीं है। एक तरफ का व्हीकल रुक जाता है क्योंकि दोनों तरफ का व्हीकल इस पुल पर एक साथ नहीं चल सकता। सरकार ने इसको निम्न स्तर की पोजीशन में डिक्लेयर कर दिया है। 27-5-98 को टैक्नीकल कमेटी इसका मुआयना कर चुकी है। इस समय इस पुल में कोई खतरा नहीं है। उस पर ट्रैफिक का बकायदा आना-जाना शुरू है। सिकुड़ा होने की वजह से इस पुल पर एक तरफ ही व्हीकल चलता है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछ रहा था कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि इस ओटू झील के पुल की छत टूट चुकी थी और रास्ता 3-4 महीने तक रास्ता बन्द हो गया था और उस छत को टैम्पोरेरी तौर पर बनाया गया। ये अपने किसी अधिकारी से रिपोर्ट मंगवा कर बताएं।

श्री हर्ष कुमार : इस पुल का स्लैब टूट चुका था। इसकी टैम्परेरी तौर पर मरम्मत हुई थी। अगर इसकी मरम्मत न होती तो आज यह पुल चालू अवस्था में कैसे हो सकता था।

श्री भागी राम : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका महकमा आपको सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है या फिर मुख्यमंत्री जी ने आपको सही रिपोर्ट देने के लिए रोक रखा है। जब मैं पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी था और पी()डब्ल्यू() मिनिस्टर के साथ अटैचड था तो मैंने खुद पुल की छत बनवाई थी।

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी आप स्टेटमैंट न दें।

श्री भागीराम : जब से हाउस चल रहा है इनका कोई भी वजीर सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है और ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी आप सवाल पूछिए।

श्री भागीराम : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं आया।

Providing of Drainage System

***785. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the area between Gochhi and Seria is affected by rainy water every year and farmers of the said area could not sow their crops for the last three years; if so, the steps taken or proposed to be taken to provide proper drainage system for draining out the rainy water of the aforesaid areas ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : जी हां, श्रीमान जी। सेरिया-गोच्छी पम्प हाउस लिंक ड्रेन योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना पर धन की उपलब्धता पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

डा0 वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस काम पर कुल कितना पैसा खर्च होगा और यह स्कीम कब तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि डीघल और गंगटान साथ-साथ लगते गांव हैं उन गांवों में जब भी ज्यादा बरसात होती है तो बरसात का पानी खड़ा होने की समस्या हो जाती है क्या उन गांवों से बरसात का पानी निकालने के बारे में महकमे की तरफ से कोई योजना अंडर कंसीडरेशन है ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1995 की बाढ़ में बेरी हल्का, गोहतक का इलाका और सिवानी का इलाका काफी प्रभावित हुआ और वहां पर बाढ़ के कारण काफी नुक्सान हुआ। उन इलाकों में कहीं ड्रेन क्षतिग्रस्त हुई, कहीं माईनर क्षतिग्रस्त हुई और कहीं पर बाढ़ का पानी खड़ा हो गया जिसके कारण उन इलाकों में काफी नुक्सान हुआ। इसका कारण जहां तक मैं समझा हूं वह यह है कि हमारी सरकार से पहले की जो सरकारें रहीं, शायद वे किसानों के प्रति उदासीन रहीं। जितना भी बिगड़ा हुआ स्ट्रैक्चर था, चाहे वह ड्रेन का था चाहे वह नहरों का था चाहे कहीं पर सीपेज ठीक न की गई हो या चाहे कहीं पर बाढ़ का पानी खड़ा होने की समस्या हो, उसके बारे में पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं

दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछले दो साल के दौरान उन कामों को प्राथमिकता दी। माननीय सदस्य ने इस योजना पर कुल कितना खर्चा करने के प्रावधान के बारे में पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस योजना पर 21.15 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है और 17-4-98 को बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से इस योजना को स्वीकृत करवाया जा चुका है। हम इस योजना के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि यह योजना 3-6-99 तक पूरी हो जाएगी।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर साहब, डीघल और गंगटान गांवों में बरसात का पानी खड़ा होने की बहुत भारी समस्या है उस पानी को निकालने के बारे में क्या इनके महकमे के पास कोई योजना अंडर कंसीडेशन है ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में भी हम सर्वे करवा रहे हैं। जब उसकी अलाइनमेंट निश्चित हो जाएगी तो इस योजना को भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री सिरी कृष्ण हुडा : अध्यक्ष महोदय, रीठाल और धुण्डाल माइनर सरकार ने पिछले साल बनाई उस पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उस माइनर से रीठाल गांव का पानी निकलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस माइनर को बनाने पर जिन अधिकारियों की वजह से नाजायज पैसा लगाया गया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, उस माइनर के बारे में एक कमेटी इन्क्वायरी कर रही है और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो कार्यवाही की जाएगी उसकी रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट माननीय सदस्य हुडा साहब को भिजवा दी जाएगी।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य डा0 वीरेन्द्र पाल जी ने मेन सवाल में पूछा है कि पिछले तीन साल से गोच्छी और सेरिया गांवों के क्षेत्र के किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर सके हैं। मैं आपके माध्यम से इस बारे में यह जानना चाहता हूँ कि जिन दोनों गांव के किसान पिछले तीन साल से फसलों की बुआई नहीं कर सके क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सेरिया गोच्छी पम्प हाउस लिंक ड्रेन योजना को कौन सी ड्रेन के साथ जोड़ा जाएगा ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस ड्रेन के पम्प हाउस का पानी झज्जर सब ब्रांच में डाला जाएगा।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें रीठाल, कबूलपुर और जुलाना भी शामिल हैं या नहीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह सवाल पूछने की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब सवाल पूछने का समय आता है तो ये सवाल भी ठीक तरह से नहीं पूछ पाते। डा0 वीरेन्द्र पाल जी ने पूछा था कि क्या यह तथ्य है कि गोच्छी तथा सेरिया के बीच का एरिया प्रत्येक वर्ष बरसाती पानी से प्रभावित होता है तथा गत तीन वर्षों से उक्त क्षेत्र के किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर सके। यदि हां, तो पूर्वोक्त क्षेत्र से बरसाती पानी के निकासी के लिए उचित निकासी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए क्या पग उठाये गए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इनका सवाल भी सही नहीं था क्योंकि जिसका ये जिक्र कर रहे थे वह माईनर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये सवाल गलत पूछते हैं लेकिन फिर भी हम मेहनत करके सही जवाब देते हैं।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो सवाल पूछा था वह यही था। इस तरह से कई सवाल थे। हो सकता है कि मेरी गलती से या आफिस की गलती से ऐसा हो गया हो। लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि यह 20730 आर०डी० है और इसाइला डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्दर है यह जुलाना गांव की जमीन में है और यह नाला दिवाना गांव की आवपाशी करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यह किसी की गलती से ऐसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप बताएं कि जिस गांव में पिछले तीन चार साल से सिंचाई के लिए एक बून्द पानी न जाये तो उस गांव की क्या हालत होगी ? यह आप भी समझ सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि वर्ष 1995-96 की बाढ़ में जो 20730 आर०डी० नाला डैमेज हो गया था, वह कब तक बना देंगे ?

श्री हर्ष कुमार : मैंने पहले भी बताया था कि वर्ष 1995-96 में जो सरकार थी, उसने इरीगेशन की तरफ सही ध्यान नहीं दिया। उस सरकार की उदासीनता की वजह से ही हमारी नहरें, नाले, ड्रेनें आदि खराब हुए पड़े हैं। अब हमें इन सारे कामों को पूरा करने के लिए धन की कमी आ रही है। हम धीरे-धीरे इनको पूरा कर रहे हैं और उम्मीद है कि दो साल के अन्दर-अन्दर हरियाणा की पूरी टेलों पर पानी पहुंच जायेगा। इसके अलावा जो माईनर हैं, नाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी आदि हैं उन सब की भी गाद निकालने का काम करके उनकी सफाई आदि कर देंगे। इन दो सालों में ही जिस नाले का डा० वीरेन्द्र पाल जी जिक्र कर रहे हैं, वह भी इसमें शामिल है।

Treasury Office, Jind

***718. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that the treasury office and its lock room, Jind are functioning in separate buildings; if so, the time by which the said office is likely to be shifted in one building ?

वित्त मन्त्री (श्री चरण दास) : यह ठीक है कि खजाना कार्यालय व इसका सुदृढ़ कक्ष तथा सिंगल लॉक इस समय अलग-अलग स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। जब लघु सचिवालय के नये खण्ड का निर्माण होगा तो खजाना कार्यालय का अमला तथा सुदृढ़ कक्ष एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जायेंगे।

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, जींद के अंदर ट्रेजरी आफिस कहीं है और इवल लोक रूम कहीं है। जब पब्लिक अपने काम के लिए जाती है तो उस वक्त कंसर्ड आफिसर कभी ट्रेजरी आफिस में बैठता है, कभी इवल लोक रूम में बैठता है जिसके कारण वह पब्लिक को नहीं मिल पाता। अध्यक्ष महोदय, इससे पब्लिक को अपना काम करवाने में बड़ी तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों आफिसिज को एक जगह पर कब तक लायेंगे ? वहां पर मिनी सचिवालय पहले से ही जींद में बना हुआ है।

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही जींद के अंदर ट्रेजरी आफिस और इवल लोक रूम को एक जगह पर लाने का काम करवा देंगे। इस काम के लिए 1546200 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह काम कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चरण दास : अध्यक्ष महोदय, यह काम बहुत जल्दी कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो डेट रामफल जी दे देंगे, उस डेट तक यह काम कर दिया जायेगा।

Distributary from Pai Minor

***703. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to off-take a distributary (Canal) from Pai Minor to village Sohati in District Sonipat; and

(b) if so, the time by which the construction work of the aforesaid distributary is likely to be started/completed ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस उद्देश्य के लिए धन की उपलब्धता के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पाई माइनर से गांव सोहटी तक राजवाह निकालने के लिए धन कब तक उपलब्ध होगा और इस पर कब तक काम शुरू होगा और क्या खर्चा आयेगा ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, सोहटी माइनर आर०डी० 0 से 135500 तक पाई राजवाह आर०डी० 53170 से निकाला जाना है, सरकार ने 30-1-96 को इसके लिए 4.5 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। अध्यक्ष महोदय, नई सोहटी माइनर की लंबाई 4 कि०मी० है और इसका शीर्ष डिसचार्ज 5.45 क्यूसिक है. इसके लिए कोई जमीन अधिग्रहण नहीं की गई है, इसके लिए जमीन लाभान्वित लोगों द्वारा मुफ्त प्रदान की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस राजवाह से सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर, थरोधा, सोहटी और पहलादपुर आदि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, इससे इन गांवों की करीब 1000 एकड़ जमीन सिंचित होगी और वहां के लोगों को लाभ पहुंचेगा। परंतु धन के अभाव के कारण यह योजना अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। अध्यक्ष महोदय, अब इस राजवाह के लिए संशोधित परियोजना अनुमान 18.66 लाख रुपये का बनाया जा चुका है और इसकी स्वीकृति प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना को शुरू करने के लिए धन आर०डी०आई०एफ०-3 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता अप्रैल, 1997 से मार्च, 1999 तक उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, नई सोहटी माईनर का निर्माण कार्य अनुमानित स्वीकृति मिलने के बाद शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन ऑवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Physical Education

***746. Shri Jai Sigh Rana :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the classes from which sanctioned posts of Physical Education has been introduced in schools in the State;

[Shri Jai Singh Rana]

(b) the total number of sanctiond posts of Physical Education Teachers in the State togetherwith the number of posts lying vacant amongst them at present; and

(c) the total number of schools in which Physical Education Teachers have not yet been posted in spite of having the subject of Physical Education therein ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) शारीरिक शिक्षा विषय हरियाणा राज्य के विद्यालयों में श्रेणी नौवीं से शुरू किया गया है।

(ख) शारीरिक मास्टर (डी०पी०ई०) तथा शारीरिक टीचर (पी०टी०आई०) के स्वीकृत पदों की संख्या क्रमश: 628 और 2658 है। इन पदों में से 324 पद शारीरिक मास्टर (डी०पी०ई०) और 215 पद शारीरिक टीचर (पी०टी०आई०) के वर्तमान समय में खाली पड़े हैं।

(ग) उन विद्यालयों की संख्या जिनमें शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में है परन्तु शारीरिक मास्टर (डी०पी०ई०)हशारीरिक टीचर (पी०टी०आई०) नियुक्त नहीं है उनकी संख्या 228 है।

Rural College of Education, Kaithal

***665. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Rural College of Education, Kaithal has been closed; if so, the reasons thereof; and

(b) whether Government intends to re-open the said College ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र द्वारा रूरल शिक्षण महाविद्यालय, कैथल को शैक्षणिक सत्र 1990-91 से असम्बद्ध (डिसएफीलिएट) कर दिया गया था।

(ख) इस महाविद्यालय को पुन: खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

Setting up of 220 K.V. Sub-station at Sonipat

***620. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 220 K.V. Sub-station at Sonipat; if so, the time by which it is likely to start functioning ?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : हां, श्रीमान जी, इस उपकेन्द्र को दिनांक 31-3-1999 तक चालू करने की योजना है।

Construction of Roads by H.S.A.M.B.

*647. **Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Amarpur to Rangarh (Rajasthan Border) and from Nayan to Baba Bhaiya upto Ashram, District Mahindergarh ?

बागवानी तथा विपणन राज्य मन्त्री (श्री जगबीर सिंह मलिक) : वर्तमान में, इन सड़कों का निर्माण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Retirement Age

*742. **Shri Mani Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the retirement age limit of the State Government employees ?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। हरियाणा सरकार द्वारा इस विषय में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Power Projects

*632. **Shri Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Power Projects (Hydro & Thermal) are in the State at present togetherwith the date on which these projects were commissioned;

(b) the generating capacity of each of the project as referred to in part (a) above;

(c) the total MW quantity of electricity being generated in the State at present togetherwith per unit generating cost of electricity;

(d) whether electricity is being purchased by HSEB from any other sources; if so, the names thereof and the per unit rate at which it is being purchased; and

(e) the per unit rate being charged for supplying of electricity to Domestic, Agricultural, Commercial and Industrial Sector, separately ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमान जी, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) तथा (ख) राज्य में वर्तमान बिजली परियोजनाओं एवं उनकी चालू होने की तिथियों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम	क्षमता	चालू होने की तिथि	
			यूनिट-1	यूनिट-2
1.	**पश्चिमी यमुना नहर जलीय विद्युत**			
	1. बिजली घर-ए	2×8 मैगावाट	29-5-86	13-6-86
	2. बिजली घर-बी	2×8 मैगावाट	15-5-87	1-6-87
	3. बिजली घर-सी	2×8 मैगावाट	27-3-89	18-4-89
		कुल 48 मैगावाट		
2.	**थर्मल पावर स्टेशन, फरीदाबाद**			
	1. यूनिट-1 60 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	55 मैगावाट	22-11-74	
	2. यूनिट-2 60 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	55 मैगावाट	6-3-76	
3.	यूनिट-3 60 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	55 मैगावाट	1-4-83	
	कुल 165 मैगावाट			
3.	**थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत**			
	1. यूनिट-1	110 मैगावाट	1-11-79	
	2. यूनिट-2	110 मैगावाट	27-3-80	
	3. यूनिट-3	110 मैगावाट	1-11-85	
	4. यूनिट-4	110 मैगावाट	11-1-87	
	5. यूनिट-5	210 मैगावाट	28-3-89	
	कुल	**650 मैगावाट**		
	कुल योग	**863 मैगावाट**		

(ग) राज्य में वर्तमान समय में कुल उत्पादित बिजली तथा इन परियोजनाओं पर पैसों में प्रति यूनिट चालू औसतन बिजली उत्पादन लागत निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम	प्रतिदिन औसत बिजली उत्पादन /यूनिट लाखों में	प्रति यूनिट बिजली दर/पैसों में
1.	पश्चिमी यमुना नहर जलीय परियोजना	8-10	77
2.	फरीदाबाद थर्मल परियोजना	20-22	204
3.	पानीपत थर्मल परियोजना	90-95	185

(घ) बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं से निम्नलिखित विवरण के अनुसार बिजली क्रय करता है :—

क्र० सं०	परियोजना	पावर प्लांट का नाम	दर पैसों में प्रति यूनिट
1.	राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम	सिंगरौली/यू०पी०	80
		रिंहद सुपर थर्मल केन्द्र/यू०पी०	163
		अटा गैस पर आधारित विद्युत परियोजना/राजस्थान	114
		औरिया गैस पर आधारित परियोजना/यू०पी०	114
		दादरी गैस/यू०पी०	124
		दादरी थर्मल/यू०पी०	193
		ऊंचाहार/यू०पी०	157
2.	राष्ट्रीय जलीय बिजली विद्युत निगम	सलाल जलीय परियोजना /जम्मू कश्मीर/ऊरी/जम्मू कश्मीर/	55
		बैरासूल जलीय परियोजना/एच०पी०/	220
		टनकपुर जलीय परियोजना/यू०पी०/	37
			138

Malenka Minor

***695. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state the date on which the construction work of the Malenka Minor was started togetherwith the time by which the work of the said minor is likely to be completed ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : मालेनका माइनर का कार्य दिसम्बर 1979 के दौरान आरम्भ किया गया था तथा बुर्जी नं०-42,000 तक का कार्य 4/1987 तक पूरा हो चुका था। आर्थिक तंगी व मुकदमेबाजी के कारण 10/1996 तक कार्य निलम्बित रहा। बुर्जी नं०-82,620 तक मिट्टी का शेष कार्य तथा 7 पुलों के निर्माण का कार्य अप्रैल 1997 के अन्त तक पूरा हो चुका था। शेष कार्य धन की उपलब्धता होने पर पूरा कर लिया जाएगा

Construction of a Rivulet

***786. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that a Rivulet in village Baghpur, district Jhajjar at Moga No. 78957 alongwith left side of J.S.B. Canal and parallel to drain No. 8 at the time of its desilting; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct another Rivulet parallel to the said drain ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस मोगे को ड्रेन नं०-8 की बाहरी सीमा के किनारे से बदल कर पुनः निर्माण किया गया है।

Post of Home Science Teacher

***719. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the post of Home Science teacher in Government Girls High School, Kalwa, District Jind, is lying vacant; if so, the time by which the said post is likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, कालवा जिला जीन्द में गृह विज्ञान अध्यापिका का कोई पद उपलब्ध नहीं है और इसलिये इस पद को भरने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Recruitment of Police Constables

***788. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Home be pleased to state whether any recruitment in Police Department has been made during the period from 1st April, 1996 to date; if so, the category-wise names and addresses of the persons so recruited ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : 1-4-1996 से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई सिवाय 69 सिपाही अनुग्रह पूर्वक नीति के अन्तर्गत तथा 12 सिपाही न्यायालय के आदेशानुसार भर्ती किये गये। अनुग्रह पूर्वक नीति के अन्तर्गत भर्ती किये गये 69 सिपाहियों व न्यायालय के आदेशानुसार 12 सिपाहियों का विवरण सदन के पटल पर रख रखा है।

दिनांक 1-4-1996 से अब तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान नीति के अन्तर्गत भर्ती किये गये 69 उम्मीदवारों की सूची

क्र० सं०	उम्मीदवार का नाम व पिता का नाम	वर्ग	यूनिट	पता
1	2	3	4	5
1.	वीर सिंह पुत्र स्व० श्री फतेह सिंह	सामान्य	सोनीपत	गांव गढ़ी खेवा, जिला पानीपत।
2.	गीता देवी पुत्री स्व० श्री रणबीर सिंह	सामान्य	सोनीपत	गांव नारनौंद, जिला हिसार।
3.	प्रमिला देवी पत्नी स्व० श्री धर्मवीर	सामान्य	सोनीपत	गांव मकरौली कलां, जिला रोहतक।
4.	बीरमति पत्नी स्व०श्री सतपाल	सामान्य	सोनीपत	गांव काकरोई, जिला सोनीपत।
5.	चान्दकौर पत्नी स्व० श्री कृष्ण चन्द	सामान्य	पानीपत	गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत।
6.	निर्मला देवी पत्नी स्व० श्री बलबीर सिंह	सामान्य	पानीपत	गांव भुंडलाना, जिला सोनीपत।
7.	गायत्री देवी पत्नी स्व० श्री विनोद कुमार	सामान्य	पानीपत	गांव बढ़ाना, जिला सोनीपत।
8.	सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० श्री धर्म सिंह	सामान्य	पानीपत	गांव मल्लाह माजरा, जिला सोनीपत।
9.	नवीन कुमार पुत्र स्व० श्री राम कुमार	सामान्य	पानीपत	मकान नं० 194-आर, भगत नगर, पानीपत।
10.	उर्मिला देवी पत्नी स्व० श्री जयप्रकाश	सामान्य	पानीपत	गांव कुलासी, जिला झज्जर।
11.	हवा कौर पुत्री स्व० श्री अशोक कुमार	सामान्य	रोहतक	गांव गिवाना, जिला सोनीपत।
12.	विद्यावती पत्नी स्व० श्री सतबीर सिंह	सामान्य	रोहतक	गांव राजलु गढ़ी जिला सोनीपत।
13.	तेज सिंह पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र सिंह	सामान्य	चतुर्थ वाहिनी	गांव धुसकानी, जिला रोहतक।
14.	विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री धर्म सिंह	सामान्य	अम्बाला	गांव नसीरपुर, जिला सोनीपत।
15.	कृष्ण चन्द पुत्र स्व० श्री रणधीर सिंह	सामान्य	द्वितीय वाहिनी	गांव निजामपुर, जिला सोनीपत।

1	2	3	4	5
16.	सुभाष चन्द पुत्र श्री साधू राम	सामान्य	यमुनानगर	गांव ज्योतिसर, जिला कुरूक्षेत्र।
17.	करण सिंह सपुत्र स्व० श्री सुखबीर सिंह	सामान्य वर्ग	अम्बाला	गांव पिन्जौर जिला पंचकूला।
18.	कृष्ण सिंह सपुत्र स्व० श्री सरण सिंह	—यथोपरि—	गुड़गांव	गांव अखलपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
19.	संजय कुमार सपुत्र स्व० श्री वेद प्रकाश	—यथोपरि—	अम्बाला	गांव फौगट संजरवास, जिला भिवानी।
20.	संजय कुमार सपुत्र स्व० श्री रोहताश सिंह	—यथोपरि—	रिवाड़ी	गांव जोराशी, जिला, गुड़गांव।
21.	विनोद कुमार सपुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	गांव बरोना, जिला, सोनीपत।
22.	संजीव कुमार सपुत्र स्व० श्री नसीब सिंह	—यथोपरि—	कुरूक्षेत्र	गांव हवतपुर, जिला यमुनानगर।
23.	हेमराज सपुत्र स्व० श्री ब्रह्म सिंह	—यथोपरि—	गुड़गांव	गांव काकरी, जिला फरीदाबाद।
24.	अजय कुमार सपुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश	—यथोपरि—	जी()आर()पी()	मकान नं() 126÷27 जवाहर नगर, सोनीपत।
25.	प्रदीप कुमार सपुत्र स्व० श्री छत्तर सिंह	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	गांव बड़ौदा, जिला सोनीपत।
26.	अनिल कुमार सपुत्र स्व० श्री बलवान सिंह	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	गांव मलिक कालोनी गोहाना रोड़, सोनीपत।
27.	विरेन्द्र सिंह सपुत्र स्व० श्री हुक्म सिंह	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	गांव सपेरा, जिला, सोनीपत।
28.	विजय पाल सपुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	गांव हसनपुर, जिला गुड़गांव।
29.	सुनीता रानी सपुत्री स्व० श्री राज कुमार	—यथोपरि—	सिरसा	गांव बेनाल, जिला हिसार।
30.	अशोक कुमार सपुत्र स्व० श्री रघबीर सिंह	—यथोपरि—	हिसार	गांव भैरखेड़ी, जिला रोहतक।

1	2	3	4	5
31.	हरदीप सिंह सपुत्र स्व० श्री राम कुमार	सामान्य वर्ग	हिसार	गांव कथूरा, जिला सोनीपत।
32.	विरेन्द्र सिंह सपुत्र स्व० श्री दलबीर सिंह	—यथोपरि—	जीन्द	गांव पिलाना, जिला रोहतक।
33.	सज्जन कुमार सपुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द्र	—यथोपरि—	कैथल	गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर।
34.	रजनीश कुमार सपुत्र स्व० श्री रणबीर सिंह	—यथोपरि—	जी०आर०पी०	गांव झिन्नसाली, जिला सोनीपत।
35.	देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री रत्न सिंह	सामान्य	प्रथम वाहिनी	गांव सांपली, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)।
36.	नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रणधीर सिंह	सामान्य	गुड़गांव	गांव बुटाना, जिला सोनीपत।
37.	प्रवीण कुमार पुत्र स्व० श्री रामफल	सामान्य	फरीदाबाद	गांव बीरधाना, जिला झज्जर।
38.	राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री कर्म चन्द	पिछड़े वर्ग	अम्बाला	मकान नं० 486/5 मोहन नगर, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।
39.	गुरदीप सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह	पिछड़े वर्ग	अम्बाला	गांव कुलवेरी, जिला करनाल।
40.	वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री सूरजभान	पिछड़े वर्ग	गुड़गांव	गांव बुलीट, जिला महेन्द्रगढ़।
41.	दर्शना देवी पत्नी स्व० श्री लाल चन्द	पिछड़े वर्ग	कैथल	गांव धनाना, जिला अम्बाला।
42.	सुशील कुमार पुत्र स्व० श्री सूरत राम	पिछड़े वर्ग	यमुनानगर	मकान नं० 18, सैक्टर-20ए चण्डीगढ़।
43.	संजीव कुमार पुत्र स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह	पिछड़े वर्ग	गुड़गांव	गांव भटसाना नया गांव, जिला रेवाड़ी।
44.	अशोक कुमार पुत्र स्व० श्री नर सिंह	पिछड़े वर्ग	यमुनानगर	गांव डांड, जिला कैथल।

1	2	3	4	5
45.	देव कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह	पिछड़े वर्ग	गुड़गांव	गांव शाहबाजपुर, जिला रेवाड़ी।
46.	नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद	पिछड़े वर्ग	गुड़गांव	गांव खेड़ोली, जिला महेन्द्रगढ़।
47.	सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 श्री महासिंह मन्द	पिछड़े वर्ग	फरीदाबाद	मकान नं० 705 डबुआ, जिला फरीदाबाद।
48.	सभे सिंह पुत्र स्व० श्री रणबीर सिंह	पिछड़े वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव गोकलगढ़, जिला रेवाड़ी।
49.	तेजपाल पुत्र स्व० श्री लिंग राम	पिछड़े वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव नथौरी बहरोर, जिला अलवर (राजस्थान)।
50.	सुरेश कुमार पुत्र स्व० श्री मोहिन्द्र सिंह	पिछड़े वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव कमालपुर, जिला रेवाड़ी।
51.	बलबन्त सिंह पुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह	पिछड़े वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव मऊडेहरगना, जिला नारनौल।
52.	जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री जोरावर सिंह	पिछड़े वर्ग	तृतीय वाहिनी	गांव डिघानी, जिला महेन्द्रगढ़।
53.	सुनील कुमार सुपुत्र स्व० श्री रिछपाल सिंह	पिछड़ा वर्ग	फरीदाबाद	गांव सतलिप, दादरी जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)
54.	संजय कुमार सुपुत्र स्व० श्री राम चन्द्र	—यथोपरि—	—यथोपरि—	गांव अटेली, जिला महेन्द्रगढ़।
55.	सत्यप्रकाश सुपुत्र	—यथोपरि—	—यथोपरि—	मकान नं० 456, एस०जी०एम० नगर, एन०एच० 4 पी०एस०, एन०आई०टी, फरीदाबाद।
56.	मंगू राम सुपुत्र स्व० श्री हरभगवान	—यथोपरि—	—यथोपरि—	गांव जाटूसाना, जिला रेवाड़ी।

1	2	3	4	5
57.	सुरेश कुमार सुपुत्र स्व० श्री देवी दत्त	पिछड़ा वर्ग	करनाल	गांव सराय औरंगाबाद, जिला झज्जर।
58.	महेश कुमार सुपुत्र स्व० श्री गोपी राम	—यथोपरि—	करनाल	गांव अर्धाना जिला करनाल।
59.	जसवन्त सिंह सुपुत्र स्व० श्री हरि सिंह	—यथोपरि—	पंचकुला	मकान नं० 64/26, ब्रह्मनगर, जिला सोनीपत।
60.	राजेश कुमार सुपुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश	अनुसूचित जाति	पानीपत	मकान नं० 201, दौलतपुर मदम, जिला रोहतक।
61.	भरजीत सिंह सुपुत्र स्व० श्री राम मूर्ति	—यथोपरि—	यमुनानगर	गांव गल्लहा, जिला अम्बाला।
62.	राजबीर सिंह सुपुत्र स्व० श्री जगन्न नाथ	—यथोपरि—	चतुर्थ वाहिनी	मकान नं० 31/32, माया पुरी बैंक कालोनी जिला यमुनानगर।
63.	गुरमीत सिंह सुपुत्र स्व० श्री मान सिंह	—यथोपरि—	—यथोपरि—	गांव चकरा हीरा, जिला सिरसा।
64.	चुन्नी लाल सुपुत्र स्व० श्री रणधीर सिंह	—यथोपरि—	गुड़गांव	गांव भागलपुर, जिला रोहतक।
65.	सुनील कुमार सुपुत्र स्व० श्री विजय सिंह	—यथोपरि—	हिसार	गांव गीड़, जिला नारनौल।
66.	सुनील कुमार सुपुत्र स्व० श्री आजाद सिंह	—यथोपरि—	फरीदाबाद	गांव रोट, जिला सोनीपत।
67.	सुशील कुमार सुपुत्र स्व० श्री दयानन्द	—यथोपरि—	—यथोपरि—	मका नं० 176/14, सैनीपुरा, रोहतक।
68.	सतीश कुमार सुपुत्र स्व० श्री सतपाल	—यथोपरि—	अम्बाला	गांव लाडवा, जिला झज्जर।
69.	अत्तर सिंह सुपुत्र स्व० श्री सोहन लाल	—यथोपरि—	जी०आर० पी०	गांव विशोका, जिला रिवाड़ी।

विवरण

12 सिपाहियों की सूची जो 1-4-1996 से आज तक न्यायालय के आदेशानुसार भर्ती किये गये

क्र० संख्या	यूनिट का नाम	उम्मीदवार का नाम	वर्ग	पता
1	2	3	4	5
1.	पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव	श्री सुन्दर पाल पुत्र श्री ओम प्रकाश	पिछड़े वर्ग	गांव मौला हेरा, जिला गुड़गांव।
2.	पुलिस अधीक्षक, नारनौल	श्री दया राम पुत्र श्री मंगतु राम	पिछड़े वर्ग	गांव नियामतपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
3.	पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र	श्री गुरबख्श सिंह पुत्र स्व० श्री करतार सिंह	पिछड़े वर्ग	गांव नलवी, जिला कुरुक्षेत्र।
4.	पुलिस अधीक्षक, रोहतक	श्री राजपाल पुत्र श्री तेलु राम	सामान्य	गांव बैन्शी, जिला रोहतक।
5.	पुलिस अधीक्षक, रोहतक	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश	सामान्य	गांव खिडवाली, जिला रोहतक।
6.	पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बाल किशन	सामान्य	गांव पटौदी, जिला गुड़गांव।
7.	पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव	श्री इन्द्रपाल पुत्र श्री राजपाल	सामान्य	गांव कालीयाका, जिला गुड़गांव।
8.	चतुर्थ वाहिनी मधुबन	श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री दरियाव सिंह	सामान्य	गांव कथूरा, जिला सोनीपत।
9.	पंचम वाहिनी, मधुबन	श्री जगदीश पुत्र श्री चेत राम	सामान्य	गांव डीगल, जिला रोहतक।
10.	पंचम वाहिनी, मधुबन	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भाई राम	सामान्य	गांव डीगल, जिला रोहतक।
11.	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार	श्री शेर सिंह पुत्र श्री भलखान सिंह	पिछड़े वर्ग	गांव निजामपुर, जिला यमुनानगर।
12.	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार	श्री धर्मपाल पुत्र श्री लाल सिंह	सामान्य	गांव सैदापुर, जिला यमुनानगर।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Expenditure incurred on advertisement

48. Shri Sampat Singh : Will the Miniter of State for Public Relations be pleased to state the total expenditure incurred on account of advertisements given in the newspapers/magazines and other media by the State Government during the year 1996-97, 1997-98 and 1998-99 to-date; togetherwth the details of the amount paid to each newspaper, magazine and other media during the aforesaid period ?

Interim Reply.

"ATTAR SINGH SAINI

Minister of State for
Public Relations, Parliamentary
Affairs, Non-conventional
Energy Sources and Power,
Haryana, Chandigarh.
Dated : 22-7-1998.

Subject :—**Unstarred Question No. 48**
Expenditure incurred on Advertisement.

Respected Sir,

The notice of Unstarred Question No. 48 seeking information about expenditure incurred on advertisements during the years 1996-97 and 1998-99 to-date has been received in this office on 15th July, 1998. As the information is to be given for every newspaper, magazine and other media for the above years, it shall require a lot of time to compile the requisite information.

It is, therefore, requested that a period of at least two weeks by way of extension of time may kindly be allowed for answering this question.

Yours faithfully,

Sd/-

(ATTAR SINGH SAINI)
Minister of State for
Public Relations.

Prof. Chhattar Singh Chauhan,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha."

Pabra Canal

49. Shri Sampat Singh : Will the minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) the date on which the new Pabra Link canal/channel was sanctioned;

(b) the present stage of the construction of the afore-said canal togetherwith the time by which it is likely to be completed; and

(c) whether the compensation for the acquisition of land for the construction of the aforesaid canal/channel has been given; if so, the details thereof ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) पावड़ा जोड़ नहर के निर्माण का परियोजना अनुमान दिनांक -02-1-1991 को स्वीकृत किया गया था।

(ख) पुलों को छोड़कर, पावड़ा जोड़ नहर का निर्माण बुर्जी नं०-22,000 से 31,250 (अन्तिम छोर) तक पूरा हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिगृहित भूमि के बारे में दिए गए स्थगन आदेश, जो कि मार्च 1998 में निरस्त किए गए हैं, के कारण शीर्ष छोर का कार्य पहले शुरू नहीं किया जा सका। इस कार्य के लिए निविदाएं पहले ही आमन्त्रित की जा चुकी हैं और मई 1998 में खोली जा चुकी हैं। बुर्जी नं० से 22,000 तक का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा तथा वर्ष 1998 के अन्त तक इसके पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) जिला राजस्व अधिकारी/भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हिसार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 35,12,520 रु० 30 पैसे के निर्णय की घोषणा की जिसमें से 20,05,534 रु० 80 पैसे की राशि का भुगतान भूमि मालिकों को भूमि के मुआवजे के रूप में किया जा चुका है। शेष 15,06,285 रु० 50 पैसे की राशि, जो कि गांव सनियाना तथा चमार खेड़ा से सम्बन्धित है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा है क्योंकि भूमि मालिकों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया है।

Memorandum of Understanding on Yamuna Water

50. Shri Sampat Singh : Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any Memorandum of understanding between Haryana, U.P., Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi regarding allocation of surface flow of Yamuna was signed on 12-5-1994; if so, the details thereof;

(b) whether the aforesaid accord is in the interest of Haryana State; and

(c) if the reply to para (b) above be in negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to reject the said accord ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार)

(क) जी हां, यमुना के सरप्लस फ्लो (सतह बहाव) के बटवारे के बारे में पांच बेसीन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों जो कि :— हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मध्य तत्कालीन केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री की उपस्थिति में 12-5-94 को समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

इस समझौते के अनुसार अन्तिम स्तर पर निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न राज्यों में बटवारा निर्धारित हुआ :—

हरियाणा	:	5.730 बी०सी०एम०
उत्तर-प्रदेश	:	4.032 बी०सी०एम०
राजस्थान	:	1.119 बी०सी०एम०
हिमाचल प्रदेश	:	0.378 बी०सी०एम०
दिल्ली	:	0.724 बी०सी०एम०
कुल	:	11.983 बी०सी०एम०

(ख) जी हां।

(ग) नहीं।

Releasing of Grant to Maharaja Agrasen Medical College

51. Shri Sampat Singh : Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state—

(a) whether any agreement between Haryana Government and Maharaja Agrasen Medical Education & Science for Research Society was signed on June, 1990; if so, the details thereof; and

(b) whether the amount of grant was released to the society as per aforesaid agreement till to-date; if so, the yearwise details thereof ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मड़िया) :

(क) जी हां, हरियाणा सरकार तथा महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं विज्ञान शोध समिति अग्रोहा के बीच 1-6-90 को एक इकरारनामा हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि राज्य सरकार भवन निर्माण/सामग्री (अभावर्ती) खर्च का 50 प्रतिशत व आवर्ती खर्च का 99 प्रतिशत वहन करेगी। सरकार ने 267 एकड़ 14 मरले भूमि 99 साल की लीज पर समिति को एक रुपया वार्षिक नाम मात्र किराये पर दी हुई है।

[श्री विनोद कुमार भड़िया]

(ख) सरकार ने समिति को अनावर्ती आवर्ती अनुदान 31-3-96 तक निम्न प्रकार जारी किया :—

वर्ष	राशि
1990-91	60,71,000.00
1991-92	78,50,000.00
1992-93	1,06,50,000.00
1993-94	1,48,28,000.00
1994-95	1,36,48,000.00
1995-96	74,63,000.00
कुल	6,05,10,000.00

Expenditure Incurred on the Repair/Construction of Roads

52. Dr. Virender Pal Ahlawat : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the constituency-wise expenditure incurred on the construction of new roads and on repair in the state during the period from July 1997 to June, 1998 ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव) : जुलाई, 1997 से जून, 1998 तक की अवधि के दौरान राज्य में निर्वाचन क्षेत्रवार नई सड़कों के निर्माण तथा मुरम्मत पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नई सड़कों के निर्माण पर हुआ खर्च (रुपये लाखों में)	मुरम्मत पर हुआ खर्च (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	कालका	339.30	231.28
2.	साढ़ौरा	39.90	62.96
3.	छछरौली	6.04	44.47
4.	जगाधरी	16.26	31.07
5.	यमुनानगर	—	41.33
6.	मुलाना	36.88	70.01

1	2	3	4
8.	अम्बाला कैंट	1.67	—
9.	अम्बाला सिटी	5.01	45.51
10.	नग्गल	10.38	79.40
11.	इन्द्री	17.30	58.30
12.	नीलोखड़ी	—	56.81
13.	करनाल	3.55	29.06
14.	जुंडला	0.42	71.03
15.	घरौंडा	2.28	41.66
16.	असंध	—	58.66
17.	पानीपत	—	73.18
18.	समालखा	15.40	71.28
19.	नौलथा	10.83	53.96
20.	शाहबाद	5.97	137.31
21.	रादौर	25.15	41.18
22.	थानेसर	5.26	132.82
23.	पेहवा	5.98	130.98
24.	गुहला	—	46.85
25.	कैथल	42.39	109.25
26.	पुन्डरी	6.65	63.02
27.	पाई	0.67	60.46
28.	हसनगढ़	15.01	41.35
29.	किलोई	11.95	73.11
30.	रोहतक	10.14	11.13
31.	मेहम	6.21	129.21
32.	कलानौर	16.59	85.46
33.	बेरी	—	113.55
34.	सालावास	61.43	179.71
35.	झज्जर	108.46	97.11

1	2	3	4
36.	बादली	0.21	57.70
37.	बहादुरगढ़	45.50	61.46
38.	बड़ौदा	6.68	52.70
39.	गोहाना	9.04	76.02
40.	कैथल	0.02	50.89
41.	सोनीपत	0.26	77.29
42.	राई	—	44.94
43.	रोहट	6.44	100.21
44.	कलायत	4.82	23.94
45.	नरवाना	—	58.94
46.	उचाना	—	61.00
47.	राजौंद	—	36.75
48.	जीन्द	12.55	83.19
49.	जुलाना	1.90	81.55
50.	सफीदों	0.43	55.88
51.	फरीदाबाद	—	19.55
52.	मेवला महाराजपुर	5.80	71.26
53.	बल्लभगढ़	0.04	46.98
54.	पलवल	14.71	72.00
55.	हसनपुर	16.16	45.00
56.	हथीन	0.53	57.00
57.	फिं० झिरका	6.66	95.85
58.	नूंह	0.96	58.50
59.	तावडू	5.31	80.76
60.	सोहना	27.87	81.31
61.	पटौदी	6.72	86.30
62.	गुड़गांव	0.22	76.90
63.	बाढड़ा	28.47	26.16

1	2	3	4
64.	दादरी	41.18	66.61
65.	मुंढाल	49.77	82.48
66.	भिवानी	70.04	122.02
67.	तोशाम	18.30	127.52
68.	लोहारू	2.18	80.32
69.	बवानी खेड़ा	46.57	105.99
70.	बरवाला	14.96	103.16
71.	नारनौंद	1.78	119.87
72.	हांसी	0.32	106.88
73.	भट्टू कलां	94.44	12.58
74.	हिसार	27.41	38.25
75.	घिराय	7.59	89.31
76.	टोहाना	61.90	107.54
77.	रतिया	77.61	31.92
78.	फतेहाबाद	83.29	67.98
79.	आदमपुर	65.51	42.06
80.	दड़वा कलां	32.55	43.51
81.	ऐलनाबाद	22.00	73.15
82.	सिरसा	0.15	34.70
83.	रोड़ी	8.10	53.14
84.	डबवाली	—	39.47
85.	लाबल	4.28	161.33
86.	रिवाड़ी	25.43	45.92
87.	जाटूसाना	32.34	98.46
88.	महेन्द्रगढ़	24.24	50.88
89.	अटेली	2.30	65.35
90.	नारनौल	0.60	31.93
	कुल :	**1848.37**	**6418.94**

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों इत्यादि की सूचनाएं

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बस में बम विस्फोट सम्बन्धित हमारी एक कॉलिंग अटैंशन मोशन नं० 8 थी वह आपने यह कह कर रद्द कर दी कि alleged incident took place in Delhi which falls within the jurisdiction of Delhi Administration. अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा रोडवेज की जिस बस में बम दिल्ली में फटा वह बम सफीदों और पानीपत के बीच के ऐरिया में रखा गया था। (विघ्न) दिल्ली प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम हरियाणा में भेजी है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश इस प्रकार के अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप हर चीज़ को डिसअलाउ कर देते हैं। * * * * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह कल ही डिसअलाउ हो चुका था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल जो मामला था वह दूसरा था और आज जो यह मामला है वह दूसरा है क्योंकि यह मामला हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह बम सफीदों और पानीपत के बीच के ऐरिया में उस बस में रखा गया और दिल्ली प्रदेश ने अपनी एक पुलिस टीम इस बात का पता लगाने के लिए हरियाणा में भेजी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस मोशन को अलाउ कर दें। (विघ्न)

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौटाला साहब ने गिनीज़ बुक का जो जिक्र किया है वह चेयर की गरिमा के अनुरूप नहीं है इसलिए उसको रिकार्ड से निकलवाने की कृपा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गिनीज़ बुक का जो जिक्र चौटाला साहब ने किया है उसको रिकार्ड न किया जाए।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए बम विस्फोट के बारे में मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं। हमारी रिलायेबल इन्फर्मेशन है कि दिल्ली में जो बम फटा है वह इस किस्म का बम था कि वह 15 मिनट से ज्यादा का टाईम का बम नहीं हो सकता है। 15 मिनट से ज्यादा उसकी लिमिट ही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15 मिनट में ही वह बम हरियाणा की हद्द में रख दिया गया हो और 15 मिनट में वह बस दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पुलिस इस बारे में इन्कवायरी कर रही है, सारी बात सामने आ जाएगी। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : क्या यह तय हो गया है कि यह टाईम बम ही था ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हां यह टाईम बम ही था। जिस किस्म का यह बम था उसकी डयूरेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : क्या इस बारे में फोरैंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री बंसी लाल : रिपोर्ट अभी कहां आ गई, अभी तो पुलिस इन्वैस्टिगेशन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी रिलायेबल इन्फर्मेशन यही है कि इस किस्म का बम 15 मिनट से ज्यादा डयूरेशन का होता नहीं है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई फाईंडिंग ही नहीं आई है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके पास भी इस बारे में इन्फर्मेशन है। लेकिन समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एक टीम इन्क्वायरी के लिए हरियाणा में भेजी है। वह टीम इस बारे में जानकारी लेने के लिए आई है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अगर आपके पास कोई इन्क्वायरी की रिपोर्ट हो तो आप बता दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह समाचार पत्रों में छपा है कि दिल्ली पुलिस ने इस बात की इन्क्वायरी के लिए अपनी एक टीम भेजी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरी इन्फर्मेशन के मुताबिक जिस किस्म का यह बम था वह 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था, वह 15 मिनट में ही फट जाना था। क्या इनके पास पुलिस से ज्यादा इन्फर्मेशन है या जो पुलिस इन्क्वायरी कर रही है उसने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार को दे दी है ? अध्यक्ष महोदय, ये गलत ढंग से बात को सदन में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, गलत बात को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश ये करते हैं मैंने तो स्पष्ट कहा है कि जिस क्वालिटी का वह बम था वह 15 मिनट में ही फट जाता है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता ने जो रिप्लाई दिया है उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सफीदों से दिल्ली पहुंचने के लिए दो ही रास्ते हैं एक तो वाया पानीपत होकर और दूसरा वाया रोहतक-बहादुरगढ़ होकर।

कृषिपत्नी एवं विपणन राज्य मन्त्री (श्री जगबीर सिंह मलिक) : अध्यक्ष महोदय, तीसरा रास्ता भी है वह वाया गोहाना सोनीपत होता हुआ दिल्ली को जाता है।

वास्तुकला राज्य मन्त्री (श्री राजकुमार सैनी) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह आईडिया कैसे लगाया कि उस बस में सफीदों में ही बम रखा गया था।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से वाया मुरथल दिल्ली जानी वाली बसें दिल्ली बाई पास पर सवारियां छोड़ती हैं वहां से और भी सवारियां चढ़ती हैं। आधा घंटा दिल्ली में चलने के बाद ही कोई भी बस अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे दिल्ली पर पहुंचती है। इस बीच में बस कहीं पर भी नहीं रुकती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि वह बस दिल्ली बस अड्डे पर 11.15 बजे पर पहुंची और बम एक्सप्लोजन 11.35 बजे पर हुआ यानि 20 मिनट बाद वह बम फटा।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने काल अटैंशन मोशन बहबल गांव की पंचायत से संबंधित भूमि को हथियाने के बारे में दिया था जिसको आपने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : राणा जी, जिस तरह से काल अटैंशन मोशन देनी चाहिए थी वह आपने नहीं दी। आपकी काल अटैंशन मोशन रूल्ज के हिसाब से नहीं थी इसलिए इसको रिजैक्ट कर दिया गया है। (विघ्न) राणा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपकी यह मोशन डिस-अलाऊ हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) आप इस बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से पूछ लें कि किस तरह से काल अटैंशन मोशन दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं।

श्री जय सिंह राणा : * * * * * * * * * * * * ।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड नहीं किया जाए।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, जय सिंह राणा जी जिस जमीन से सम्बन्धित बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस सरकार से पहले इनकी सरकार थी तो उस वक्त गोहाना के अन्दर क्या हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। दलाल साहब, आप थोड़ा अपनी बात को दुरुस्त करें क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस का राज था तो राणा साहब इंडीपेंडेन्ट एम०एल०ए० थे और इनका राज नहीं था। (विघ्न)

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, आज भू-माफिया वहां पर जमीनों पर गलत ढंग से कब्जे कर रहा है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। अध्यक्ष महोदय, जमीनों पर कब्जे करना या गलत ढंग से इनकी रजिस्ट्रियां करवाना यह तो कांग्रेस पार्टी के राज का काम है। पिछली बार इनके राज में गुड़गांव में जमीनों पर कब्जे हुए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है कि गुड़गांव जिले के कई गांवों की कई सौ एकड़ जमीनों पर इनके राज में उनके मालिकों को तहसील में बुलाकर आर्मी के जनरल के नाम पर पट्टा करवाया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई कह रहा हूं। हमारी सरकार में कोई भू-माफिया नहीं है और न ही हमारी सरकार इस तरह से किसी अपराधी तत्वों को प्रोत्साहन देती है। अगर माननीय सदस्य राणा साहब के नोटिस में कोई इस तरह की बात थी तो इनको वहां के अधिकारियों से इस बारे में मिलना चाहिए था और अगर वे फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करते तो फिर इनको मंहकमे के मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात कहनी चाहिए थी। (विघ्न) इनके अपने राज में गुड़गांव और फरीदाबाद जिले की जमीनों के फर्जी दस्तावेज मंजूर करवाकर अपनी पार्टी के लोगों और अपने चहेतों को दिए गए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, पीछे क्या हुआ या क्या क्या होता रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब भी इनके राज में कंटीन्यू रहेगा। क्या ये उसको कंटीन्यू रखना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम कंटीन्यू नहीं रखना चाहते हैं। ये अभी पिछली बातों को भूले नहीं हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का प्रैशर पहले गुड़गांव और फरीदाबाद की तरफ था। लीडर ऑफ दी हाउस भी इस बात को मानेंगे कि वहां पर जमीनों के कितने स्कैंडल हुए। हम को भी यह पता है कि कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि दिल्ली का यह प्रैशर अब करनाल, पानीपत और बहादुरगढ़ के हल्कों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। आज इस भू माफिया जिनको प्रोपर्टी डीलर कहना शायद ज्यादा अच्छा शब्द होगा, इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की बातें अब इन इलाकों में शुरू हो गयी हैं। इससे पहले कि यहां पर भी कोई

एक बड़ा स्कैंडल इस तरह का उभरकर आए, अगर माननीय सदस्य इस बारे में अपनी कोई बात यहां पर रखना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है ? वह केवल 100 एकड़ जमीन की ही बात नहीं है बल्कि उन तत्वों को सक्रिय होने से रोकना भी है ताकि कोई भी किसी पंचायत की जमीन पर गलत ढंग से कब्जा न कर सके। अध्यक्ष महोदय, करनाल जैसे क्षेत्र में इस सौ एकड़ जमीन का दस लाख रुपये प्रति एकड़ तो साल का पट्टा ही हो सकता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे तत्वों को किसी भी जमीन को हड़पने से रोके।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं अगर इस किस्म का कोई तत्व है तो ये या तो सदन में बताएं या सदन के बाहर बताएं, हम ऐक्शन लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इसलिए ही हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए हैं। जो करनाल जिले में बड़थल गांव है उसमें 98 एकड़ जमीन पंचायत की है उस जमीन को कुछ लोग ट्रस्ट के नाम से हथियाना चाहते हैं। पंचायत की जमीन इस तरीके से ट्रांसफर होनी चाहिए जिस तरीके से डी०सी० रिपोर्ट करते रहे हैं और डायरैक्टर पंचायत उसको सैंक्शन देते रहे हैं। यह बड़ा सीरियस मामला है। मुख्यमंत्री जी यह सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं है। करनाल और कुरुक्षेत्र में इसका प्रैशर पड़ेगा। इन इलाकों में पंचायतों की जमीनें भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, मेरी यह सबमिशन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पूरे प्रदेश के अंदर करनाल जिले के जिस एक गांव का नाम लिया है हम उसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन इसके साथ ही चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को अपनी पार्टी के राज के दिन याद करने चाहिएं। इनकी सरकार ने गुड़गांव और फरीदाबाद में कोई गांव नहीं छोड़ा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिनको ये सुनाना चाहते हैं वे आज हैं नहीं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इनको बताना चाहूंगा कि जितनी पंचायतों की जमीनें चाहे वह शामलात हो चाहे और किसी किस्म की हो या चाहे ट्रस्ट की हो, अगर किसी जमीन को कोई आदमी हथियाने की कोशिश करता है तो आप मेरे नोटिस में लाएं, उस जमीन को मैं बचाऊंगा।

श्री खुर्शीद अहमद : हम तो यह मामला आपके नोटिस में लाए हैं, इसको आप जरूर बचाएं। This is our request.

श्री बंसी लाल : इनके पर्टिकुलर्ज दे देना हम कार्यवाही कर देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आपके जमाने में जो लूट-खसोट होती थी उसका क्या करें। (शोर एवं विघ्न) आपके राज में तो श्मशान घाट तक की जमीन पर कब्जे कर लिए थे। (शोर एवं विघ्न)

श्री बंसी लाल : ऐसा है कि जो-जो जमीनें आपने बताई हैं उनकी मुझे एक लिस्ट दें और फैक्चुअल पोजीशन भी बता दें। आपकी यह बात तो मैं मानता हूं कि आप जहां का जिक्र कर रहे हो वहां काफी जमीन ऐसी है। ये भी हो सकता है कि वहां उन जमीनों को कोई हड़प करने की कोशिश कर रहा हो। हमारी कोशिश होगी कि उसमें गलत कार्यवाही न होने दें, जिसकी जमीन है उसके पास ही रहे।

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर 1997 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे बी०डी०पी०ओज०, डी०डी०पी०ओज० और ऐ०डी०सीज० की कांफ्रैंस बुलाई थी उसमें सबको हिदायत दी गई थी कि एक गांव पहले लेकर उसकी पैमाइश व निशानदेही करवाएं और फिर आगे की

[श्री कंवल सिंह]
कार्यवाही करें। इस प्रोग्राम के तहत थ्रू-आउट कार्य चल रहा है। गुड़गांव जिले में बहुत वैल्यूएबल जमीन है। वहां मैं दो बार विजिट कर चुका हूं। इनके राज में एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ को पंचायत की जमीन यूं ही सौंप दी गई थी वह जमीन भौंडसी गांव में है। इस प्रकार जहां भी नाजायज कब्जे हैं हम उन्हें छुड़ाएंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कभी टाइम दे दिया करें। फिर आप कहते हैं कि रोला मचाता है। (विघ्न)

श्री खुर्शीद अहमद : सर, आपकी इजाजत से इस हाउस का ध्यान एक खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं। The headline of the news is—"Who can use red lights on cars." मेरे पास 25 की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट 27 की आई है। जब यह लिस्ट बनती है तो रैड लाइट कहां-कहां यूज हो, इस बारे में इस हाउस की ओर ख्याल सबसे बाद में जाता है। इस लिस्ट में पहले तो सारे एम०पीज०, एम०एल०एज० साफ थे। अब जो लिस्ट बाद में आई है उसमें एम०पीज०, एम०एल०एज० के नाम तो करैक्ट कर दिए गए हैं लेकिन विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिए जिस अधिकारी की आपको जरूरत पड़ती है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है जबकि there is an institution of a Secretary in this House.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी एम०एल०ए० या एम०पी० का नाम इस लिस्ट से कभी डिलीट नहीं किया गया। जिस आदमी ने गलती से यह नाम काट दिये थे उन नामों को फिर से दुरूस्त कर दिया गया है। यह गलती परिवहन विभाग के सैक्रेटरी या कमीशनर के कार्यालय से हो गयी थी और जिस कर्मचारी ने यह गलती की थी उसकी कल ही एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली गई है।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसमें सैक्रेटरी विधान सभा और सैशन जज का भी नाम होना चाहिये क्योंकि अगर सैक्रेटरी विधान सभा को कहीं रास्ते में डिटेन कर लिया तो इस सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? उनका नाम भी होना चाहिये।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में इस बारे में सब बातें खुर्शीद अहमद जी से हो गई हैं, इन्होंने अपना नाम दर्ज कराना था सो वह हो गया है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से यह पूछना था कि भूमि माफिया कौन थे ? क्योंकि हम तो इस सदन में नये आये हैं परन्तु चौधरी बीरेन्द्र सिंह इस सदन में मौजूद नहीं हैं। मेरा अपना कोई क्वैश्चन नहीं था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौ० खुर्शीद अहमद जी बता देंगे।

श्री खुर्शीद अहमद : जिन भूमि माफिया को मैं जानता था उनको तो छः महीने की सजा हो गई है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने, चौटाला साहब ने और कुछ मैंबर्ज ने एक काल अटैंशन मोशन दिया था जोकि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में था। हरियाणा के जितने भी कालेज और यूनिवर्सिटीज का गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन था उसको खत्म कर दिया गया है और गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को एक रेजीडैंशियल यूनिवर्सिटी बना दिया है जबकि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको एक साल के अन्दर यू०जी०सी० ने मान्यता प्रदान की है और ग्रान्ट दी

है। इसी पैटर्न पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने अब एक एक्ट बनाया है और वे भी इसे फॉलो कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपका काल अटैंशन मोशन डिस-अलाऊ कर दिया गया था।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने कल यह कहा था कि यह काल अटैंशन मोशन अण्डर कंसीडिरेशन है और डिस-अलाऊ नहीं किया गया है। स्पीकर सर, इस बात का सवाल नहीं है कि अकेले प्रशासनिक मुद्दे ही सामने आयें बल्कि अर्जेंट मैटर भी सामने आ सकते हैं। इससे अर्जेंट मुद्दा और क्या होगा कि जहां प्रोफैशनल कोर्सिज चलते हों और उन कालेजों का यूनिवर्सिटी से एफीलिएशन खत्म कर दिया जाये ? स्पीकर सर, आज प्रोफैशनेलिज्म का जमाना है। आज बी०ए० और एम०ए० करने से बात नहीं बनेगी। आज तो बिजनैस मैनेजमेंट, फार्मेसी और टैक्नीकल कोर्सिज का जमाना है। बिजनैस मैनेजमेंट, फार्मेसी और इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी के कोर्सिज गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में चल रहे थे। इस यूनिवर्सिटी को जापान और फिनलैंड ने एक मॉडल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया था और वहां से एक डैलीगेशन भी यहां पर आया था, आज जापान और फिनलैंड इस यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उस यूनिवर्सिटी का एफीलिएशन अब खत्म कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या इनमें से कोई कोर्स बन्द कर दिए गये हैं ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जितने कालेज जैसे इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज या टैक्नीकल कालेज हैं उनका एफीलिएशन इस यूनिवर्सिटी से खत्म कर दिया है जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने भी इस यूनिवर्सिटी की बिनाह पर ही एक एक्ट बनाया है। अब अगर हर शहर में कालेज और रिजनल सैंटर आप खोलेंगे तो उनके लिए स्टाफ भी अलग-अलग लगाना होगा, अलग-अलग डीन और डायरेक्टर लगाने होंगे जिससे एक्सट्रा एक्सपैंसिज होंगे। एक यूनिवर्सिटी जो कि राईजिंग स्टेज पर है उसकी एफीलिएशन इस बिनाह पर खत्म न की जाये कि वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मेरी मांग यह है कि इस पर डिस्कशन के बाद सरकार रिप्लाई दे कि किन कारणों से इसको डिसएफीलिएट किया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा और भी कई माननीय सदस्यों ने उठाया था और आज भी मैंने अपने जवाब में यह बात कही कि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का कोई किसी तरह का दर्जा हम ने नहीं घटाया है। हमारी सरकार के समय में हम ने इस विश्वविद्यालय के लिए ग्रांट्स दी हैं और ऑनगोईंग वर्कस जो अधूरे पड़े थे, उन को पूरा किया है। हमारे शासनकाल में इस यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मान्यता प्राप्त की है। हम ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। यू०जी०सी० ने भी इसको मान्यता दी है। अध्यक्ष महोदय, हम ने इस विश्वविद्यालय में नये पुराने लगभग 62 टैक्नीकल कोर्सिज शुरू किए हैं। जब हमारी सरकार बनी तब कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से दरख्वास्त की कि कुरूक्षेत्र में जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वह कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में है तथा उसका छात्रावास भी इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि कुरूक्षेत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, इसके साथ और कोई चीज जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी किसी को दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, चाहे महाभारत की लड़ाई में अर्जुन की बात हो अथवा विधान सभा की बात हो, तो उस समय सभी को कुरूक्षेत्र याद आता है। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की चारदीवारी में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की

[श्री राम बिलास शर्मा]
स्थापना हुई थी। लेकिन पिछली सरकार ने किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से इस कुरुक्षेत्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ एफिलिएट कर दिया। पिछले तीन वर्ष के समय में जब इंजीनियरिंग के छात्रों को अपने परिणाम समय पर नहीं प्राप्त होते थे तो उनका कैरियर खराब हो गया। हमारी सरकार आते ही लोगों ने यह मांग की कि इस कॉलेज को इसकी पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम ने इस के लिए एक्सपर्ट्स की एक जांच समिति बिठाई जिस ने अपनी रिपोर्ट दी कि यह कॉलेज चूंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है, इसलिए इसको पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की बात लगातार कुरुक्षेत्र व रोहतक विश्वविद्यालय के कुलपति भी करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव तथा फरीदाबाद के कॉलेज एम०डी०यू० रोहतक के नजदीक पड़ते हैं और हिसार से दूर पड़ते हैं। इस प्रकार से सारी बातों को देखते हुए हम ने गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को टैक्नीकल यूनिवर्सिटी का स्वरूप दिया है। इसमें इलैक्ट्रोनिक्स, एम०बी०ए०, बी०इ० इत्यादि कोर्सिज चल रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को हम ने इस प्रकार से रैजिडैंशियल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है जिस प्रकार से कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जैसे 40-50 विश्वविद्यालय दुनिया भर में समझे जाते हैं। उन के हिसाब से हम ने हरियाणा में एक्सक्लूसिवली इस यूनिवर्सिटी को रैजिडैंशियल स्टेटस दिया है। इस के साथ हम ने कोई भेदभाव नहीं किया है। इस में कोई किसी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं है। जब यह सरकार बनी थी तो उस समय भी यह कहा गया था कि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं अपने माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि इस का अस्तित्व समाप्त होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बल्कि हम इस का और भी ज्यादा विकास करेंगे और इन पिछले दो सालों में हम ने करोड़ों रुपए इस यूनिवर्सिटी के अधूरे कार्यों पर, जो पिछली सरकार छोड़ कर गई थी, खर्च किए हैं। कहीं भी इस विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और इस के साथ कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी को सरकार द्वारा ग्रांट्स भी दी गई हैं। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है तब से इस यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट्स में कटौती की गई है। आप निःसंदेह वर्ष 1995-96, 1997-98 व 1998-99 के ग्रांट्स के आंकड़े देख सकते हैं, हर साल दो-अढ़ाई करोड़ रुपए का कट लगाया जा रहा है। जब यह ऐक्ट इस सदन में पास होने के लिए आया था तब आप भी यहां थे और हम भी यहां थे उस समय मैंने प्वायंट आउट किया था इसमें कई खामियां हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस में जो कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कालेज है उसके बारे में मैंने भी कहा था कि यह इंजीनियरिंग कालेज उससे एफीलिएटिड नहीं होना चाहिए। जो लॉ क्लासिज हैं वे टैक्नीकल क्लासिज में नहीं आती। ये लॉ क्लासिज भी गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ एफीलिएटिड नहीं होनी चाहिएं। उस समय भी हम सभी ने इसका विरोध किया था। हालांकि इसका गलत प्रचार भी किया गया कि सम्पत सिंह ने इस ऐक्ट का विरोध किया जबकि मैंने इसकी अमैण्डमैंट मांगी थी। जहां तक ये दूरी की बात करते हैं, क्या डबवाली कुरुक्षेत्र के नजदीक है ? दूरी की बात नहीं हुआ करती। साईंस यूनिवर्सिटीज ही टैक्नीकल यूनिवर्सिटीज होंगी। वे जो सब्जैक्टस प्रमोट कर सकेंगी वे दूसरी यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकेंगी। अभी रामविलास शर्मा जी ने जिक्र किया कि कितने बढ़िया कोर्सिज हैं जैसे मास कम्यूनिकेशन, इन्वायरमैंट साईंस, एम०एस०सी० एप्लायड मैथेमैटिक, एम०एस०सी० इंडिस्ट्रियल कैमेस्ट्री, बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर साईंस इत्यादि। जिस फोरन यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं वे टैक्नीकल यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली टैक्नीकल यूनिवर्सिटी पूरे हिन्दुस्तान में हिसार में ही बनी थी। हिन्दुस्तान वाले बाहर से एग्जाम्पल ले आते हैं कि ये

रैजिडैन्शियल यूनिवर्सिटी नहीं है इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि that is a residential university but not a technical university. That is for other purposes but not for technical purposes. ये सारे सब्जैक्टस टैक्नीकल परपज के लिए उन लड़कों को पढ़ाए जाते हैं जो अनएम्पलायड रह जाते हैं ताकि उनकी प्रोफैशन मिल सके। आज भी जो कम्प्यूटर जानने वाले लड़के हैं उनको अमरीका वाले बुला रहे हैं। जहां तक प्रिएम्बैल की बात है— that is holy. Every section of the Act can be amended but the preamble of the Act cannot be amended. You may amend the Constitution of India but you cannot amend the preamble of the Constitution of India. So, the preamble of the Act says—

> "to establish and incorporate a teaching-cum-affiliating University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers of technology, pharmacy, environmental studies, non-conventional energy sources and management studies and also to achieve excellence in these and connected fields..."

This was an affiliating University.

स्पीकर साहब, अब यह यूनिवर्सिटी किन कालेजों का एफीलिएशन करेगी जब ये रैजीडैन्शियल बन गई हैं ? रामविलास जी के पास इसका जवाब हो तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आपको याद होगा क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था कि दो-अढ़ाई साल पहले जब मैं और आप विपक्ष में थे तो मैंने और आपने सबसे पहले कहा था कि कुरुक्षेत्र और सोनीपत के इंजीनियरिंग कालेज इस यूनिवर्सिटी के साथ एफीलिएटिड नहीं होने चाहिएं, यह एक गलत बात है। आप यह बताएं कि अगर ये यूनिवर्सिटीज अब रैजीडैन्शियल बन गई हैं तो क्या इससे इसकी टीचिंग या रिसर्च स्टैण्डर्ड में कोई कमी आ जाएगी ? आप और मैं दोनों ही एजूकेशन से सम्बन्धित रहे हैं इसलिए आप बताएं कि जहां तक इस यूनिवर्सिटी के स्टेटस का सम्बन्ध है, जहां तक एकैडमिकल स्टेटस की बात है तो क्या इसके रैजीडैन्शियल बनने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा ?

श्री सम्पत सिंह : जी हां, कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनमें फर्क पड़ेगा जैसे लाइब्रेरी। उसमें रिसर्च करने वालों को वह सुविधा अब नहीं मिल पाएगी जो पहले मिलती थी। इसलिए जो यह कालेजों की डिस-एफीलिएशन हो रही है, यह ठीक नहीं है। सिरसा में जो कालेज है उसके लिए इस बजट में एक पैसा भी नहीं रखा गया है। उस समय हमने यह भी कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में एन्वायरमैंटल साइंस और फोरैस्ट्री के सब्जैक्टस भी पढ़ाए जाने चाहिएं। अगर ये दोनों बातें इसमें और जुड़ जातीं, अगर इसमें इन्वायरमैंट और फारेस्ट्री के सब्जैक्टस और जुड़ जाते तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में गोदारा साहब कुछ बोलेंगे या नहीं।

गृह मंत्री (श्री भजन राम गोदारा) : मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जिस महानुभाव ने यह यूनिवर्सिटी बनाई थी उसको यह देखना चाहिए था कि इसका बाद में रिएक्शन क्या होगा।

श्री सम्पत सिंह : आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है क्या आप यह चाहते हैं कि इस का एफिलिएशन हो ?

श्री मनी राम गोदारा : मैं तो यह चाहता हूं कि कायदे कानून के हिसाब से इसमें सब कुछ हो।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लैरीफाई करना चाहता हूं। गुरू जम्भेश्वर जी की इज्जत मैं इन सबसे ज्यादा करता हूं। इनका गुरू जम्भेश्वर के सिद्धान्तों से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन मैं उनके सारे सिद्धान्तों को मानता हूं।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गुरू जम्भेश्वर जी के हिन्दू फेथ के 20 और 9 यानी 29 सिद्धान्त हैं और उनका हिन्दुस्तान में बहुत आदरणीय स्थान है। उनके नाम से हिसार का विश्वविद्यालय बनाया गया। हमारी सरकार आने के बाद कई लोगों को यह अंदेशा था कि इसका नाम बदला जाएगा या इसके अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा लेकिन हमने उसके उल्ट इस विश्वविद्यालय को, गुरू जम्भेश्वर जी के नाम के इस विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपया लगा करके आगे बढ़ाया है।

श्री सम्पत सिंह : आप उसकी ग्रांट के बारे में भी बता दें।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने कहा कि गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की ग्रांट घटाई गई है। अध्यक्ष महोदय, उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट नहीं घटी। जो पिछले दो साल का दौर था, वह हमारे ऊपर आर्थिक संयम बरतने का दौर था और जितनी भी यूनिवर्सिटीज थीं चाहे वह गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी थी चाहे वह महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी थी और चाहे वह कृषि विश्वविद्यालय था सबकी ग्रांट उस समय कम की गई। सम्पत सिंह जी, आपको स्मरण होगा कि जब यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी उस समय आप भी सदन में थे, चौधरी बंसी लाल जी भी सदन में थे, मैं भी सदन में था और माननीय अध्यक्ष महोदय भी सदन में थे। उस समय जब रीजनल इंजीनियरिंग सैंटर कुरुक्षेत्र को गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ लगाया जा रहा था तो हम सबने उसका विरोध किया था। यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है कि एक क्लास किसी यूनिवर्सिटी में चल रही है उसको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ मिला दिया जाए। अब हमने इस यूनिवर्सिटी को एक रैजीडैंशियल यूनिवर्सिटी की स्वीकृति दे दी है। हमने इस यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स को बंद नहीं किया है। अब भी लगभग 62 टैक्नीकल कोर्स उस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को यू०जी०सी० ने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी करार दिया है। उन्होंने इसको एक मोडल यूनिवर्सिटी बताया है। हमारी उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई दुर्भावना नहीं है, उसके पीछे कोई राजनैतिक कारण नहीं है। इस बारे में कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अनुसार हमने यह काम किया है। इस यूनिवर्सिटी के दर्जे को हमने नहीं घटाया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बात तो गुरू जम्भेश्वर टैक्नीकल यूनिवर्सिटी को एक रैजीडैंशियल यूनिवर्सिटी बना देने की है इसमें इसके नाम से कोई सरोकार नहीं था। यह सारे भारतवर्ष में टोप की यूनिवर्सिटी थी और विशेष रूप से यह उत्तरी भारत में इस प्रकार की सबसे टोप की यूनिवर्सिटी थी। खास करके जब हरियाणा प्रदेश में एक टोप यूनिवर्सिटी हो जिसमें एनीमल हसबैंडरी का भी कोर्स रखा गया हो। उस यूनिवर्सिटी की ग्रान्ट इन्होंने घटाई है। अब ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी की वजह से ऐसा किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद में तो ये शीतकालीन सम्मेलन के नाम पर सम्मेलन करके 10-12 करोड़ रुपया खर्च कर देते है, उस वक्त इनके पास यानी सरकार के पास पैसा कहां से आ गया ? क्या सरकार के पास पैसे की दिक्कत नहीं आई ? इस यूनिवर्सिटी को केन्द्र सरकार की तरफ से भी ग्रान्ट मिली है। दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी सरकार की तरफ से 90-95 प्रतिशत ग्रांट मिलती है। इस यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ रुपया स्वयं फीस आदि के माध्यम से इकट्ठा किया। जो कालेज इस

यूनिवर्सिटी से हटा दिए गए, वह अच्छा नहीं किया क्योंकि जो छात्र इनमें टैक्नीकल एजूकेशन प्राप्त कर रहे थे उनको दिक्कत आई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के बारे में चौटाला साहब व सम्पत सिंह जी की बातों का हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तसल्ली से जवाब दिया है। लेकिन चौटाला साहब ने फरीदाबाद में किसी शीतकालीन सम्मेलन के बारे में कहा कि वहां पर 10-12 करोड़ रुपये खर्च हो गए। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई सम्मेलन हमने वहां पर नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब मण्डियाली में किसानों को गोलियों से मारा गया था, उस समय वहां फरीदाबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें नाच गाने हुए थे।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मण्डियाली में जो कुकर्म हुआ था वह भी इन्हीं का कराया हुआ था। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब मेहम का बाई-इलैक्शन हो रहा था तो इनका होम मिनिस्टर वहां पर तख्त के नीचे छिप गया था, वहां से निकाला था। चौटाला साहब के एक छोटे लड़के को, जो वहां बूथ कैपचरिंग करवा रहा था, गांव के लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद उनके पिता श्री के व दादा श्री के टैलीफोन आए कि किसी तरह उस लड़के को गांव से निकालो। पुलिस को कहा गया कि उसको पुलिस की वर्दी पहना कर निकाल दो। लेकिन कोई पुलिस वाला वर्दी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक सरदारों का बच्चा जो बेचारा नया-नया भर्ती हुआ था उसको धमका कर उसकी वर्दी छीन ली और पहना कर इनके लड़के को वहां से निकाल दिया गया। जब गांवों वालों को इस बात का पता चला तो गांव वालों ने उस लड़के को गंडासों से व दूसरे हथियारों से काट दिया। वह लड़का अपने मां-बाप का अकेला था। दो दिन बाद उसकी बहन की शादी होनी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब बैंसी गांव में यह हो रहा था तो ये उस वक्त क्या कर रहे थे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट में यह बात पूर्ण रूप से साफ हो चुकी है कि उस समय वहां अभय सिंह नहीं था। इसके बाद भी अगर सरकार यह समझती है कि अभय सिंह दोषी है तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कल भी मैंने चुनौती दी थी कि वह ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करें, उसे लागू करें। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय की तो दूसरों पर आरोप लगाने की आदत बन गई है यह बात मैं कल भी कह चुका हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अध्यक्ष महोदय कल आपने भी मुझे कहा था कि मैं इनके बारे में दिया गया 5 जजों का फैसला आपको पढ़कर सुनाऊं। यह फैसला मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन 5 जजों ने यूनानीमसली फैसला दिया है। (विघ्न एवं शोर) कोर्ट ने सूओमोटो कन्टैम्प्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया और 5 जजों की एक बैंच मुकर्रर की। (विघ्न एवं शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस कोर्ट ऑफ कन्टैम्प्ट के बारे में मैं बताता हूं। जैसे एक दिन पहले भी मैंने सदन में इस बारे में बताया था कि मैंने अदालत में क्या बयान दिया, इस जजमैंट में भी लिखा हुआ है—

> "Before parting with the case, I would like to make it clear that no observation made here shall be taken to have been proved for that purpose, other than this case against the present Chief Minister Ch. Devi Lal, Ch. Dharam Singh, D.I.G. (C.I.D.), Shri Raj Singh, Supdt. of Police, Haryana and Shri Banarsi Lal, Inspector."

[श्री बंसी लाल]

और ये सब बातें डिसकस होकर जो जजमैंट आई वह यह है "As a result of the foregoing discussion, the rule stands discharged against both the respondents." अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस मेरे और श्री हंस राज भारद्वाज के खिलाफ जारी किया गया था वह कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं है। As if, there was no case. (Interruptions) as if no case came to the court. अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये लोग क्या-क्या कहेंगे और क्या न कहेंगे, क्योंकि इनकी स्कीम कामयाब नहीं हुई, ये लोग मुझे मार नहीं सके, इस बात का इन्हें दुख है। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जिस जजमैन्ट का जिक्र मुख्यमंत्री महोदय ने किया वह ए०आई०आर० पेज नं०-166 पर है जिस के लास्ट पैरा नं०-170 में लिखा हुआ है कि--

> Both the respondents are unanimously held guilty under section 12 of the Contempt of Court Act, 1970."

यह मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कल आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट का फैसला है, 5 जजों की बैंच का फैसला है। अध्यक्ष महोदय, जो बात मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं वह तो मुख्य मंत्री के वकील ने बाद में कोर्ट में दरखास्त देकर कही थी कि मुझे माफ किया जाये। इसके बाद तीन जजों ने तो इन्हें माफ कर दिया लेकिन श्री एस०एस० संधावालिया और श्री पी०सी० जैन ने उन्हें माफ नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक संगीन जुर्म है और इस जुर्म को माफ नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री को माफ नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, यह हाईकोर्ट का फैसला है मेरा नहीं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में गीता को कोट किया गया और गीता में लिखा हुआ है कि--"क्रोधार्थ भवति सम्मोहत, सम्मोहत स्मृति विभृत, समृति भ्रष्ट बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट प्राणश्ति"। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या होता है यह तो श्री राम विलास जी ही बतायेंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी मुश्किल यह है कि अनपढ़ आदमी से पाला पड़ गया है (हंसी) In the last portion of the judgement, it is written—

> "As a result of foregoing discussion, the rule stands discharged against both the respondents."

जब मामला डिस्चार्ज हो ही गया तो फिर इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि क्या डिस्कस हुआ। अल्टीमेटली वह डिस्चार्ज हो गया तो फिर बाकी बात खत्म हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, शायद इनको यह बात याद नहीं है जब ये घड़ियों की चोरी में पकड़े गए थे और इनको एक हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ था। उस समय इनके पिता श्री ने कहा था कि यह मेरा लड़का ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह लड़का उनका नहीं यह तो मनी राम गोदारा का गोद हो गया, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इनको उल्टा फिर ले लिया और वे बोले कि यह तो मेरा उत्तराधिकारी है। कई बार ये उनके उत्तराधिकारी बने और कई बार यह उनका बेटा होता ही नहीं, इनका हम क्या करें। अध्यक्ष महोदय, इनकी किस-किस चीज का जवाब दें। मैं अभी महम के किस्से के बारे में कह रहा था लेकिन महम के किस्से का इनके पास कोई जवाब नहीं। ये ग्रेवाल रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, ग्रेवाल रिपोर्ट क्या है। अध्यक्ष महोदय, महम

काण्ड में अगर चौटाला साहब के लड़के को उस गरीब सरदार की वर्दी न पहनाई गई होती और उस सरदार के लड़के को इनके लड़के के कपड़े न पहनाए होते तो उस सरदार के लड़के का कत्ल नहीं होता क्योंकि वहां पर उसका कोई दुश्मन नहीं था। अध्यक्ष महोदय, वह लड़का तो इन्होंने मरवा दिया क्योंकि अपने लड़के के लिए उसकी वर्दी छीन ली और पुलिस के बीच में से उसको निकाल कर ले गए। जब लोगों ने वहां पर इनके लड़के के कपड़े पहने हुए उस लड़के को देखा तो उन्होंने सोचा कि इनका लड़का जा रहा है उसके बाद लोगों ने आव देखा न ताव उसको काट डाला। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कन्टैम्प्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने उस जज के खिलाफ बयान दिया था, सी०जे०एम० के खिलाफ बयान देने पर मेरे खिलाफ कन्टैम्प्ट का केस तो बनता ही था। अध्यक्ष महोदय, बिजली को हाथ लगवा कर या दूसरी मंजिल से धक्का दे कर मुझे मारने का इनका प्रोग्राम था और मेरे पास अपनी जान बचाने का कोई और चारा नहीं था, जान तो बचानी ही थी। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि महम में क्या हुआ। (विघ्न) इन्होंने जो इतने कुंए खोद रखे हैं, उनका क्या हुआ ?(विघ्न)

वाक-आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करते हुए पांच जजों के फैसले का जिक्र किया। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Now this matter ends. Zero hour is over. Nothing is to be recorded without my permission. मेरी लीडर्ज ऑफ दि पार्टीज से प्रार्थना है कि वे अपनी पार्टी के ऐसे विधायक, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है उनके नाम लिख कर मेरे पास भेज दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमें कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित मामले पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सभी सदस्य एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आऊट करते हैं।

(At this stage, all the members of the Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party, present in the House staged a walk out as a protest against not having been allowed to speak on the matter concerning the contempt of court.)

वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : जो इण्डिपैंडैंट मैम्बर्ज हैं अगर उनको भी बोलना है और अगर वे पहले नहीं बोले हैं तो they may please give the list of the speakers so that I may ask those members to speak. मैंने कल सदन को आश्वासन दिया था कि आज चाहे रात के 9 बज जाएं, कोई भी सदस्य जिसको बोलने का मौका नहीं मिला है उसको आज समय जरूर मिलेगा।

Mr. Speaker : According to the previous practice and in order to save the time of the House, the excess demands over grants for the year 1993-94 on the order paper (Nos. 3, 5, 6, 8, 15, 18, 23 and 25) are deemed to have been read and moved together and a general discussion on the excess demands is permitted. However, the members are requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion while speaking.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2,69,17,967/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Home.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1,37,47,787/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respecct of **Excise & Taxation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 4,34,177/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Finance.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 7,04,52,773/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Buildings & Roads.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 23,78,50,309/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1,71,08,328/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Animal Husbandry.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 7,80,61,212/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Transport.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2,30,79,146/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Loans and Advances.**

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बोलने की बात आ रही है मुझे बोलने का समय पहले नहीं मिला था तो क्या मैं अब बोलूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि जिन मैंबर्ज को पहले बोलने का समय नहीं मिला है उनकी लिस्ट बनाकर मेरे पास भेज दें ताकि उन मैम्बर्ज को बोलने का समय मिल सके।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं मिला था।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठ जाएं। यह जो एक्सैस डिमांड 1993-94 है इस पर कोई डिस्कशन नहीं होती। इसको बिना डिस्कशन के पास कर लेते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, आप उन सदस्यों को ही बोलने का समय देना जिनको अभी तक बोलने का समय ही नहीं मिला हो। अध्यक्ष महोदय, 1993-94 की ऐक्सैस डिमांड को छोड़कर बाकी सब पर इकट्ठी ही डिस्कशन करवा लें।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, 1993-94 की ऐक्सैस डिमान्डज को हम पास कर लेते हैं और बाकी पर बाद में इकट्ठी डिस्कशन कर लेंगे।

Mr. Speaker : Now, I shall put various demands to the Vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2,69,17,967/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Home.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1,37,47,787/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Excise & taxation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 4,34,177/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Finance.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs.7,04,52,773/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Building & Roads.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs.23,78,50,309/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs.1,71,08,328/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Animal Husbandry.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs.7,80,61,212/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Transport.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs.2,30,79,146/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Loans and Advances.**

The motion was carried.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for grants on Budget for the year 1998-99 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands for grants on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion. The notices of cut motions given by Sarvshri Capt. Ajay Singh, Sampat Singh, Ram Pal Majra, Khurshid Ahmed and Ashok Kumar, M.L.As. on Demand No. 2, Sarvshri Randeep Singh, Capt. Ajay Singh, Ram Pal Majra, Sampat Singh, M.L.As. on Demand No. 3, Sarvshri Capt. Ajay Singh, Birender Singh and Khurshid Ahmed, M.L.As. on Demand No. 4, Sarvshri Birender Singh, Capt. Ajay Singh, Sampat Singh, Khurshid Ahmed and Satvinder Singh Rana, M.L.As. on Demand No. 8, Sarvshri Randeep Singh, Khurshid Ahmed, Sampat Singh, Ram Pal Majra and Capt. Ajay Singh, M.L.As. on Demand No. 9, Sarvshri Sampat Singh, Capt. Ajay Singh, Satvinder Singh, Birender Singh and Khurshid Ahmed, M.L.As. on Demand No. 10, Sarvshri Sampat Singh, Capt. Ajay Singh and Khurshid Ahmed, M.L.As. on Demand No. 11, Sarvshri Randeep Singh, KhurshidAhmed, Capt. Ajay Singh and Ram Pal Marja, M.L.As. on Demand No. 13, Sarvshri Khurshid Ahmed, Birender Singh, Sampat Singh, Capt. Ajay Singh and Satvinder Singh, M.L.As. on Demand No. 15, Sarvshri Randeep Singh, Capt. Ajay Singh, Ram Pal Majra and Khurshid Ahmed, M.L.As. on Demand No. 16, Sarvshri Khurshid Ahmed, Sampat Singh, Capt. Ajay Singh, Ram Pal Majra and Randeep Singh, M.L.As. on Demand No. 17, Sarvshri Birender Singh, Khurshid Ahmed, Capt. Ajay Singh, Ashok Kumar and Ram Pal Majra M.L.As. on Demand No. 21, Sarvshri Khurshid Ahmed and Capt. Ajay Singh, M.L.As. on Demand No. 22, Sarvshri Khurshid Ahmed, Capt. Ajay Singh, Ram Pal Majra and Randeep Singh, M.L.As. on Demand No. 23, will also be deemed to have been read and moved.

That a sum not exceeding **Rs. 2,84,62,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 2,88,36,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 1—Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 99,56,89,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 58,64,79,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 2—General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,76,30,73,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 10,00,00.000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 2,53,58,44,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 3—Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 31,14,23,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 66,03,55,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 4—Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs.19,58,84,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs.22,88,18,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 5—Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs.2,75,91,06,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs.2,65,41,92,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 6—Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 3,16,08,18,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 9,33,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 4,32,97,58,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 4,67,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 7—Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,04,85,49,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,53,61,45,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 99,85,03,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 34,73,48,000**/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 8—Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs.7,50,93,02,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs.6,27,55,10,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 9—Education.**

That a sum not exceeding **Rs.3,54,07,70,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,09,77,73,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 2,57,11,47,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 51,63,27,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 10—Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs.31,94,64,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs.19,65,33,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No.11—Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs.34,09,98,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

[Mr. Speaker]
payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs.29,21,79,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No.12—Labour & Employment.**

That a sum not exceeding Rs.1,81,17,15,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,78,36,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 85,11,71,000/- and capital expenditure amount of Rs. 91,64,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 9,26,54,000/- for revenue expenditure and Rs. 91,83,79,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,21,17,000/- and capital expenditure amount of Rs. 3,96,84,47,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 14—Food & Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 2,33,37,38,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,38,78,28,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 5,74,47,00,000/- and capital expenditure amount of Rs. 1,35,00,00,000/- and Rs. 2,47,81,72,000/- transferred from Demand No. 25, already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 15—Irrigation**

That a sum not exceeding Rs. 29,53,18,000/- for revenue expenditure and Rs.14,92,17,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,34,24,000/- and capital expenditure amount of Rs. 4,11,83,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 16—Industries.**

That a sum not exceeding Rs.1,53,66,67,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 98,09,34,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No.17—Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs.51,51,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 48,17,01,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No.18—Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs.5,33,76,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 2,84,07,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No.19—Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 60,00,54,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 22,29,61,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No.20—Forest.**

That a sum not exceeding **Rs. 82,13,54,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 46,32,92,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 21—Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 11,80,10,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 11,15,38,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs.13,43,98,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 3,35,62,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 22—Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,86,45,35,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 29,59,33,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs.2,11,43,66,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 18,95,67,000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 23—Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 95,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 2,88,67,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 53,75,000/-** and capital expenditure amount of **Rs. 1,34,33,000/-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24—Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,47,81,72,000/-** out of **Rs. 6,05,71,90,000/-** already voted on account for capital expenditure be transferred to Demand No. 15 to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 under that Demand & balance amount of **Rs. 3,57,90,18,000/-** already stands voted on account under **Demand No. 25—Loan and Advances by State Government for the year 1998-99.**

Demand No. 2

Capt. Ajay Singh :
Shri Sampat Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Shri Khurshid Ahmed :
Shri Ashok Kumar :

That Demand No. 2 of Rs. 1,61,42,11,000/- on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

[Mr. Speaker]

Demand No. 3

Shri Randeep Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Shri Sampat Singh :

That Demand No. 3 of Rs. 4,47,77,91,000/- on Account of Home be reduced by Rs. 1,00,000/-.

Demand No. 4

Capt. Ajay Singh :
Shri Birender Singh :
Shri Khurshid Ahmed :

That Demand No. 4 of Rs. 97,17,80,000/- on account of Revenue be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 8

Shri Birender Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Sampat Singh :
Shri Khurshid Ahmed :
Shri Satvinder Singh :

That Demand No. 8 of Rs. 4,94,13,45,000/- on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 9

Shri Randeep Singh :
Shri Khurshid Ahmed :
Shri Sampat Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Capt. Ajay Singh :

That Demand No. 9 of Rs. 13,78,48,17,000/- on account of Education be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 10

Shri Sampat Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Satvinder Singh :
Shri Birender Singh :
Shri Khurshid Ahmed :

That Demand No. 10 of Rs. 7,72,75,77,000/- on account of Medical and Public Health be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11

Shri Sampat Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Khurshid Ahmed :

That Demand No. 11 of Rs. 51,59,97,000/- on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 13

Shri Randeep Singh :
Shri Khurshid Ahmed :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ram Pal Majra :

That Demand No. 13 of Rs. 2,69,98,86,000/- on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re/-. 1.

Demand No. 15

Shri Khurshid Ahmed :
Shri Birender Singh :
Shri Sampat Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Satvinder Singh :

That Demand No. 15 of Rs. 15,32,44,38,000/- on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 16

Shri Randeep Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Shri Khurshid Ahmed :

That Demand No. 16 of Rs. 62,91,82,000/- on account of Industries be reduced by Rs. 1,00,000/-.

Demand No. 17

Shri Khurshid Ahmed :
Shri Sampat Singh :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Shri Randeep Singh :

That Demand No. 17 of Rs. 2,51,87,51,000/- on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 21

Shri Birender Singh :
Shri Khurshid Ahmed :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ashok Kumar :
Shri Ram Pal Marja :

That Demand No. 21 of Rs. 1,28,47,31,000/- on account of Community Development be reduced by Re. 1/-.

[Mr. Speaker]

Demand No. 22

Shri Khurshid Ahmed :
Capt. Ajay Singh :

That Demand No. 22 of Rs. 39,75,13,000/- on account of Co-operation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 23

Shri Khurshid Ahmed :
Capt. Ajay Singh :
Shri Ram Pal Majra :
Shri Randeep Singh:

That Demand No. 23 of Rs. 5,46,31,11,000/- on account of Transport be reduced by Re. 1/-.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरी एक सबमिशन है। अभी जो आपने कहा था कि जिन सदस्यों को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है उनको हम डिमांडज पर बुलाएंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सारी डिमांडज तो इकट्ठे पास नहीं होंगी बल्कि एक-एक करके पास होंगी इसलिए जिन मैम्बर्ज के कट मोशंज हैं उनको भी अगर आप हर डिमांड पर एक-एक या दो-दो मिनट का बोलने का समय दे दें तो यह बहुत अच्छा होगा।

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डिमांडज पर बोलने के लिए इजाजत दी। सर, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर आगे भी बनी रहेगी। अगर मैं इरैलेवैन्ट बोलूं तो आप खुद ही मुझे टोक दें बजाए इसके कि दूसरा मैम्बर मुझे कुछ कहे।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं।

श्री सम्पत सिंह : सर, यह तो बहुत थोड़ा समय है। आप मुझे 50 मिनट बोलने के लिए दे दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको केवल 15 मिनट बोलने के लिए दिए जाते हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं डिमांडज के बारे में डिमांडवाइज ही डिसकस करूंगा और उस समय ही मैं डिमांड का नम्बर भी बता दूंगा। सर, सबसे पहले इस बजट की वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई हैं, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, स्टेट इस बात के लिए सीरियस नहीं है कि इसका फाईनेंशियल मैनेजमैन्ट ठीक किया जाए। अगर आप फाईनेंशियल मैनेजमैन्ट ठीक नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद ही स्टेट इतना जबरदस्त दीवालिया हो जाएगा कि इसके पास कर्ज तो क्या ब्याज चुकाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। सर, ऐक्चुअल लायबिलिटीज 31 मार्च, 1997 को 467.78 करोड़ रुपये की थी जबकि अब 31 मार्च, 1998 के लिए जो ऐस्टीमेट्स बने हैं उसमें यह लायबिलिटीज 80527/- करोड़ रुपये की हो जाएंगी यानी कितनी बड़ी लायबिलिटीज हैं लेकिन मुकाबले में असैट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं हैं इसलिए स्पीकर सर, अगर स्टेट इतनी बड़ी लायबिलिटीज झेल रहा है तो फिर स्टेट जीवित कहां रहेगी ? इसी तरह से दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कर्जे की अदायगी हर साल बढ़ती ही जा रही है। आप तो कर्जे की अदायगी ही नहीं दे पाएंगे फिर आप नये कर्जे लेने की बात क्यों कर रहे हैं ? 1995-96 में यह अदायगी 555.73 करोड़ रुपये की थी जबकि आज यह अदायगी

1056.95 करोड़ रुपये की हो गयी है। स्पीकर सर, इसके बावजूद भी कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। लेकिन केवल सेल्ज टैक्स का ही रैवेन्यू 1995-96 में 1055 करोड़ रुपये का था और उसके बाद यह तकरीबन 1700 करोड़ रुपये का हो गया यानी यह रैवेन्यू भी बढ़ गया है और 700 करोड़ रुपये के टैक्सिज लोगों पर लगे हैं फिर ये कैसे कह सकते हैं कि टैक्सिज नहीं लगे हैं ? स्पीकर सर, लेकिन इनके बदले में जनता को सर्विसिज क्या मिली है?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : स्पीकर सर, यह माना कि प्रो० सम्पत सिंह जी तैयारी से बोल रहे हैं परन्तु कल मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि 171 करोड़ रुपये का यह पिछला सारा शोर शराबा है और उसमें सिर्फ जो बढ़ाया है वह इतना है। अध्यक्ष महोदय, प्रो० सम्पत सिंह जी 700 करोड़ रुपये के सेल्ज टैक्स की जो बात कह रहे हैं वह तो सरकार की कार्यकुशलता है। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। जो रैवेन्यू कलैक्शन हुआ, जो चोरी रोकी या जो टैक्स पीछे लगे हुए थे उनको ही हमने रिकवर किया। रेट ऑफ टैक्स नहीं बढ़ा।

श्री सम्पत सिंह : यह जो बीच में जवाब आ रहे हैं इनके बारे में मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि वित्त मंत्री जी जवाब देते समय बता दें कि कितनी रिकवरी की है और बाकी का एरियर कहां से वापस लेंगे ? यह तो आपका उदाहरण है कि अब असैट्स से फालतू लायबिलिटीज हो गई तो आज तो चलो ठीक है कि ये बड़ी-बड़ी स्कीमें देंगे लेकिन कल को कैसे चलेगा ? स्पीकर सर, अब मैं पॉवर पर बोलना चाहता हूं। रामबिलास जी कहेंगे कि पॉवर की तो डिमान्ड ही नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि करीब 210 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट एच०एस०ई०बी० को देने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इससे माड़े और इससे बुरे हाल बिजली बोर्ड के पहले कभी नहीं हुए। बार-बार डींगें मारी गई डेट्स भी दी गई और कहा गया कि बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा देंगे। दलाल साहब को ऐग्रीकल्चर के बारे में बोलना चाहिए था लेकिन बोलते गए बिजली के बारे में। सारे के सारे सदस्य बिजली के ऊपर बोल रहे हैं और ये सभी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने बिजली के मामले में कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो काम मैं करके गया था वही हुआ उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जनरेशन के हैड में हरियाणा प्रदेश की 1975-76 के अंदर हमारी कैपेसिटी 55 मैगावाट थी और वह भी केवल फरीदाबाद में थी, बाकी जगह जो प्लान्ट्स लगे हैं वह आफ्टर 1976 में लगे हैं उसके बाद जो कैपेसिटी बनी, वह 876 मैगावाट थी। यह 55 से 876 मैगावाट की कैपेसिटी तक कौन लेकर आया ? यह 17-18 गुनी बढ़ौत्तरी हुई। इसी तरह से अगर यूनिट्स के हिसाब से देखें तो उस समय 32 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होती थी जबकि अब 336 करोड़ यूनिट बिजली ले रहे हैं तो यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि सारा कुछ उसी टाईम हुआ। दूसरी बात इसके बारे में मुझे यह कहनी है कि जब चौधरी बंसी लाल जी राज छोड़कर गए थे, उस समय 7 लाख कंज्यूमर्ज थे जबकि आज 33 लाख 90 हजार 245 कंज्यूमर्ज हैं। उनकी डिमांड को मीटआउट किसने किया ? अगर आने वाली कोई भी सरकार यह सब काम न करती तो आगे ये कैसे कर देते ? ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन यदि किसी सरकार के समय में घटे हैं तो इनकी सरकार के समय में घटे हैं। पिछले दो सालों के अंदर ट्यूबवैल्ज कनैक्शन घटे हैं। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय 3 लाख 75 हजार 934 ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन थे और अगले साल ये 3 लाख 66 हजार समथिंग रह गए और बाद में ये 3 लाख 64 हजार समथिंग रह गए। कितने ट्यूबवैल्ज घट गये, 12 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज घटे हैं। नये ट्यूबवैल्ज कनैक्शन देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1975-76 में 45 लाख यूनिट डेली बिजली उपलब्ध थी जबकि 1990-91 में 260 लाख यूनिट बिजली डेली उपलब्ध थी और अब एंट बन डे 315 लाख यूनिट बिजली 25-8-90 को थी।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी सम्पत सिंह जी ने ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज के बारे में जिक्र किया है। इस बारे में तो आंकड़ों से ही पता चल जायेगा क्योंकि पिछले ढाई साल में जब से हमारी सरकार आई है, हमने नहरों के पानी को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसलिए जब किसान को नहरों से पानी मिलेगा तो वह ट्यूबवैल्ज को क्यों चलायेगा?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, दलाल साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि 75 हजार ट्यूबवैल्ज कनैक्शन की एप्लीकेशन पैंडिंग क्यों हैं ? (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**) उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसमीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 1974-75 में ट्रांसफार्मर्ज की संख्या 21 हजार थी और आज यह एक लाख से भी ज्यादा है यानी पांच गुणा ट्रांसफार्मर्ज कहां से आ गये हैं ? पहले 46991 कि०मी० बिजली की लाईन थी जो आज 1,65,827 कि०मी० हो गई है तो यह डवल्पमेंट कैसे हुई ? जहां तक सब-स्टेशंज की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, 1974-75 में 220 के०वी० के सब स्टेशन नहीं थे। सब स्टेशन तो 1975-76 के बाद में ही लगाये गये हैं। मुख्यमंत्री महोदय का यह कहना कि सारा कुछ उन्होंने ही किया है यह कोई जवाब नहीं है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : आपके राज में बिजली की प्रोग्रेस कितनी और कहां-कहां हुई, यह हमें बतायें ?

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसको आप पढ़कर देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है ? पानीपत का प्लांट नम्बर 1 और 2 1977 में हमारी सरकार ने ही शुरू किया था। (विघ्न)

श्री सोमवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये इस सदन को बतायें कि जब 1987 में इनकी सरकार आई तो कितने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन पैंडिंग थे और जब इनकी सरकार नहीं रही उस समय में कितने कनैक्शन पैंडिंग थे ?

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चार साल के अन्दर साठ हजार ट्यूबवैल्ज कनैक्शन दिये थे जबकि वर्तमान सरकार ने कुल 12 हजार ट्यूबवैल्ज कनैक्शन ही दिये हैं जोकि टोटल में से भी कुछ घटे हैं इस पर इनका यह कहना कि पावर की उपलब्धि न होने के कारण या नहरों में पानी देने के कारण यह हुआ है, यह कोई जवाब नहीं है। फिर आज के दिन 75 हजार ट्यूबवैल्ज कनैक्शन की एप्लीकेशन पैंडिंग क्यों पड़ी हैं ? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने फरवरी के महीने में जो अपना बजैटरी एस्टिमेट्स दिया था उसमें स्टेट प्लान में जो बजट एस्टिमेट्स था, वह 325 करोड़ और एक्सटर्नल एडिड प्रोजैक्ट्स का 228 करोड़ रुपये का दिया था जोकि वर्तमान बजट में 325 करोड़ रुपये जमा 180 करोड़ रुपये जो कुल 505 करोड़ रुपये हो जाता है। यह बजट एस्टिमेट्स पहले 553 करोड़ रुपये का था जोकि वर्तमान बजट में सरकार ने घटा दिया है। जब इस सरकार ने चार-पांच महीनों में ही बजट को 50-60 करोड़ रुपये घटा दिया तो बाकी का यह सरकार कैसे पूरा करेगी ? मेरा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है। 1997-98 में बिजली बोर्ड का घाटा 313 करोड़ रुपये का था और अब इन्होंने 1998-99 में 485 करोड़ रुपए के घाटे का बजट एस्टिमेट्स दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो लोन लिया गया है, उसकी मूल पेमेंट तो 183 करोड़ रुपए सालाना होगी और इस पर ब्याज की राशि 290 करोड़ रुपए सालाना होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो मूलधन की राशि दे रहे हैं उससे ज्यादा तो इसका ब्याज ही देना पड़ेगा। इसलिए

चाहे सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में कमी हो या इनएफिशिएंसी हो, या बिजली बोर्ड में करप्शन हो, कारण कोई भी हो सकते हैं। There is something wrong in the HSEB. दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने मेरा अनस्टार्ड क्वैश्चन तो पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इनको पढ़कर सुना देता हूं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले से ही चल रहा था, उसका जिक्र तो इन्होंने किया नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले कुछ नहीं चल रहा था। मैं बता भी सकता हूं लेकिन इससे हाऊस का समय बर्बाद होता है। उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल प्लांट की 110 मैगावाट की दोनों यूनिट्स 1977 में चालू की गई थीं और बाद में हमारी सरकार के समय में ही बिजली की जनरेशन भी की गई। उसके बाद पानीपत थर्मल प्लांट में ही 220 मैगावाट की यूनिट हमारे समय में ही पूरी हुई है। (शोर एवं विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, इस में काम किस ने करवाया है ? ये कहते हैं कि 1977 में इनकी सरकार ने इस यूनिट को चालू करवाया लेकिन इस की कमिशनिंग भी हुई होगी, टैस्टिंग भी हुई होगी, वह किसने करवायी ?

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पानीपत में 210 मैगावाट की 5वीं यूनिट रिकार्ड टाईम में तैयार हुई थी तथा उस वक्त हमारी सरकार ने मुलाजिमों को बोनस भी दिया था। इस यूनिट का ओवर-टाईम कार्य करवा कर हमारी सरकार ने ही इसको तैयार करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, 48 मैगावाट की हाईडल यूनिट भी हमारी सरकार के समय में ही पूरी हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ही जो बिजली जनरेट हो रही है, उन में से अधिकतर यूनिट्स तो हमारे समय की ही हैं। हां, चौधरी बंसी लाल जी ने जो बिजली जनरेशन का कार्य अपने समय में किया है, वह 55 मैगावाट से ज्यादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानीपत की छठी यूनिट के बारे में बताना चाहता हूं। The project for the 6th unit (210 MW) was cleared by the Ministry of Environment and the Planning Commission on 7-4-89 and 3-7-89, respectively. The estimated cost was Rs. 238.27 crores. चौधरी बंसी लाल जी ने बताया कि अगर उस वक्त यह प्रोजैक्ट बन जाता तो इतने करोड़ रुपए खर्च होते। The H.S.E.B. had given a letter of intent for Boiler and T.G. set to BHEL on 23-3-89 with an advance payment of Rs. 11.25 crores. Designing was completed and machinery worth Rs. 80 crores from BHEL was received in 1998 and it is lying idle. उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 5 अप्रैल को हमारी सरकार चली गई तथा 30 मार्च, 1991 तक इसमें कार्य चल रहा था। उसके बाद दुर्भाग्य से उस पर कार्य बंद हो गया। आज का भी पता नहीं कि वहां पर काम हो रहा है अथवा नहीं। आज ये कह रहे हैं कि उस पर कार्य कराया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर जो फाउंडेशन तैयार किया गया था, उस में पिछले सालों में पानी भर गया था, चाहे वह फ्लड की वजह से भरा हो या किसी और कारण से। उस पानी को निकालने का कार्य तो ये कर रहे हैं लेकिन और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह नए प्रोजैक्ट्स का भी है और ऑनगोईंग वर्क्स का भी है। मंत्री जी अपने जवाब में बता देंगे कि क्या बजट में इस छठी यूनिट के लिए पैसे का कोई प्रावधान किया गया है ? मैं कहता हूं कि इस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और ये कहते हैं कि इस को अगले साल तक तैयार कर देंगे। जहां तक उसके रैनोवेशन की बात है तो उसकी रैनोवेशन की जाए

[श्री सम्पत सिंह]
ताकि उसकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। उस समय इंजीनियर्स ने इसकी रैनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था, बाद में उसे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया और जब तक उसकी रैनोवेशन की जाएगी तब तक यह कोस्ट बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। बिजली की जनरेशन पिछले 3 सालों में कितनी बढ़ी है, अगर इसका हिसाब ले लें तो इसका यही जवाब था कि 1996-97 में 2700 मिलियन यूनिट जनरेट हुई एवं 1997-98 और 1998-99 में भी वही 2700 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट हुई। इसका मतलब यह हुआ कि थर्मल पावर प्लांट में रैनोवेशन का कोई असर नहीं हुआ। इस पर ये जितना खर्चा कर रहे हैं, वह सब बेकार कर रहे हैं। फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट के बारे में दलाल साहब भी कह रहे थे कि पहले कोई प्रोजैक्ट मंजूर भी होता है, यदि कोई प्रोजैक्ट मंजूर होता है तो फरीदाबाद का थर्मल प्लांट लगाने के लिए हमारे समय में मंजूर हुआ था। यह जो प्रपोजल है, यह है—

Initially the proposal for the gas based power plant of 300 M.W. at Faridabad was sent by the H.S.E.B. to Central Electricity Authority in November, 1990.

उसके बाद उसके बारे में यह डिसाइड किया गया कि उसको स्टेट गवर्नमैंट नहीं बनाएगी बल्कि उसको एन०टी०पी०सी० बनाएगी। एन०टी०पी०सी० ने उसको बढ़ाकर 432 मैगावाट का कर दिया। उस वक्त जो प्राईम मिनिस्टर थे उन्होंने उसका पत्थर रखा था लेकिन डिप्टी स्पीकर सर, it is in open market. उससे हमें जो पावर मिलेगी वह मार्किट रेट पर मिलेगी। मार्किट रेट पर तो आज भी पावर एवेलेबल है। आज भी ले लो, उससे आपको कौन रोकता है ? मार्किट रेट पर जो पावर मिलती है, वह सबसे ज्यादा मंहगी मिलती है। फरीदाबाद का आपका अपना प्लांट नहीं है। इसके अलावा यमुनानगर थर्मल प्लांट की बात करते हैं। यमुनानगर थर्मल प्लांट के लिए नवम्बर 1987 में सरकार ने लैंड एक्वायर करने के बारे में एक्वीजिशन लेने का डिसाईड किया था और 1132 एकड़ लैण्ड एक्वायर की गई वह लैण्ड भी हमारी सरकार ने एक्वायर की थी। उस पर करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया after that physical possession of land acquired by H.S.E.B. was also handed over to NTPC on 1-2-1990. उसके बाद एन०टी०पी०सी० को दे दिया गया। एन०टी०पी०सी० को देने के बाद वे उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आने वाली सरकार काम न करे तो हम क्या कर सकते हैं ? आज की सरकार कह रही है कि हम काम करेंगे लेकिन आज की सरकार कितना काम करेगी। पिछले साल इस सरकार ने 15 लाख रुपए खर्च किए, वह भी नहरों की गाद निकालने और माईनर्ज की सफाई आदि करने पर खर्च कर दिया होगा। इस बार उस प्रोजैक्ट पर 22 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, 210 मैगावाट का प्रोजैक्ट हो, उस पर आप 22 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हैं जबकि इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने हैं।

एक आवाज : वह 110 मैगावाट का प्रोजैक्ट है।

श्री सम्पत सिंह : पहले वह 210 मैगावाट का था, अब उसको 110 मैगावाट का कर दिया होगा। फिर भी उस पर हजारों-करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आप उसके पुराने एस्टीमेट्स को देखें, वह 1744 करोड़ रुपए था। अगर यह सरकार हर साल उस पर 22 करोड़ रुपए खर्च करती रहे तो उसको कम्पलीट होने में 100 साल लग जाएंगे। दलाल साहब ने हिसार थर्मल पावर प्लांट का जिक्र कर दिया कि हिसार में भी थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। मैंने सोचा शायद वहां पर भी वह बन रहा होगा लेकिन

जब बजट स्पीच में देखा तो पता चला कि 1997-98 में उसके लिए 65 लाख रुपए रखे गए थे लेकिन 1998-99 में मिल यानि उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। वह थर्मल पावर प्लांट बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में कुछ पता नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो बिजली की नई जनरेशन आएगी वह कहां से आएगी क्योंकि इन्होंने बजट में नए प्रोजैक्ट के लिए कोई पैसा नहीं रखा है। यदि नए प्रोजैक्ट नहीं बनेंगे तो नई जनरेशन आने की कोई गुंजाइश नहीं है केवल मात्र आप 240 करोड़ रुपए का लोन लेकर राजी हो रहे हैं कि उससे काम चल जाएगा लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है।

बिजली राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : यह मैं आपको बता दूं कि यह जनरेशन कहां से आएगी। वह आप अगले डेढ़ साल में देख लेना तब बिजली फालतू होगी। बिजली कहां से आएगी, उस बारे में मुख्यमंत्री जी ने कल बताया था कि हम कहां-कहां से बिजली की जनरेशन करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : सैनी साहब, अगर आपको याद नहीं है तो आप गोदारा साहब से अपना मैनीफैस्टो पूछ लें। मैं आपके मैनीफैस्टो की कापी कल नहीं लाया था लेकिन आज लेकर आया हूं। उसमें साफ लिखा है कि विदिन 3 मन्थस बिजली की समस्या हल हो जाएगी। जैसे कोई जादू से हल हो जाएगी। हां, हल करने वाला आदमी तो सदन से चला गया।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सदन में बिजली की बात हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे आप यह सम्पत सिंह जी की क्वालीफिकेशन समझ लो या इनका यह हाउस के साथ मजाक समझ लो या इनकी यह हाउस में झूठ बोलने की बात समझ लो। हर चीज को कह देते हैं कि यह पड़ी है। मैं कहता हूं कि दिखा तो दें कि कहां पड़ी है।

श्री सम्पत सिंह : यह मैं आपको मार्किट कमेटी की दुकानों के आवंटन वाली बात के बारे में कापी देता हूं, इसको आप पढ़कर सुना दो।

(इस समय माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह द्वारा माननीय गृहमंत्री को कुछ कागज दिए गए)

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप यह बताएं कि आप कहते हैं कि तीन महीने के अन्दर बिजली देने की बात कही थी वह किसने कही थी ?

श्री सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वह भी बता दूंगा।

श्री मनी राम गोदारा : डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने मुझे मंडियों के बारे में कागज दिया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि नव निर्मित मंडियों में आढ़तियों को उचित दामों पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : आवंशन से नहीं उचित दामों पर आवंटित की जाएंगी। उचित दाम आवंशन थोड़े ही होता है। आप यह बता दें कि उचित दाम क्या होता है ? (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उचित दाम का क्या मतलब होता है। मैं आपको बता देता हूं कि उचित दाम का मतलब होता है जो प्राईस सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : उचित दाम का मतलब होता है रिजनेबल प्राईस। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं या तो उचित दाम हो या आक्शन हो। ओपन आक्शन के विरोध में उचित दाम का मतलब सीधा है कि रिजर्व प्राईस पर जो चीज सरकार उचित दाम पर और जगहों पर देती है उसी प्रकार से उनको दी जाए। (शोर)

श्री अतर सिंह सैनी : रिजर्व प्राईस का मतलब होता है आरक्षित दाम। (शोर)

श्री अशोक कुमार : आप यह बता दें कि उचित दाम क्या होता है ? (शोर)

श्री सम्पत सिंह : आप उचित दाम बताओ क्या होता है। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : उचित दाम का मतलब होता है रिजनेबल प्राईस और रिजर्व प्राईस का मतलब होता है आरक्षित दाम। आज के दिन अगर हम कहीं पर जमीन लेते हैं तो उसकी जो प्राईस आएगी वह रिजर्व प्राईस होगी और उसकी कीमत जो आज के दिन है जिस समय हम उसको अलाट करेंगे उस समय वही कीमत ली जाएगी। हो सकता है 10 साल के बाद कोई दुकान ले या न ले और कोई आढ़ती वहां जाना चाहे या न जाना चाहे तो उस समय क्या पोजिशन होगी और उचित दाम क्या होगा।

श्री सम्पत सिंह : अगर आपने दुकानें आक्शन से देनी थी तो उसका आपने अपने मैनिफैस्टो में क्यों जिक्र किया ? (शोर) मैनिफैस्टो में उसका जिक्र करने से लाइसैंसी को क्या फायदा हुआ ? चलो यह कल का वाद-विवाद था इसलिए वह कल पर चला गया। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझ से यह पूछा था कि आप तीन महीने में बिजली देने की बात कह रहे थे वह किसने कही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने तीन महीने नहीं दो महीने में 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी। मैंने तो एक महीना आपको फालतू बता दिया या इन्होंने जो यह बात अपने चुनाव के मैनिफैस्टो में लिखी हुई है वही बात मैंने आपको कही है। इसके अन्दर लिखा हुआ है हरियाणा विकास पार्टी दो महीने के अन्दर लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि क्या लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है ? अब इनकी सरकार को बने हुए दो साल हो गए हैं अब ये कह रहे हैं कि डेढ़ साल के बाद हम किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दो साल पहले इन्होंने जो 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था वह पूरा नहीं हुआ। इनकी सरकार बने दो साल हो गए और डेढ़ साल के बाद ये 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात अब कर रहे हैं। ये चार साल बाद वह वायदा पूरा करने की बात करते हैं जो आज से दो अढ़ाई साल पहले पूरा होना चाहिए था। मैं यह कागज गोदारा साहब को दे देता हूं। यदि इस कागज में यह बात नहीं है तो मैं अपने शब्द वापिस ले लूंगा। इन्होंने अपने मैनिफैस्टो में यह कहा था कि दो महीने के अन्दर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। दो महीने भी हो लिए, उसके बाद दो साल भी हो लिए और आज ये कह रहे हैं कि डेढ़ साल के बाद 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी हमारे मैनिफैस्टो का जिक्र कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कल मुख्य मंत्री जी ने बिजली से संबंधित सारी जानकारी सदन को दी थी। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार बिजली पैदा करने के लिए प्रयास कर रही है। ये हमारे घोषणा पत्र की बात करते हैं इनको अपने घोषणा पत्र को याद करना चाहिए। (शोर)

Shri Sampat Singh : Sir, I want to know under what rule, you are allowing him. He cannot speak now.

Mr. Deputy Speaker : I have permitted him to speak.

Shri Sampat Singh : But, sir, under what Rule ? Kindly quote that Rule.

Mr. Deputy Speaker : I can allow him to speak. You cannot dictate me.

Shri Sampat Singh : This will be bailing out the Government. This will be shielding the Government.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेश को चुनौती नहीं दे रहे। उनके 12.00 बजे कोई भी सदस्य बीच में प्वायंट आफ आर्डर का नाम लेकर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और प्वायंट आफ आर्डर करने की बजाए दूसरी बातें कहने लग जाते हैं ये ठीक प्वायंट आफ आर्डर नहीं करते। (शोर)

श्री सतपाल सिंह सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, ये सीनियर मोस्ट मैम्बर हैं। इनको इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी मर्यादा में रह कर अपनी बात कहें। दलाल साहब एक मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं, इनको कह लेने दें। इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री सम्पत सिंह : इसका मतलब क्या है कि ये तो सारी मर्यादाएं तोड़ते रहें लेकिन we do not expect such a thing from you, sir.

श्री कर्ण सिंह दलाल : इनके जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्या ये कुछ भी कहते रहेंगे ? इन्होंने बोलते हुए बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि 1987 में भी इनकी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था। उस समय कहा था कि हम सारे कर्जे माफ करेंगे। ये उस समय दुनिया भर के असत्य वायदे करके आये थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ठीक कहा था कि यह हमारा गठजोड़ नहीं है, जुगाड़ है।

श्री मनी राम गोदारा : मैंने ऐसी जुगाड़ वाली बात नहीं कही। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर कोई बात हुई तो इनको कैसे पता चला क्योंकि ये वहां पर थे नहीं ? इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में नोट छापने वाली मशीन का जुगाड़ करने की बात कही थी क्या अब ये वह मशीन लायेंगे ? ये जुगाड़ वाला शब्द कहां से लाए, ये जानते होंगे। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

Mr. Speaker : Sampat Singh ji, please conclude within a minute. आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब मेरे बोलते समय तो टोटल इन्टरप्शन रही है।

श्री मनी राम गोदारा : फतेहाबाद के इलैक्शन के दौरान मैंने एक बात कही थी वह सही है कि संपत सिंह तो पढ़ा लिखा है लेकिन चाकी तो सारे नौवीं फेल हैं। यह बात सही है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज मुझे पढ़े-लिखे का सर्टिफिकेट दिया है, कल दूसरे किसी मेरे और साथी को देंगे, धीरे-धीरे हम सबको दे देंगे। (विघ्न एवं शोर) I am speaking on facts. There is nothing political.

Mr. Speaker : You are requested to conclude within two minutes.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मैनीफैस्टो का जिक्र नहीं करूंगा। इसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, इसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि हमने 1997-98 में 148 करोड़ रुपये खर्च कर दिये और 1998-99 में 458 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, लाईन लोसिज कितने हैं। 1995-96 में 28% थे, 1996-97 में सरकार आते ही 29½% हो गए, 1997-98 में खर्चा बढ़ाने से लाईन लोसिज 32.15% हो गए और 1998-99 में यह 31% हो गए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, please sit down. Now, I would request another member, Shri Satvinder Singh Rana to speak. (Interruptions)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पावर पर गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहा हूं इसलिए मेरी बात इनको पिंच हो रही होगी। उसके लिए आप इनको कहें कि यह सरकार बेल आऊट हो जायेगी। They are being bailed out.

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, बिजली आदि के बारे में जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, तो ये लोग अपनी सरकार के वक्त में कहां गये थे, उस समय इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, जब 1996 में हमारी सरकार आई, उस समय बिजली की बहुत खराब हालत थी। हमारे मुख्यमंत्री जी की डेढ़ साल की मेहनत के बाद हरियाणा में बिजली की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले डेढ़ साल में हम हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में पूरी बिजली दे देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यदि चौ० सम्पत सिंह जी अपने साथ-साथ जो विपक्ष के दूसरे भाई हैं, उनका जिक्र भी करते, उनके कारनामों का जिक्र करते तो ज्यादा अच्छा होता, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे ? (विघ्न एवं शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि क्या यह सिस्टम ठीक हुआ तो इन्होंने कहा, हां हो गया। अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम इतना ठीक हुआ है कि ठीक होने के बाद 28% लाईन लासिज की बजाय 29½% लाईन लोसिज दे रहा है और 31 मार्च, 1998 तक ये लाईन लोसिज 32.15% हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी आयेगा। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, मैं 31 मार्च, 1998 इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बड़ी मेहनत करके इसको पढ़ा है, देखा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ऑफ ट्यूबवैल्ज़ की बात है तो 1990-91 में यह 35% थी और आज यह कैपेसिटी 29% रह गई है। स्पीकर सर, ओनली 29% और ये दे रहे हैं 43%, उसमें 14% तो बिजली की चोरी में जा रहा है और दूसरे स्पीकर सर, किसान को बिजली दे रहे हैं 8 घण्टे। 8 घण्टे के लिए उसे 365 दिन के लिए बुक किया गया। एग्रीकल्चर सैक्टर में 365 दिन में से ⅓ तो किसान को बिजली की आवश्यकता ही नहीं होती और बाकी के दिनों में जब उसको जरूरत होती है तो किसान को ये बिजली देते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय 43% का बन शर्ड 14 होता है और यह भी ⅓ बिजली किसान को मिलती नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker : I would request Shri Sampat Singh to kindly take his seat.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बातों से गवर्नमैंट एक्सपोज हो रही है इसलिए आप मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं देना चाहते हैं, यह हमारे साथ इनजस्टिस है।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी अपनी प्रिडिक्शन है, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। आप खुद देखिए कि आपने कब बोलना शुरू किया था।

श्री सम्पत सिंह : मैं एकदम रैलेवैन्ट बोल रहा हूं इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि मुझे थोड़ा और समय दीजिए ताकि मैं कन्कल्यूड कर सकूं।

श्री अध्यक्ष : अगर अपनी बात को खत्म नहीं करना चाहते तो यह आपकी अपनी मर्जी है मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप एक मिनट में कन्कल्यूड कीजिए।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं पावर के ऊपर अपनी बात कन्कल्यूड कर रहा था। अगर टोटल एक्चुअल लोस को देखा जाए तो यह लोस 60% तक बन जाता है इसलिए मेरी यह मांग है कि बिजली बोर्ड की बर्किंग की हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इन्क्वायरी करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो वायदे किए थे और लोगों को जो झूठी तसल्ली दी जा रही है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसिडी के बारे में भी इन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपये की सबसिडी बिजली पर दे रहे हैं। इस तरह की सबसिडी आपके अपने बजट में 150 करोड़ रुपया कैश और 100 करोड़ रुपये की एडजस्टमैंट की बात है बजट में असत्य आंकड़े तो कम से कम नहीं होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, 250 करोड़ में एडजस्टमैंट का कोई लोजिक नहीं है। 700 करोड़ रुपये में से 400 या 300 करोड़ रुपया सबसिडी का होगा और बाकी एडजस्टमैंट होगी। एडजस्टमैंट का मतलब यह है कि सबसिडी सारी की सारी थैफूट हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अब तो गवर्नमैंट के पास एक्साईज रैवैन्यू काफी आ गया है और 200 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर ट्यूबवैल्ज से भी आने हैं इसलिए क्यों न पंजाब पैट्रन पर इसको माफ कर दिया जाए ? 775 करोड़ के करीब रैवैन्यू सरकार के पास आना है क्यों न उसमें 200 करोड़ रुपये माफ कर दिए जाएं ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाएं।

श्री सतबिन्द्र सिंह राणा (राजौद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 3 जो कि गृह और ला एंड आर्डर से जुड़ी हुई है, से अपनी बात शुरू करता हूं उसके बाद मैं डिमान्ड नं० 8, 9, 10, 12 और 15 पर भी अपने विचार रखूंगा। सरकार मेरी बातों पर ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरकार में आने से पहले बहुत ही लम्बे चौड़े वायदे किए थे। जब से यह सरकार बनी है तब से हरियाणा का नौजवान भटक रहा है और लूट खसोट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वायदा किया था कि हम शराब बंद करेंगे जिसका हम सदैव समर्थन किया था। इन्होंने हरियाणा में शराब बंद की लेकिन पता नहीं किन कारणों से दोबारा से हरियाणा में शराब खोल दी है। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अन्दर कोई लूट-खसोट होती है तो कहा जाता है कि हरियाणा के नौजवान यह सब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सरकार आती है और उनका जो मैनीफैस्टो होता है उसमें ये नौजवानों को कहते हैं कि हम तुम्हें गैस ऐजैन्सी देंगे, पैट्रोल पम्पस देंगे और बसों के परमिट देंगे। इसके साथ-साथ उनको नौकरियां भी देने का वायदा किया जाता है। जब हमारा नौजवान इन सब चीजों से हताश हो जाता है और उनके मां-बाप उनको कहीं पर

[श्री सतबिन्द्र सिंह राणा]

नौकरी न करने की वजह से ताने मारते हैं तो वह क्राईम में इन्वालव्ड हो जाता है। मां-बाप आज पता नहीं किस तरह से अपना पेट काट कर बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और इस एच०वी०पी० और बी०जे०पी० की सरकार ने आते ही सबसे पहले नौकरियों पर बैन लगाया और नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा। आज रोहतक, जींद और सोनीपत में जहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है और न ही वहां पर औरतों और नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं इसलिए वे मजबूर होकर यह काम करते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट पढ़ी उसमें ढिढाना गांव का नाम आया और इन्होंने कहा कि जो चार मुलजिम पकड़े गए वे फलाँ पार्टी के थे। यह क्यों हो रहा है ? आज हम जो नारे देकर नौजवानों को विश्वास देते हैं कि हम आपको पैट्रोल पम्प, गैस एजैन्सियां और बसों के परमिट देंगे लेकिन वे सब तो मंत्री ही ले जाते हैं, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। आज थाने में कोई अपनी दरख्वास्त देने जाता है तो मुन्शी उसको कहता है कि कुछ खर्चा पानी दे दो और जब वह दे देता है तो दूसरी विरोधी पार्टी को पकड़ कर लाता है, उसको भी यही कहा जाता है कि कुछ खर्चा पानी दे दे और तू भी दरख्वास्त दे दे। आज हरियाणा में यह आम प्रथा पड़ गई है। आज प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि पूछो मत। आज कोई भी गलत काम करता है तो उसको राजनैतिक आदमी ही शह देते हैं। इसमें चाहे मैं हूं या कोई भी हो ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में किठाना और नगुरा दो गांव हैं। वहां के कुछ नौजवान ऐसी हरकतें करते थे कि जब पहले शराब बंद थी तो वे नौजवान शराब की स्मगलिंग करते थे और अब शराब खुल गई है तो वे लूट-खसौट करते हैं। वे नौकरी न मिल पाने के कारण अपने परिवार के तानों बानों से तंग आकर ऐसे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव शामदों में एक मर्डर हुआ है। जिन्होंने मर्डर किया वह तो आज बाहर हैं और आई विटनैस के तौर पर आज कहा जा रहा है कि यह आदमी इसमें शामिल नहीं थे बल्कि दूसरे लोग इसमें शामिल थे। उनको पता था कि अगर वे बाहर रह गए तो कोई बात नहीं होगी लेकिन जो सर्विसमैन थे उनको अंदर करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो कल को किसी का भी नाम लेकर अंदर किया जा सकता है, किसी को भी पकड़वाया जा सकता है इसलिए इस बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के राजौन्द में तीन चार दिन के अंदर ही पांच-छः डकैतियां हुई हैं। अभी बीस दिन पहले राजौंद के अंदर ही एक बी०जे०पी० के कार्यकर्ता के घर पर चोरी हुई है। पता नहीं चोरी हुई भी है या नहीं लेकिन वह राजस्थान में गया और वहां से लौटने के बाद पुलिस वालों को 1100 रुपये देकर कहा कि फलां गांव के ओम नाम के आदमी ने चोरी की है। पुलिस वालों ने जब पूछा कि ओम कौन है तो उसने किसी गरीब आदमी का नाम लेकर कहा कि यही ओम है। इसके बाद पुलिस वाले उसको ले आए और उसकी इतनी पिटायी की कि वह गरीब बीस पच्चीस दिन से अपने बिस्तर से नहीं उठ पाया है। अध्यक्ष महोदय, उसको पुलिस वालों ने मुसली लगायी। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ? इसी वजह से वह गरीब आदमी अपने घर में ही पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य भले ही इस बात को मजाक में लें लेकिन ऐसी बातें कही हुई हैं ये तथ्य सही हैं। आज इन चीजों को देखते हुए, बिगड़ती हुई लॉ एंड आर्डर की स्थिति को देखते हुए हरियाणा की स्थिति ऐसी हो गई कि इसने बिहार और यू०पी० को भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो हम बिहार और यू०पी० की ही मिसाल देते थे परन्तु आज हरियाणा के अंदर भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो गयी है कि बच्चे अपने मां-बाप से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इनको बिगाड़ने वाले हम सभी नेता लोग ही हैं क्योंकि हम उनको तरह-तरह के नारे तो दे देते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस की भर्ती हुई है जिसके बारे में यहां पर कई बार बात आयी है कि डेढ़-डेढ़ लाख रुपये देकर पुलिस की नौकरी मिलेगी। दो तारीख से यह पुलिस की भर्ती शुरू हुई

है और शायद यह तीस तारीख तक चलेगी। लाखों नौजवानों ने इसमें भर्ती होने के लिए फार्म भरे हुए हैं उनकी इस भर्ती के लिए दौड़ वगैरह भी हुई है।

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : स्पीकर सर, पहले ये शायद हाउस में नहीं होंगे इसलिए इनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन मैंने लीडर ऑफ दी अपोजीशन के एक सवाल के जवाब में एक बात बड़ी साफ और क्लीयर कही थी कि हमारी यह पुलिस की भर्ती मैरिट के बेसिज पर हो रही है। मैंने उस समय सारे हाउस को यकीन दिलाया था कि आगे भी यह भर्ती मैरिट के बेसिज पर ही होगी। उस समय उन्होंने यह कहा था कि अगर हम यह साबित कर दें या सबूत दे दें कि इसमें गड़बड़ हुई है तो हमने कहा था कि आपका स्वागत है आप सबूत लाइए तो सही। लेकिन वैसे ही खड़े होकर कहना ठीक बात नहीं है। अभी तक तो भर्ती हुई ही नहीं है। जिस दिन कोई ऐफिडैविट लेकर इस बारे में हमारे पास केस लाएगा या कोई सबूत उसके पास होगा तो हम उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे। आप कहते हैं कि हमने सारे लोगों को बिगाड़ दिया। लेकिन इनको हमने नहीं बिगाड़ा बल्कि आपकी पार्टी के राज में ही ये लोग बिगड़े। उस समय नौकरियां कहीं पर 60 हजार रुपये में, कहीं पर 70 हजार रुपये में बिकीं। खैर, मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप हमारे सामने इस बारे में कोई केस तो लाइए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन जो आप लोगों ने नौजवानों को गलत आदत डाल दी है तो आप यह न समझें कि सबकी यही आदत है।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि मैरिट के हिसाब से पुलिस में बच्चों की भर्ती की जाएगी। मैरिट तो इन लोगों के हाथ में होगी क्योंकि जो बीस नम्बर का बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी मैरिट कौन देखेगा ? फिर मैरिट कहां रह जाएगी ?

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : स्पीकर साहब, मैं भी यह बात इसलिए ही कह रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि डेढ़ लाख रुपये ले लिए। मैं यह कह रहा हूं कि जब हम मैरिट की बात करते हैं तो मैरिट उस दिन कही जाएगी जब रेस, कूद दौड़ कराने के बाद मैरिट के आधार पर उसी दिन रिजल्ट निकाल दें लेकिन यह जो 15 नंवर इंटरव्यू के लिए लिखे हैं इनकी मर्जी है कि कैंडीडेट से जो मर्जी पूछें।

श्री मनी राम गोदारा : मेरे ख्याल से सारे मैम्बर्ज को बताना होगा कि 1995 में जो भर्ती हुई थी उस को जब हाईकोर्ट ने रिजैक्ट किया तब हाई कोर्ट ने गाईडलाईज दीं कि इन गाईडलाईज को फौलो करते हुए आगे भर्ती होगी। आप सभी मैम्बर्ज को और जितने भी आदमी सर्विस में हैं, उनको यह पता होगा कि Interview is also a part of the examination for merit. (विघ्न) यह पहली दफा इसलिए हो रहा है कि हाईकोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन और गाईडलाईज दी हुई हैं उन्हीं के आधार पर हम भर्ती कर रहे हैं। (शोर एवं विघ्न) आप ये बताइए कि कौन सी जगह इन्टरव्यू नहीं होते ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : आर्मी में कांस्टेबल का इंटरव्यू नहीं होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे ये बार-बार टोक रहे हैं। मेरा समय तो इसी में समाप्त होता जा रहा है अभी तो मैं अपने हल्के के बारे में भी कुछ नहीं बोला हूं। मैं गोदारा साहब से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मैरिट की बात कह रहे हैं, इंटरव्यू की बात कह रहे हैं तो जिस जिले में इंटरव्यू हो लिए हैं उनकी लिस्ट क्यों नहीं लगी, पहले ये बताइए ? जींद जिले में इंटरव्यू खत्म हो लिए लेकिन वहां लिस्ट अभी तक नहीं लगी है।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैंने बताया है कि इंटरव्यू हो गई, लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने के बाद डाक्टरी मुआयना होगा और उसके पश्चात् उनके चरित्र की वैरीफिकेशन होगी उसके बाद अनाउंस होगा। आपके सामने अनाउंस होगा। आप आना।

श्री अध्यक्ष : सतविन्द्र सिंह जी, आप दो मिनट में कन्कल्यूड करिए।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने तो अपने हल्के की बात भी नहीं कही। (विघ्न)

स्थानीय स्वशासन मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सतविन्द्र सिंह जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिएं। उन्होंने कहा है कि पुलिस भर्ती में एक लाख, डेढ़ लाख तक लिया जा रहा है या लिया गया है अब ये कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है मेरा मतलब यह है कि लिस्ट नहीं लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, ये इस बात की क्लेरिफिकेशन दें।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, भर्ती का जो लम्बा प्रोसेस है उसको कम किया जाये क्योंकि जो नौजवान शहर में भर्ती होने के लिए जाता है तो चार आदमी उसके साथ जाते हैं कि हमारा लड़का भर्ती होगा और इस तरह से रोजाना पांच सौ रुपये तक उनके खर्च हो जाते हैं। इस तरह से जो भर्ती हुई उस पर लोगों ने हजारों रुपया खर्च कर दिया है। (विघ्न) (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, भर्ती की बात मैं नहीं करूंगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : I would request you to please conclude within 2 minutes.

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नं० 8 में भवन और सड़कों की बात कही हुई है। मेरे हल्के में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता। मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे गांव की सड़क को इतना बढ़िया और इतना ऊंचा बना दिया कि जब बारिश हुई तो गांव के सारे घर पानी में डूब गये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उस सड़क के साथ-साथ एक नाला भी बनाया जाये ताकि जो गांव का पानी है उसकी निकासी हो सके। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस सरकार ने कई जगह भवन बनाये हैं लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया में तो एक ईंट भी नहीं लगी है। हमारा बस स्टैण्ड जो अढाई साल पहले बनना शुरू हुआ था, उसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी चल रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बस स्टैण्ड को स्पीड से बनाया जाये। इसके अलावा मैं लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के में एक विश्राम गृह बनाया जाये ताकि माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय आप कभी-कभी हमारे हल्के में दर्शन दे सकें। जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग की बात है 1976 में हमारे गांव में नहर के पानी की एक ब्रिगी लगाई गई थी। आज उसका इतना बुरा हाल है कि हमारे गांव के लड़के पानी को ढो-ढो कर गंजे हो गये हैं जिसके कारण उनका कोई रिश्ता भी नहीं करता है। (विघ्न) (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जो डिस्पैंसरी है उसमें चार डाक्टरों की पोस्ट सैंक्शंड हैं लेकिन उनमें से एक भी वहां पर पोस्टिड नहीं है मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक डाक्टर तो वहां पर लगाया जाये। जहां तक सिंचाई की बात है हमारा सारा इलाका टेल पर पड़ता है एक दो जगह को छोड़कर किसी भी नहर की टेल पर पानी नहीं पहुंचता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी टेलों पर पानी पहुंचाया जाये। पहले नहरों में पानी 15 दिन तक चलता था लेकिन अब सात दिन तक चलता है। सरकार से अनुरोध है कि नहरों में पानी 15 दिन तक तो चलना ही चाहिये। जहां तक सहकारिता का सवाल है हमारे इलाके में

किसानों को कोआप्रेटिव बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। अगर उनको ऋण मिलता भी है तो या तो वह किसी की सिफारिश के आधार पर या पर्ची सिस्टम के आधार पर मिलता है। जब हम उन अधिकारियों को मिलते हैं तो वे कहते हैं कि आप तो अपोजीशन के एम०एल०ए० हैं। ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम क्या करें ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किथाना गांव के अंदर हम ने एक को-आप्रेटिव बैंक खोलने की मांग कर रखी है, मेरी प्रार्थना है कि वहां पर को-आप्रेटिव बैंक खुलवाया जाए। इसके साथ ही जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं डिमांड सं० 3, 8, 10, 15, 23 व 25 से संबंधित कुछ बातें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य देश के सभी राज्यों में एक शांतिप्रिय राज्य समझा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की आलोचना करने नहीं जा रहा हूं। लगभग पिछले 26 महीनों में, जब से यह भाजपा-हविपा गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, हरियाणा के जनमानस के अंदर असुरक्षा की भावना पनपी है और बड़ी तेजी से अपराधों का ग्राफ प्रदेश के अंदर बढ़ा है। यह एक चिंतनीय विषय है। इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य यू०पी० और पंजाब में अपराध होते थे, उसी प्रकार से हरियाणा राज्य में अब अपराध होने लगे हैं। परसों शायद गृहमंत्री जी अपने जवाब में पिछले 10 महीने की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर रहे थे जिस में यह वर्णन था कि इतने बलात्कार हुए हैं, इतने अपहरण के केस हुए हैं तथा इतने कार वगैरह छीनने के केस हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन आपराधिक घटनाओं के कारण क्या हैं। यह जानने का हम सब लोगों का फर्ज बनता है। जब हमें जनता ने चुनकर इस महान् सदन में भेजा है तो हमें इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि आखिर इन आपराधिक घटनाओं के कारण क्या हैं और राज्य में इन समस्याओं का हल क्या हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। हर गांव के अंदर सैंकड़ों बेरोजगार युवा बेकार घूम रहे हैं। इसलिए आज एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है, जिसके तहत सभी युवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बगैर नौकरियां मिलें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। आज मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। कल दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाए जाते थे परसों किसी दूसरी पार्टी अथवा सरकार पर आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए हम सब को मिलकर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा व पार्टी से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां मिलें, चाहे वह पुलिस भर्ती हो, चाहे चपड़ासी की भर्ती हो अथवा किसी अधिकारी की भर्ती हो। योग्य उम्मीदवार को बिना सिफारिश व पैसे दिए, अपना उचित स्थान मिलना चाहिए। सदन में पुलिस भर्ती का जिक्र भी किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। कई नौजवान 6 फुट से भी ज्यादा कद वाले हैं, वे भागदौड़ इत्यादि में सबसे आगे रहे हैं लेकिन उनको यथायोग्य स्थान नहीं मिल पाया है। जब यह भाजपा-हविपा गठबंधन की सरकार बनी थी तो वास्तव में ही मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यह सरकार पार्टी के मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि पुलिस भर्ती में सरकार ने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों को 15-15 सीटें अलॉट की हैं। हो सकता है, दूसरे भाई इस बात से इन्कार करेंगे, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने की कृपा करें। मेरे हल्के के सीमा गांव का एक नरेश नाम का लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने फिजीकल टैस्ट यानि भागदौड़ का टैस्ट पास कर लिया उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पर जो अधिकारी इंटरव्यू ले रहा था,

[राव नरेन्द्र सिंह]
उस ने मुझ से पूछा कि क्या आप को गाना गाना आता है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस भर्ती के लिए भी गाना गाने की आवश्यकता पड़ेगी ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी तो यही गुजारिश है कि सब लोगों को रोजगार देने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि कोई भी सरकार सब को नौकरी नहीं दे सकती है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : आप बताएं कि हमने इंटरव्यू के लिए कोई प्रावधान बनाया है या नहीं।

राव नरेन्द्र सिंह : आदरणीय गृह मंत्री इस सदन के सबसे बरिष्ठ आदमी हैं। मैं मानता हूं कि नौकरियों में इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रावधान हैं परन्तु पुलिस विभाग में गाना गाने का क्या सम्बन्ध है ?

श्रीमती कमला वर्मा : संगीत जानना भी एक बहुत बड़ी कला है न कि कोई बुराई।

राव नरेन्द्र सिंह : मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सभी भाईयों को नौकरी नहीं मिल सकतीं। न आपकी सरकार दे सकती है, न हमारी सरकार दे सकती है और न ही कोई और सरकार दे सकती है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

श्री मनी राम गोदारा : इस पुलिस भर्ती में हरियाणा के अन्दर 87,000 नौजवानों ने हिस्सा लिया। इनमें से 37,000 नौजवान फिजीकल फिट निकले। कोई भी बोर्ड चाहे एस०एस०एस० बोर्ड हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई और बोर्ड हो, वह अपने लैवल पर इंटरव्यू लेते हैं और अपना काम करते हैं। हम इसमें अपनी तरफ से नहीं देखते। (शोर)

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं, से कहना चाहूंगा कि मेरे मुताबिक बी०सीज० कैटेगरी के लिए 11 प्रतिशत आरक्षण है लेकिन जहां तक मेरे नालेज में आया है महेन्द्रगढ़ जिले में यादव, सैनी और गुजर इस पुलिस भर्ती में केवल 7 ही लिए गए। जबकि यादव, सैनी और गुजर कैंडीडेट्स से फार्म भरवाते समय आरक्षित कैंडीडेट लिखवाया गया।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : इनके नोटिस में शायद यह बात नहीं है कि 1992 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो बी०सीज० और एस०सीज० कैंडीडेट्स मैरिट पर आ जाएंगे, वे जनरल कैटेगरी में समझे जाएंगे वे रिजर्व कोटे में नहीं समझे जाएंगे। आपके एरिए में अहीर या गुजर ज्यादा हैं और वे मैरिट पर आ गए होंगे। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का वाएलेशन किया जा रहा है उसको ठीक करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : राव नरेन्द्र सिंह जी, आप 5 मिन्ट में कन्क्लयूड करें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे 6 दिन के अन्दर पहली बार बोलने का समय मिला है इसलिए मुझे पूरा समय दिया जाए। सबको नौकरियां तो नहीं मिल सकतीं इसलिए जिन जिलों में सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं जैसे महेन्द्रगढ़ जिले में ऐसे जिलों में जो रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। दादरी भी उसमें शामिल कर लिया जाए। स्पीकर साहब, मेरी नौलेज में एक बात आई थी। कल हमारा नारनौल तमाम बंद रहा क्योंकि वहां पर पिछले एक हफ्ते के अन्दर तीन घटनाएं हो गई हैं जिनमें से दो आदमी भगवान को प्यारे हो गए हैं उनका मर्डर हो चुका है और एक आदमी सीरियस हालत में है। इसके अलावा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हिसार में एक फाईनेंस कम्पनी के मालिक को मार दिया गया उसकी अखबारों में फोटो भी आई थी उसको अपने आफिस में कुर्सी पर बैठे हुए गोली मार दी गई। स्पीकर साहब, हमारे गृह मंत्री जी बहुत

तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने होम डिपार्टमैंट पर तगड़ी गिरफ्त करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा राज्य परिवहन की बसें अदर स्टेटस राजस्थान और पंजाब के अन्दर जाती थीं तो लोग देखा करते थे कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसें देश के अन्दर प्रथम स्थान पर चल रही हैं आज वही स्थान किन कारणों से नीचे जा रहा है। आज हमारा हरियाणा राज्य परिवहन विभाग घाटे में जा रहा है क्योंकि सरकार ने प्राइवेट रूट परमिट देने की बीमारी चला दी है जिसके कारण स्टेट की बसों का भट्ठा बैठ गया है। अब सरकार की तरफ से बेरोजगारों को 100 किलोमीटर तक के रूट परमिट देने की स्कीम चल रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि 100 किलोमीटर तक के जो रूट परमिट दिए जाएंगे उनमें विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को ही वे रूट परमिट नहीं मिलने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, हम देखा करते थे कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में अवैध व्हीकल्ज कमाण्डर जीपें चला करती थीं वह 50-50 सवारियां ले कर चलती थीं। उनमें 50-50 सवारियां बैठी होती थीं और उनके एक्सीडैंट्स में हजारों नौजवान मर चुके हैं। इसलिए हमारे यहां भी अवैध व्हीकल्ज चलने की बीमारी पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जो प्रभावशाली लोग अवैध व्हीकल्ज चला रहे हैं उन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिन सड़कों की पिछले दो साल से बुरी हालत है, चाहे वह बारिश की वजह से है और चाहे बाढ़ के कारण है, पिछले दो साल में जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन सड़कों की मुरम्मत की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाई वे जो धारूहेड़ा से खेजड़ी की ओर से अदर स्टेट को जाता है, बजट के अन्दर उसको चौड़ा करने का प्रावधान है, यह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नारनौल का बाई पास भी जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है। उसके बारे में यह जिक्र आया कि उसको कम्पलीट करवाने के बारे में केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। स्पीकर साहब, दिल्ली में भाजपा की सरकार है उसमें इनका भी समर्थन है और पंजाब के एम०पीज० का भी समर्थन है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से पंजाब सरकार पर उस नहर को बनवाने के बारे में हमारी सरकार को ज्यादा दबाव डलवाना चाहिए। मैं कहूंगा कि हलोदरा का भी केन्द्रीय सरकार को समर्थन प्राप्त है इसलिए इनकी तरफ से भी उस नहर को बनवाने के बारे में पंजाब सरकार पर दबाव डलवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर पूरी होने से दक्षिणी हरियाणा और जिला महेन्द्रगढ़ के शुष्क खेतों को पानी मिलेगा। अब मैं बिजली के विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्पीकर साहब, 31 मार्च 1990 के बाद ट्यूबवैल्ज के नए बिजली के कनैक्शन नहीं दिए गए इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री महाजन जी सदन में बैठे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बहुत खराब है अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह सरकारी अस्पताल में जाने की बजाय प्राईवेट अस्पताल में जा रहा है क्योंकि अगर किसी अस्पताल में कोई अच्छा डाक्टर है तो सरकार उसका तबादला कर देती है। किसी सरकारी अस्पताल में कोई इक्विपमैंट नहीं है, किसी अस्पताल में एक्स-रे मशीन नहीं है किसी में जनरेटर नहीं है सरकार इस तरफ ध्यान दे। स्पीकर साहब, मेरे हल्के के नसीबपुर गांव में एक शहीदी स्मारक बना हुआ है। वहां पर 16 नवम्बर को शहीदी दिवस मनाया गया था उसमें प्रो० राम विलास शर्मा जी भी गए थे। इन्होंने उसके लिए एक लाख रुपये ग्रांट देने की घोषणा की थी। सीयरेज की वजह से वहां पर गंदगी बहुत हो चुकी है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उस समय के स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व राव तुला राम, राव गोपाल सिंह और कृष्ण गोपाल ने किया। उस दिन वहां पर लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वहां पर पार्टी लाईन से ऊपर उठ कर शहीदी दिवस मनाया गया उसमें मैं भी शामिल हुआ था लेकिन ये माननीय सदस्य उस दिन वहां पर नहीं आए।

राव नरेन्द्र सिंह : मैं माफी चाहूंगा कि किसी कारण से उस दिन मैं नहीं आ सका।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप जल्दी कन्कलूड करें।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मेरे अटेली क्षेत्र के अन्दर एक फोर लेनिंग लाईन की स्कीम सैंक्शन हुई थी। मैं चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने की कोशिश करें। स्पीकर साहब, नारनौल के अन्दर एक जल महल के नाम से बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग अकबर के साथ जो बीरबल होते थे, उनकी बातों के इतिहास से जुड़ी हुई है।

Mr. Speaker : Please conclude your speech.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि नारनौल के अन्दर जो जल महल की बिल्डिंग है वहां पर हमारे जो पहले फुलिया साहब डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने वहां की स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बिल्डिंग को जयपुर तक के लोग देखने के लिए आते हैं। मैं चाहूंगा कि इस बिल्डिंग को सरकार ठीक कराये या जो पुरातत्व विभाग है उसको इस बिल्डिंग की देखरेख का काम सौंप दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

Mr. Speaker : Please sit down. I have called upon Shri Suraj Mal.

राव नरेन्द्र सिंह : ठीक है जी, आपका धन्यवाद।

श्री सूरजमल (राई) : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज पता चला कि सारी डिमांडज आज ही पास हो रही हैं इसलिए हम भी अपनी बात कह देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आज भेदभाव बरता जा रहा है। जितने भी अपोजीशन के हल्के हैं उन सब के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। मेरा हल्का और कैलाना हल्का साथ साथ हैं। वहां पर पानी की सतह भी एक ही तरह की है। कैलाना हल्के में तो सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू कर दी जबकि मेरे हल्के राई में सरकार ने यह प्रणाली लागू नहीं की। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव बरत रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में सड़कों की रिपेयर नहीं हो रही कागजों में हो रही हो तो अलग बात है लेकिन असल में वहां पर कोई काम नहीं हुआ। बेशक मंत्री जी मेरे साथ चल कर देख लें, यदि यह बात सही नहीं होगी तो मैं कसूरवार हूंगा। मेरे हल्के में किसी भी सड़क का ऐस्टिमेट पास नहीं हुआ। जब ऐस्टिमेट ही पास नहीं हुआ तो सड़कें कहां से बनेंगी ? अफसरों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि अपोजीशन के हल्कों के एस्टिमेट पास नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में रेत की खानें हैं। वहां पर जगह-जगह पर खानें खुदी हुई हैं। खान माफिया वहां पर खड़ा हो गया है। वहां पर इसी कारण झुण्डपुर में पिछले दिनों कत्ल भी हुआ है। वहां पर मनमर्जी के हिसाब से खानों की खुदाई हो रही है। उन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई

पाबन्दी नहीं है। एक खान खोदने वाला किसी का एक किल्ला खान खोदने के लिये लेता है तो उसको वह पचास फुट की गहराई तक खोद डालता है। इसका नुकसान यह होता है कि जो साथ वाला मालिक है जिसका साथ लगता किल्ला है वह उसको उन्हें देने पर मजबूर हो जाता है। वहां पर रास्ते भी नहीं छोड़े गए। हर जगह पर खानें खोद दी गई हैं। वहां पर खान माफिया के लोग खानों पर बन्दूक लेकर बैठे रहते हैं जिस कारण दूसरा आदमी सेफ नहीं रह पाता। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भाई को मेरी बात पर यकीन न हो तो वहां जाकर देख सकता है। आज मेरे हल्के में रेत की खानों का बिजनैस सबसे बड़ा बिजनैस है, इससे लोग बड़े परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पार्टी बाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, बताना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि वह मेरा हल्का है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जमीन के बारे में करूंगा। मुरथल, खेवड़ा और मांगल आदि गांवों में पंचायत की जमीन बहुत ज्यादा है। बी०डी०ओ० और पंचायत ऑफिसर पंचायत की जमीन को पट्टे पर देते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में पंचायत की जमीन को बी०डी०ओ० और पंचायत ऑफिसर अपनी मनमर्जी से पट्टे पर देते हैं, जिसको चाहा उसको देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव मुरथल में अभी 6-7 महीने पहले 98 एकड़ भूमि 600 रुपये, 700 रुपये के हिसाब से पट्टे पर दी गई जबकि उसका रेट इससे कहीं ज्यादा है। इस बारे में मैंने एक पत्र डी०सी० साहब को लिखा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, वे सब मिले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसी तरह से अफसरों की मन-मर्जी चलती रहेगी तो इन गांवों की पंचायतें बरबाद हो जायेंगी, लोग बरबाद हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि हम हरियाणा को बिजली ठीक तरह से दे रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में बिजली मुश्किल से दो दिन में 4-5 घंटे आती है और उस 4-5 घंटे में बीस बार बिजली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कमी है इसलिए आप ज्यादा बिजली किसानों को नहीं दे सकते लेकिन जो 4-5 घंटे आप बिजली देते हैं वह तो लगातार दें ताकि किसान की एक -आध एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, अगर रात को थोड़ी देर बिजली मिल जाये तो किसान ठीक तरह से खाना तो खा सकता है और सुबह अपने डंगरों को घास-फूस भी काटकर डाल सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या कर रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, एस०डी०ओ० और जे०ई० वहां आफिसों में बैठे हैं, वे किसी का कोई काम नहीं करते। अगर उनको पैसे दे दिये जायें तब तो वे काम कर देते हैं वर्ना पैसे किसी का काम नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, किसान परेशान हैं उनका काम महीनों तक पड़ा रहता है जब वे बिजली वालों को काम करने के लिए बार-बार कहते हैं तब वे लोग उनसे पैसे मांगते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 6 थाने हैं और 6 के 6 थानों में एस०एच०ओ० भी हैं इस बात से मैं इनकार नहीं करता लेकिन सर, ये एस०एच०ओ० लोगों को बचाने की बजाय उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे पैसे लेकर ही काम करते हैं। जब शिकायत करते 13.00 बजे हैं तब उनको आपस में बदल दिया जाता है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर भ्रष्टाचार का बोल बाला है। अगर कोई भाई अपना कोई काम करवाने के लिए जाता है या कोई रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो कोई भी काम पैसा दिए बिना नहीं होता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस आदत पर थोड़ा अंकुश लगाया जाना चाहिए और स्थिति को कण्ट्रोल में करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम होता है तो उसमें थोड़ा टाईम तो लगता ही है (घण्टी) स्पीकर सर, पुलिस भर्ती के लिए इन्टरव्यू वगैरा हुए हैं और उसकी लिस्ट अभी आउट होनी है। यह कहा जा रहा है कि उसमें कोई हेराफेरी या धांधली नहीं है और सिलैक्शन मैरिट पर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह लिस्ट लगाएंगे उसी से पता

[श्री सूरजमल]

लग जाएगा कि सिलैक्शन फेयर और मैरिट के आधार पर हुआ है या नहीं। अगर उस लिस्ट के अन्दर 20-25 आदमी हर जगहों के होंगे तो यह लिस्ट सत्य है और हम मानेंगे कि भर्ती मैरिट के आधार पर हुई है लेकिन आदमी बाहर के होंगे तो हम यह बात असत्य मानेंगे। इस बात का पता चल जाएगा कि इन्टरव्यू ठीक लिया है या गलत लिया है। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी (घण्टी) इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री रिसाल सिंह (मुलाना, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला खराब है फिर भी मैं आपके माध्यम से अपनी बात सरकार को कहने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड्ज पर तो बात होती ही है लेकिन चर्चा अपने हल्के की की जाती है। यह चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि हर हल्के में अपनी-अपनी मुश्किलें और समस्याएं होती हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने हल्के की बिजली की समस्या के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक बिजली की बात है, मेरे हल्के में बिजली की बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय, केवल दो-चार घण्टे बिजली मिलती है और वह भी टूट कर मिलती है और बार-बार ट्रिपिंग होती है। शाम के टाईम जब बिजली आती है उस समय थाली में रोटी रखी होती है लेकिन तभी बिजली चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात न करते हुए बिजली के बारे में एक दो बातें जरूर कहूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सभी मैम्बर्ज से दरख्वास्त है कि वे जब भी बोल रहे थे या बोलेंगे तो उस समय मैं बीच में उनको इन्ट्रप्ट नहीं करता इसलिए अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी इन्ट्रप्ट न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव केसरी में एक 33 के०वी० का पावर सब-स्टेशन था और उसकी सीधी लाईन भाखड़ा से जुड़ी हुई थी। हमें यह आश्वासन दिया गया कि उसकी जगह पर 66 के०वी० का सब-स्टेशन बना दिया जाएगा जिससे हमारे गांव के लोग बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब हमारे गांव में बिजली ज्यादा आया करेगी। लेकिन अब भी वहां पर 33 के०वी० का ही सब-स्टेशन है और उसकी भाखड़ा वाली लाईन को हटा कर अब हमें पानीपत की लाईन से जोड़ दिया गया है। भाखड़ा वाली लाईन हटाने की वजह से वहां पर आज बिजली की वोल्टेज कम आ रही है और ट्यूबवैल्ज भी नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं आपको एक शेर पढ़कर सुनाता हूं—

"जिस खेत से मुयस्सर न हो रोटी,
उस खेत के हर दाने को आग लगा दो।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में हर जगह पर डीप ट्यूब्वैल्ज हैं। पता नहीं दलाल साहब और मुख्यमंत्री जी को अम्बाला जिले से क्यों नफरत है ? अम्बाला जिले से पांच मैम्बर्ज हैं और उनमें से चार मैम्बर्ज तो इनके ही साथी हैं। उन्होंने सारे हरियाणा में बिजली के जो रेट लागू किए हैं पता नहीं जिला अम्बाला में वे क्यों लागू नहीं किए हैं ? मेरे हल्के में 100 फीट तक के 1513, 100 फीट से 150 फीट तक के 908, 150 से 200 फीट तक 601 और 200 फीट से ज्यादा के 1579 डीप ट्यूबवैल्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ोस के हल्कों में जहां लोगों को राहत मिली है वहीं मेरे हल्के में 908 ट्यूबवैल्ज पर 10 पैसे, 601 ट्यूबवैल्ज पर 20 पैसे और 1579 पर 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा रेट लिए जा रहे हैं। यह अम्बाला जिले के साथ न्याय संगत बात नहीं है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब इनका फैसला दूसरे जिलों में लागू हो गया है तो हमारे जिले में भी यह लागू होना चाहिए। मेरे हल्के में 154 एम०आई०टी०सी० के ट्यूब्वैल्ज हैं उनमें से 30 कंडैम हो

गए हैं, 22 वर्किंग कंडीशन में हैं और जो बाकी 102 हैं वहां पर भी पानी का लैवल नीचे चला गया है। तो मेरी आपसे विनती है कि वहां पर उनमें नई मोटरें लगाकर उन ट्यूबवैल्ज को चालू करवाएं। इसके अलावा जनाब, मेरे हल्के में जहां तक रोड्ज की बात है, वहां सिर्फ उन रोड्ज की रिपेयर हुई हैं जिन पर सारे मंत्रियों का आना जाना होता है ये मंत्री महोदय रोहतक, हिसार या पानीपत वगैरह जाते हैं या फिर बहन कमला वर्मा या सुभाष चौधरी जाते हैं। बाकी जितनी मेरे हल्के में रोड्ज हैं उनकी रिपेयर नहीं की जाती। बहुत सी रोड्ज ऐसी हो गयी हैं जिनमें बहुत खड्डे पड़ गये हैं यहां तक कि कुछ रोड्ज की ऐसी हालत है जिन पर स्कूटर या मोटर साईकिल पर बैठकर गर्भवती महिलाएं चलना पसंद नहीं करती क्योंकि उनको गर्भपात का खतरा होता है। आज तक वहां पर किसी भी सड़क की रिपेयर नहीं हुई है। इसकी वजह से सड़कें टूट-टूट कर जोहड़ में गिरने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी रोड्ज की हालत हमारे हल्कों में ही क्यों है ? मैं कुछ सड़कों का नाम लेकर मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन सड़कों की मुरम्मत करवायी जानी बहुत ही आवश्यक है। ये सड़कें हैं—अधोया से अमालगढ़, अधोया से अलावलपुर, अधोया से थम्बड़, बराड़ा से थम्बड़ वाया रामपुर, बराड़ा से मुलाना वाया सोहला, बराड़ा से शाहबाद, धीन से अलीपुर, महोली से उपलाना आदि। इसके अलावा चार सड़कें मेरे हल्के में ऐसी हैं जिन पर अर्थवर्क तो हो चुका है। यह अर्थवर्क तीन साल पहले हो चुका था इन पर मिट्टी वगैरह गिर चुकी है और अब रोड़ी पड़नी है। लेकिन वहां आगे काम न होने के कारण वह मिट्टी भी बह रही है। ये सड़कें हैं—उगाला से राउ माजरा, उगाला से टडवाली, थम्बड़ से डेरा सलेमपुर और जवाहर लाल नगर से बीहटा। इन सड़कों की तरफ भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इंजीनियर-इन-चीफ, पी०डब्ल्यू०डी० ने कोई लैटर इशु किया हुआ है कि जिन सड़कों पर पहले काम हो चुका था, उन पर अब काम न किया जाए। इनको अगर कोई राजनैतिक दुश्मनी निकालनी है तो वह अलग बात है लेकिन सही बात यह है कि सड़कें न होने की वजह से वहां पर लोगों को बहुत परेशानी है इसलिए मेरा कहना है कि पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में, गावों में हरिजन बस्तियों में या बैकवर्ड बस्तियों में वाटर सप्लाई नहीं हो रही है इसलिए मंत्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बीरपाल सिंह द्वारा इस बारे में कही गयी बात का भी ध्यान नहीं दिया था। यह तो वही कहावत हुई कि "जोरू का भाई एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ"। इसलिए ये हमारी बात कहां मानेंगे। फिर भी मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जहां-जहां पर इस तरह की बस्तियां हैं वहां पर उनको पीने का पानी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब शराबबंदी हो गयी थी तो हमने सोचा था कि इसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे और अच्छे आदमियों को इससे राहत मिलेगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि शराबबंदी को पूरे तरीके से लागू करवाया जाए। कम से कम मैंने तो पूरी कोशिश की है। जिन लोगों ने शराब बेचने वालों को उस समय पकड़वाया था, उनके ही पुलिस के डंडे लगे थे, उनके ही सिर फूटे। इसलिए इसके फेल होने की वजह हम नहीं हैं इसकी वजह या तो सरकार है या फिर शराब माफिया है या फिर पुलिस है। लोगों को पुलिस द्वारा जब पीटा गया तो उन्होंने इस बारे में पुलिस से शिकायत करना बंद कर दिया। इसी तरह से जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें कोई कहता है कि डेढ़ लाख रुपये लेकर होगी कोई कहता है कि फेवरेटिज्म होगा। वह तो जो होगा बाद में पता चल जाएगा लेकिन जैसी घोषणा की गई है कि हर हल्के से 20 आदमी लिए जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी हल्के के आदमी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हैं और फिर भी उन्हें नहीं लिया जाता है तो यह उस हल्के के साथ भेदभाव होगा, अन्याय होगा। यह जो कहा गया है एक हल्के से 20 आदमी लिए जाएंगे यह एक झूठी घोषणा होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 2, 9, 12 ,15 पर अपने विचार रखूंगा। कुछ मेरे हल्के की समस्याएं हैं कुछ और बातें हैं। स्पीकर सर, इलैक्शन से पहले सरकार ने बेरोजगारों से और प्रदेश के लोगों से बहुत वायदे किए थे और उनको गुमराह किया था कि पैट्रोल पम्प दिए जाएंगे, रूट-परमिट दिए जाएंगे लेकिन सरकार बेरोजगारों का शोषण करने में लगी हुई है। उन्हें कोई पैट्रोल पम्प नहीं दिए गए। सरकार ने जो रूट-परमिट निकाले हैं उनमें रूट 418 हैं और परमिट 699 को दिए जाने हैं। एक सोसाइटी में 5 बेरोजगार होते हैं। प्रदेश के अंदर 7 हजार सोसाइटीज रजिस्टर्ड हुई हैं। पहले तो सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने का खर्च कम होता था लेकिन अब सरकार ने वह खर्च बढ़ाकर 6125 रुपये प्रति सोसाइटी कर दिया है और अगर 6125 रुपये को 7 हजार रुपये से जर्ब करें तो सरकार ने बेरोजगारों से 4200-4300 करोड़ रुपये के लगभग ज्यादा लिया है जो कि उनके साथ मजाक है। पिछली सरकार के समय में जिस सोसाइटी को परमिट मिलता था, उसी पर ऑडिट फीस लगती थी लेकिन अब वह फीस बढ़ाकर सरकार ने एक हजार रुपये सालाना कर दी है। इस प्रकार नौजवानों का शोषण हो रहा है। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जिस सोसाइटी को परमिट न मिले, उस पर ऑडिट फीस नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा पंजीकरण का जो रेट है वह कम किया जाए क्योंकि यह सरासर बेरोजगारों के साथ धोखा है। अब मैं शहरी विकास विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने रोहतक शहर के विकास के लिए 3-4 करोड़ रुपये की स्पैशल ग्रांट दी थी। रोहतक जिले में किलोई कांस्टीच्यूएंसी भी है और रोहतक कांस्टीच्यूएंसी भी है। सारे का सारा पैसा रोहतक कांस्टीच्यूएंसी में ही खर्च हुआ है इस प्रकार मेरे हल्के के साथ भेदभाव हुआ है। मेरे हल्के की सैनिक कालोनी, शास्त्री नगर, हरिजन कालोनी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कमला नगर कालोनी, हरीसिंह नगर, रैनकपुरा इन कालोनियों में कोई विकास के काम नहीं हुए। सारे का सारा पैसा वहां लगा है जहां पहले लग चुका था और अब लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यह पैसा शहर के बीच में लगा है और अगर हमने किसी अधिकारी को कहा तो उन्होंने कहा कि ये कालोनियां मान्यता प्राप्त नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि शहरी विकास ऐक्ट के तहत रोहतक शहर के अंदर दो सैक्टर बने हैं एक तो एक नंबर सैक्टर और दूसरा 14 नंबर सैक्टर है वह मान्यता प्राप्त हैं उनमें सरकार ने क्या किया है वह मैं आपको बता देता हूं। 14 नम्बर जो सैक्टर है उसकी आबादी बहुत कम है लेकिन उस सैक्टर का डिवल्पमैंट बहुत किया गया है उस पर बहुत ज्यादा रुपया लगा दिया है जबकि एक नम्बर सैक्टर के डिवल्पमैंट पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक शहरी विकास प्राधिकरण ने अभी तक वहां पर दो सैक्टर विकसित किए हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सैक्टर 14 रोहतक विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जबकि सैक्टर 1 किलोई विधान सभा क्षेत्र में आता है इसलिए शहरी विकास मंत्री ने सैक्टर एक के साथ ऐसा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है। वे सैक्टर 14 के लिए हर सुविधा देने के लिए आये दिन घोषणा करते रहते हैं लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सड़क के उस पार सैक्टर एक भी है तथा सैक्टर एक का विकास करने का काम भी सरकार ने मंत्री महोदय को दे रखा है। सैक्टर एक का एरिया सैक्टर 14 से ज्यादा है जबकि सैक्टर 14 में स्वीमिंग पूल, बाल वाटिका, डिसपैंसरी, झूला, कौम्युनिटी सैंटर आदि बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है। लेकिन सैक्टर एक में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जहां खाली प्लाट्स पड़े हैं वहां पर झाड़ियां कीकर आदि खड़ी हैं। शहरी विकास मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उनकी सफाई कराई जाये। शहरी विकास मंत्रालय करोड़ों रुपये इस विभाग को शहरों के विकास के नाम पर देता है तथा प्लाट वालों से भी काफी रुपया वसूल किया जाता है। परन्तु सैक्टर 14 में तो जोकि मैडीकल कालेज के नजदीक है, वहां पर डिसपैंसरी खोल दी गई है। पानी की निकासी का सैक्टर एक में कोई प्रावधान नहीं है। बरसात का पानी सड़कों पर भरने के कारण सड़कें भी खराब हो चुकी हैं।

इनको हरियाणा प्रदेश का मंत्री होने के नाते एक चुनाव क्षेत्र और दूसरे चुनाव क्षेत्र में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिये। वे अगर ऐसा करेंगे तो इस प्रदेश का विकास कैसे करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं अब सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। चुनावों से पहले यह सरकार लोगों से बड़े वायदे किया करती थी कि हम इस प्रदेश में गंगा का पानी लायेंगे, एस०वाई०एल० का पानी लायेंगे परन्तु आज उन वायदों पर कोई ध्यान यह सरकार नहीं दे रही है। पिछले डेढ़ साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय किलोई गांव में गये थे तो उन्होंने वहां की पी०एच०सी० को सी०एच०सी० में बदलने के लिए घोषणा की थी, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। 1995 की बाढ़ में किलोई की पी०एच०सी० की बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी। पिछले सैशन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह सी०एच०सी० की बिल्डिंग जल्दी ही बना दी जायेगी परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किलोई 15 हजार की आबादी का गांव है परन्तु चिकित्सा की वहां के लोगों को कोई सुविधा नहीं है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव को चिकित्सा की सुविधा तो मिलनी चाहिये। इसके अलावा सारी की सारी सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं जिसके कारण लोगों ने सड़क के रास्ते आना-जाना ही छोड़ दिया है अब सभी लोग जब शहर आते हैं तो कच्चे रास्ते से ही आते हैं क्योंकि सड़क में दो-दो फुट के गड्ढे हैं। भालोट से रूड़की, रूड़की से भागान और भागान से बखेता का रास्ता लोग छोड़ चुके हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। सांघी से चिड़ी की सड़क अस्त-व्यस्त हो चुकी है। यह सड़क तीन किलोमीटर बन चुकी है और तीन किलोमीटर तक अर्थ वर्क भी हो चुका है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस सड़क के काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं पशु पालन मंत्री जी का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा। कभरी गांव में एक बहुत बड़ी गऊशाला है जिसमें लगभग पांच हजार गऊएं हैं। लेकिन उन गऊओं के लिए किसी डाक्टर की सुविधा नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस गऊशाला में डाक्टर का प्रबन्ध किया जाये ताकि बीमार गऊओं की देखभाल हो सके। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो हाऊस का समय एक घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाऊस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान कानून और व्यवस्था की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। रोहतक और सोनीपत जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस हो चुकी है क्योंकि ये दोनों ही जिले यू०पी० और दिल्ली राज्यों के साथ लगते हैं, इसलिए इन में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। शराबबंदी के वक्त एक शराब का माफिया जो प्रदेश के अंदर उभरा था, आज शराबबंदी खत्म होने के बाद भी वह दिन-दहाड़े कत्ल करता है, लूट खसोट करता है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अंदर बहु-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार को इस की तरफ ध्यान देना चाहिए।

[श्री सिरी कृष्ण हुड्डा]

मेरे हल्के में पी०डब्ल्यू०डी० वालों ने सुखवरा से लाडो वाली सड़क को साढ़े चार फुट ऊंचा उठा दिया है। वहां पर एक कॉलोनी है जिसमें 500 मकान बने हुए हैं। इस सड़क को ऊपर उठाने की वजह से इस कालोनी में पानी खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी यह मांग है कि वहां पर नाला बनाया जाए। इसी प्रकार से भालोट में भी पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि विभाग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर नकली दवाईयां और खाद बेची जाती है। इससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होता है बल्कि प्रदेश व देश को भी बड़ा भारी लोस होता है क्योंकि इससे पैदावार कम आएगी। अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी मैं करना चाहूंगा हूं कि पिछली सरकार ने एक ड्रेन रठाल गांव से मुंढाल तक बनाई थी जिस पर लगभग 50-60 लाख रुपए का खर्च आया था लेकिन परिणाम यह निकला कि रठाल गांव में से एक लिटर पानी भी नहीं निकला। किसानों की वहां पर जमीन बर्बाद हो चुकी है और सरकार को लगभग 55-60 लाख रुपए का चूना लग गया। इसलिए ऐसे अधिकारी जिनको ड्रेनेज का लेवल भी करना नहीं आता है, मैं पूछता हूं कि उन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? यह सवाल मैंने मुख्यमंत्री जी से भी किया था। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा विभाग की तरफ सदन का थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे जा रहा है और हर एक गांव में प्राईवेट स्कूलों की दुकानें खुल गई हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं तथा पोस्टें भी सरप्लस हो गई हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस ओर कुछ कदम उठाए जाएं ताकि गरीब लोगों को कोई नुकसान न हो। धन्यवाद।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमांड नं० 2 से लेकर 23 तक आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। (विघ्न) आज से दो-सवा दो साल पहले यह सरकार बनी थी। जनता ने पिछली सरकारों से परेशान हो कर चौधरी बंसी लाल जी में अपना विश्वास व्यक्त किया था तथा इनको अपनी सरकार बनाने का मौका दिया था। जनता को बड़ी उम्मीदें थीं कि चौधरी बंसी लाल जी के आने के बाद हरियाणा का विकास होगा। बिजली के बारे में भी लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। पहले यह कहा जाता था कि बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता हैं। यह बात सच है कि बंसीलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री थे उस समय हरियाणा का निर्माण हुआ था। इन्दिरा गांधी और कांग्रेस सरकार ने उस समय हरियाणा को पैसा दिया और हरियाणा का निर्माण हुआ। यह बात ठीक है कि जो मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है उसका नाम होता है। अब इस सरकार को बने हुए 2 साल 2 महीने हो गए हैं लेकिन जब सरकार बने हुए 6 महीने ही हुए थे तभी लोगों ने अपनी परेशानियां बतानी शुरू कर दी थीं। अब उनकी उम्मीदें बेकार चली गई हैं। ये कहते थे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाएंगे लेकिन इन दो सालों में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं अपने हल्के की सड़कों के बारे में बताता हूं मेरे हल्के सोनीपत में 24 गांव हैं किसी भी गांव की सड़क पर आराम से ट्रक नहीं चल सकता, बैलगाड़ी नहीं चल सकती, यहां तक कि आदमी का भी चलना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटी सी मिसाल सड़कों से पहले बिजली के बारे में देना चाहता हूं। कल जिस समय मुख्यमंत्री जी बिजली के बारे में बता रहे थे कि बिजली में सुधार हुआ, उस समय सोनीपत में मुरथल से 8 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ था। वह जाम लगभग 10 घण्टे इसलिए रहा क्योंकि 8 दिन से बिजली न मिलने के कारण लोगों ने मुरथल से पानीपत तक जाम लगा रखा था। इसका जिक्र आज अखबार में भी है। मेरे हल्के के किसी भी गांव में 8-8 दिन तक बिजली नहीं आती और ये कहते हैं कि आने वाले समय में लोगों को 24 घण्टे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री जी मेरे हल्के सोनीपत में 6 जुलाई 1997 को आए थे इन्होंने वहां एक पब्लिक मीटिंग को सम्बोधित करते हुए कहा

था कि 31 मार्च 1998 तक सोनीपत में 220 के०वी० का एक सब-स्टेशन स्थापित हो जाएगा। वह सब-स्टेशन चालू तो क्या हुआ बल्कि उसका आधा सामान उठाकर रोहतक ले गए। आज सदन में मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1999 मार्च तक उस सब-स्टेशन को चालू कर दिया जाएगा। मैं यह कहता हूं कि चलो अब ध्यान दिया तो सही लेकिन यह बात आश्वासन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज जो बजट रखा गया है वह केवल झूठ के पुलिन्दे बनाकर जनता को उलझाने के लिए रख दिया गया है। आज जनता जागरूक है और वह ऐसे छटपटा रही है जैसे एक मछली बिना पानी के छटपटाती है। जनता अवसर ढूंढ रही है कि इस सरकार को कैसे हटाया जाए और जैसे ही जनता को अवसर मिलेगा वह इस सरकार को एक मिनट भी नहीं रहने देगी। जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, मैं अप्रैल में अस्पताल में दाखिल था, मेरे हल्के के कुछ आढ़ती खरखौदा से पेमैंट लेकर आ रहे थे, उनको रास्ते में लूट लिया गया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई और लूटने वालों के नाम भी बताए। पुलिस उन डकैतों को पकड़ कर भी लाई लेकिन वहीं के किसी मंत्री के कहने पर उन लोगों को छोड़ दिया गया। 2-3 दिन बाद वे आढ़ती दिल्ली में मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने फोन किया और फिर उन डकैतों को पकड़ा गया। इसके बाद उनकी पेमैंट भी वापिस हो गई। इस प्रकार से यदि मंत्री या एम०एल०ए० डकैतों का साथ देंगे तो कानून कहां रह जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के सोनीपत के वार्ड नं० 2 गढ़ी बसीटा के 17 वर्षीय राकेश की निर्मम हत्या का जिक्र करना चाहूंगा। जिसमें उसके पिता राम कुमार ने आवेदन किया है कि उसके बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा कर राम निवास ने उसको मार कर रेलवे लाईन पुलिया के बीच डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, उसकी लाश 26-3-98 को दो टुकड़ों में पाई गई। इस बारे में जी०आर०पी० सोनीपत में केस भी दर्ज हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में निष्पक्ष जांच कराए। अध्यक्ष महोदय, आवेदन कर्ता का यह भी आरोप है कि इस केस में सरकारी तंत्र हत्यारों की मदद कर रहा है। इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी को लिखित में सूचना भेज रखी है और मुख्य मंत्री जी को भी इसकी सूचना भेज रखी है। वह गरीब इन्साफ के लिए भटक रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इसी वार्ड के गढ़ी बसीटा में कुछ शरारती तत्व रात को लगभग 11 बजे से सुबह चार बजे तक मकानों में पत्थर फैंकते हैं जिसके कारण वहां के लोगों के दिलों में दशहत फैली हुई है। वे लोग इस बारे में वहां के एस०पी० से भी मिले और 100-150 लोग मिलने के लिए चल कर मेरे पास भी आए। मैंने इस बारे में वहां के एस०पी० को चिट्ठी भी लिखी और फोन भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी उन लोगों के घरों में पत्थर फैंके जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। स्पीकर साहब, दो दिन पहले जब चौटाला साहब बोल रहे थे तो उस समय इस सरकार के एक मंत्री ने चौटाला साहब के विषय में कहा कि उन्होंने अपने शासन काल में दिए गए भाषण में व्यापारियों और पंजाबियों के बारे में कहा कि वे लुटेरे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और इस सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार पंजाबियों और व्यापारियों के हक में है ? क्या मुख्य मंत्री जी ने चुनावों के दौरान 90 में से एक भी सीट के लिए किसी पंजाबी को अपनी पार्टी का टिकट दिया था ? क्या इस सरकार ने अपने दो साल के शासनकाल में किसी शिक्षित पंजाबी को आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और एच०सी०एस० की पोस्ट पर नियुक्त किया ? सभी लोगों को पता है कि आप लोग पंजाबियों के कितने हक में हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान व्यापारियों पर हो रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार की तय नीति के अनुसार मण्डी के लाईसैंसशुदा पुराने आढ़तियों को ही नई मंडियों में फिक्स्ड प्राईस पर प्लाट दिए जाते थे और उन्हें प्लाट देने के बाद शेष बचे प्लाटों की नीलामी की जाती थी लेकिन मौजूदा सरकार ने पुराने आढ़तियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए करनाल में सभी प्लाटों की नीलामी की, उस

[श्री देवराज दीवान]

बारे में सभी जगहों के व्यापारियों ने आन्दोलन छेड़ा हुआ है। वहां पर सोनीपत के व्यापारियों ने भी गिरफ्तारी दी है आज भी वह आन्दोलन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का कर्मचारी वर्ग अपने हकों के लिए लड़ने के लिए अपनी कमर कस रहा है और दूसरी तरफ किसान भाई अपनी समस्याओं से जूझते हुए दयनीय स्थिति में अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं। अभी 22-7-98 के इंडियन एक्सप्रैस में किसानों द्वारा आत्म हत्या किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सड़कों के रख-रखाव एवं निर्माण हेतु 245 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा है।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब आप बैठिये। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात को खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब आप बैठिये।

श्री देवराज दीवान : यदि आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे तो मैं अपने कुछ प्वायंट्स जो मेरे द्वारा बोलने से रह गए हैं, आपकी इजाजत से सदन की टेबल पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

(इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान द्वारा कुछ पेपर चेयर की अनुमति से सदन की टेबल पर रखे गए।)

***श्री देवराज दीवान :** परन्तु आज हरियाणा की स्थान-स्थान पर टूटी हुई सड़कें सरकार की खोखली नीति को जाहिर कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि सोनीपत हल्के की निम्नलिखित सड़कें जिनका निर्माण तथा मुरम्मत पिछले वर्ष हो जाना चाहिए था, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं—

(1) सोनीपत शहर में रेलवे फाटक से गोहाना रोड तक

(2) सोनीपत शहर में रेलवे फाटक से मण्डी तक

(3) सोनीपत बस अड्डा से गांव माहरा तक

(4) सोनीपत में गीता भवन चौक से लेकर रैस्ट हाउस-कालूपुर रोड की सड़क को मजबूत करना, सोनीपत से बहालगढ़ जी०टी० रोड हाई-वे और सोनीपत से मुरथल जी०टी० रोड, हाई-वे को चौड़ा करना।

(5) सोनीपत में गीता भवन से बस-अड्डा तक कंकरीट पेवमैंट करना।

(6) खटाना गांव से खिजरपुर जट माजरा की सड़क का निर्माण।

(7) माहरा गांव से सिटावली गांव तक की सड़क की मुरम्मत।

(8) हुलैड़ी की सड़क के लैवल को ऊंचा करना।

*Papers laid and printed under the orders of the Hon'ble Speaker.

गांव कैलाश पुर तथा गांव बैयां पुर खुर्द में जाने का रास्ता नहीं है। आज तक दोनों गांव के लोग कई सालों से परेशान हैं। इन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए रास्ता देकर इन गरीब लोगों की परेशानी को दूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव चटाना और माहरा में वर्षा के दिनों में दो-दो तीन-तीन फुट तक पानी खड़ा हो जाता है। जिससे बच्चों को स्कूल में जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस उपरोक्त कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि सोनीपत शहर की 12 सड़कों की मुरम्मत के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये गये थे परन्तु सोनीपत के डी०सी० महोदय ने यह राशि उस समय किसी अन्य कार्य पर लगा दी जिससे इस सड़कों की मुरम्मत नहीं हो सकी। कृपया इस विषय में भी जांच करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर आबादी के साथ एक श्मशान-घाट का होना अनिवार्य है। मेरे हलके के गांव घटाना, पिनाना, जुआं, माहरा, मोहाना, भैना तितारपुर, खिजरपुर जट माजरा, सांदल खुर्द तथा सांदल कलां आदि गांवों में श्मशान-घाट तक जाने का रस्ता कच्चा है। वर्षा के दिनों में रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है। जिससे मृतक शरीर को श्मशान-घाट तक ले जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अर्थी उठाये हुए लोगों के फिसल जाने के कारण काफी दिक्कत हो जाती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हलका सोनीपत के सभी गांवों के श्मशान-भूमि जाने के रास्ते शीघ्र से शीघ्र पक्के करवाये जायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान गांव की चौपालों की मुरम्मत और नवनिर्माण की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे हल्के सोनीपत के निम्नलिखित गांवों में चौपालों की मुरम्मत तथा निर्माण होना है।

(1)	गांव मोहाना	— बाल्मीकी तथा धानकान चौपाल
(2)	गांव सांदल कलां	— धानकान चौपाल
(3)	गांव चटाना	— बाल्मीकी चौपाल तथा बी०सी० चौपाल
(4)	गांव जाहरी	— बाल्मीकी चौपाल
(5)	गांव ठरू	— हरिजन चौपाल
(6)	गांव शहजादपुर	— हरिजन चौपाल
(7)	गांव उल्देपुर	— हरिजन चौपाल
(8)	गांव पिनाना	— धानकान चौपाल तथा बी०सी० चौपाल
(9)	गांव जुआं नं० 2	— बी०सी० चौपाल तथा हरिजन चौपाल
(10)	गांव सांदल खुर्द	— बी०सी० चौपाल
(11)	गांव थरिया	— बी०सी० चौपाल

श्री राम जी लाल (सढौरा, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम लोगों को रहने के लिए स्वच्छ वातावरण देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हिमाचल से मारकण्डा नदी निकलती है, उसमें हिमाचल की इंडस्ट्रीज का इतना गंद पड़ा हुआ है कि उसका पानी पीने से आदमी बीमार हो जाता है। यह नदी मेरे हल्के के पड़ोसी राज्य मंत्री राज कुमार जी के गांव के नजदीक से होकर गुजरती है। उनके गांव में पीने का पानी नहीं है वे बाहर से पीने का पानी मंगवाते हैं। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, इस नदी के किनारे पर सैंकड़ों गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत कमी है अगर वहां के लोग नदी का पानी पीते हैं तो लोगों को पीलिया हो जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिन गांवों में नलके लगे हुए हैं वहां उन नलकों को चालू किया जाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे मारकण्डा नदी की गंदगी को साफ कराने का काम करवायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपको कानून व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में किंडली माडल टाउन में सतपाल ऐडवोकेट के घर पर डाका पड़ा था लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव मियापुर में भी एक आदमी को मार दिया गया जिसका एफ०आई०आर० नं०-26/1-2-98 है, इसी तरह से सुलतानपुर में भी एक आदमी को मार दिया गया जिसका एफ०आई०आर० नं०-49/29-3-98 है लेकिन अभी तक पुलिस इन कातिलों को नहीं पकड़ सकी है और न ही सरकार ने कोई कार्रवाई शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, गांव खेतोली में एक आदमी को मार दिया गया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आज से 8 रोज पहले रोड पर चलती हुई एक टैक्सी के मालिक को अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोली मारी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह पी०जी०आई० में आने के बाद बच गया। उन डकैतों को भी सरकार ने आज तक नहीं पकड़ा है। इसके साथ-साथ मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि जब हम सैक्शन में आ रहे थे, तब रास्ते में 12 बजे बरवाला में रामगढ़ के पास लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी, जिसके कारण हमें 2 घंटे वहां खड़ा रहना पड़ा। उन लोगों ने बताया कि दो लोगों ने वहां से 45 भैंसें चुराकर बेच दीं। उन्होंने दौड़-धूप करके उन चोरों को पकड़वाया लेकिन पुलिस ने 10 हजार रुपये लेकर उनको छोड़ दिया। वे लोग कह रहे थे कि हम रास्ता तभी खोलेंगे जब पुलिस उन लोगों को सजा देगी। अध्यक्ष महोदय, एस०डी०ओ० साहब वहां मौके पर मौजूद थे लेकिन उनके कहने पर भी उन्होंने रास्ता नहीं खोला। अध्यक्ष महोदय, मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं उन लोगों की बात हाउस के सामने रखूंगा तब जाकर उन लोगों ने रास्ता खोला। तीन घंटे तक रास्ता जाम होने से सवारियां बहुत ज्यादा परेशान थीं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बिजली के रेट्स की स्लैब प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने शिवालिक बोर्ड की मीटिंग में भी मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि जिला अंबाला में खास तौर से एम०आई०टी०सी० के 68 से लेकर 72 तक ट्यूबवैल चौधरी बंसी लाल जी के लगवाये हुए हैं। इस बारे में सर्वे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंत्री जी को पता है कि यहां पर एम०आई०टी०सी० के ट्यूबवैलों की गहराई लगभग 575 फुट है। इसके साथ ही वहां पर आम आदमी के ट्यूबवैल्ज 350 से 375 फुट गहरे हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन लोगों के ट्यूबवैल्ज गहरे हैं उन का फिर से सर्वे करवाने की बजाय बिजली के रेट्स स्लैब प्रणाली के तहत लिए जाएं क्योंकि सारा रिकार्ड आपके पास मौजूद है। जिनके ट्यूबवैल की 15 हार्स पावर की मोटरें हैं उसकी गहराई 300 फुट है और जिनके ट्यूबवैल की 10 हार्स पावर की मोटरें हैं उसकी गहराई 200 फुट है। लगभग सारी स्थिति आपके समक्ष है इसलिए इसकी दोबारा सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह रेट्स उसी तरह

से लागू किये जायें जैसे दूसरे जिलों में लागू किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिवालिक बोर्ड की कार्यप्रणाली की ओर दिलाना चाहूंगा। शिवालिक बोर्ड में मेरे पास के गांव कास्कर में बड़ी धांधली चल रही है। वहां पर कण्डी वालों की तरफ से छोटे-छोटे बांध बांधे गये हैं। इसका सारा रिकार्ड मेरे पास है। कण्डी वालों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है कि वहां पर 100 में से 30% बांध बांधे गये हैं। डी०एफ०ओ०, कण्डी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो 30% बांध बंधे हैं उनके भी लोग 30% पत्थर उठा ले गये। कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट वाले कहते हैं कि हमने ये लगाये हैं और कभी कण्डी वाले कहते हैं कि हमने लगाये हैं। इस बारे में लोग दुविधा में हैं। लोगों को न तो इनसे कोई राहत मिली है और न ही उन्हें किसी किस्म का फायदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दुनियाँ भर का पत्थर चोरी करके कभी कण्डी वाले बेचते हैं, कभी एग्रीकल्चर वाले बेचते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कोआपरेटिव सोसाईटीज तथा गवर्नमैंट सोसाईटीज के बारे में भी सरकार को बताना चाहूंगा कि आज की स्थिति में जितनी भी कोआपरेटिव सोसाईटीज हैं वे सारी की सारी भंग हैं और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। वे हर सोसाईटी में 2-2 या 3-3 आदमी एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे इलके में इस किस्म के 9 गांव हैं जिनमें जबरदस्ती और धक्के से कर्मचारी एडजस्ट कर दिए गए हैं जब कि वे सोसाईटीज ऑलरैडी घाटे में चल रही हैं। मैंने कोआपरेशन मिनिस्टर के समक्ष भी अनुरोध किया था और लिखित रूप में शिकायत भी की है परन्तु उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हिमाचल में एक पेपर प्रगति मिल लगी है यह मिल हरियाणा में जबरदस्ती छोटा मारकण्डा क्रॉस करके रास्ता लेना चाहती है जब कि रास्ता हिमाचल में ऊपर से हो कर आता है। उसने जबरदस्ती छोटा मारकण्डा से रास्ता बाउंड करके रास्ते पर मिट्टी डाल कर पानी हरियाणा की तरफ मोड़ दिया और 50-60 गांवों का नुक्सान कर दिया। उन लोगों की जो जीरी की फसल लगी हुई थी वह उस पानी में बह गई। अब उन लोगों ने दोबारा जीरी की फसल लगाई है। इसके साथ लगते हुए गांव कलौड़ी, इनजामपुर, राजपुर, नाहर पुर, बीड़, माजरा, असगर पुर, डूमावाला, पहाड़ी पुर, बकाला, हवेली फिरोजपुर आदि हैं जो कि इस पानी ने लगभग तबाह कर दिए हैं। वह मिल जबरदस्ती हरियाणा से रास्ता लेना चाहती है और पुल लगा कर पानी उन सारे गांवों की तरफ डालना चाहती है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि पंचायती जमीनों का जो मामला है वह बहुत ही गम्भीर है। सारी पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने गांव की दुर्दशा बताता हूं। मेरे गांव में 190 एकड़ जमीन पंचायत की है। सरपंच के खिलाफ मैंने कई मर्तबा लिखकर दिया है, इस बारे उसकी सस्पैंड भी किया गया था लेकिन फिर डी०सी० यमुनानगर ने उसको बहाल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं अपनी माननीय मन्त्री बहन कमला वर्मा जी का जो उनकी पुश्त पर हैं और बार-बार शह दे कर उसको बहाल करवाती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह है कि उस सरपंच ने 15 लाख रुपये की लकड़ 5000 रुपये पर आदमी से ले कर उस गांव की कटवा दी है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके बारे में मैंने डी०सी० को भी इन्क्वायरी के लिए कहा परन्तु बहन जी ने उसकी इन्क्वायरी नहीं होने दी और न ही अब होने दे रही हैं। इसके साथ ही साथ हरिजनों के साथ जो इतने अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। (विघ्न) हरियाणा में हरिजनों को जो मकान बनाने के लिए राशि अनुदान के रूप में दी जाती है वह बहुत कम है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 2200-2300 रुपये प्रति हज़ार तो ईंट आती है इसलिए पांच हज़ार रुपये की ग्रांट से मकान नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह राशि कम से कम 15 हज़ार रुपये की जाए ताकि कोई गरीब आदमी लोन ले कर ग्रान्ट ले कर कम से कम अपना मकान तो खड़ा कर ले। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ बिजली की कमी के कारण पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से ठीक प्रकार

[श्री राम जी लाल]

से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि हरिजन बस्तियों में जहां-जहां कुएं लगे हुए हैं उन कुओं की मुरम्मत के लिए 15-15 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने की कृपा करें ताकि वे अपने कुओं से पानी निकाल सकें। ऐसी ही हालत बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की भी है (घण्टी) बी०सी० के भाईयों को भी वैसी ही सुविधाएं दी जानी चाहिएं जैसी एस०सीज० को दी जाती हैं। उनकी बस्तियों की गलियों को पक्का करने के लिए और कुओं आदि के लिए भी अनुदान दिया जाना चाहिए। बहन जी उठ कर चली गई हैं। मैं वृद्धावस्था पैंशन की चर्चा फिर कर रहा हूं। वृद्धावस्था पैंशन की स्थिति यह है कि लारे में रख कर लोगों से पैंशन के फार्म भरवा-भरवा कर 7-7 या 8-8 महीने तक चक्कर कटवाते रहते हैं और आज तक लोगों से चक्कर कटवा रहे हैं। आज तक जिन लोगों ने पैंशन के लिए फार्म भरे हैं उनको नई पैंशन नहीं मिल पाई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जन-स्वास्थ्य मन्त्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि शिवालिक बोर्ड के तहत जितने भी ट्यूबवैल्ज लगाए गए हैं वह नीचे स्थानों पर लगाए हैं और पाईपों के द्वारा पानी ऊंचाई वाले गांवों तक पहुंचाया जाता है। ये पाईप अक्सर टूट जाते हैं। जो निचले ऐरिया में लोग रहते हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से की जानी चाहिए ताकि उनको पीने का पानी उचित मात्रा में मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मैंने इस बारे में शिवालिक बोर्ड की मीटिंग में भी चर्चा की थी और यहां पर भी कहता हूं कि मेरे सढौरा हल्के में एक भी गवर्नमैंट कालेज नहीं है। गवर्नमैंट कालेज तो दूर की बात है वहां पर तो कोई गवर्नमैंट हाई स्कूल भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिवालिक बोर्ड के सढौरा एरिए में कम से कम एक गर्ल्ज कालेज तो दे ही सकते हैं। वहां पर प्राईवेट स्कूलज हैं लेकिन उनकी फीसें बहुत ही ज्यादा हैं। यमुनानगर और बिलासपुर में प्राईवेट कालेज हैं। ये कृपा करके बिलासपुर के नजदीक एक गवर्नमैंट कालेज तो खोल दें। (घंटी) इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में जब मंत्री जी से अपना सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जवाब सदन की पटल पर रख दिया है। उसमें उन्होंने सन् 2001 तक सड़कों को पूरा करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, तब तक तो लोग खड्डों में गिर-गिर कर मर जाएंगे क्योंकि बहुत ही बुरी हालत उन सड़कों की है। मंत्री जी कम से कम वहां पर उन सड़कों के खड्डों में मिट्टी डाल कर उनको भरने की कृपा करें ताकि वहां पर लोगों के एक्सिडैंटस कम हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से सर्व श्री नफे सिंह राठी, नफे सिंह जुंडला, राम फल कुंडु, ओ०पी० जैन, कृष्ण लाल पवार और रेलू राम ने बोलना है। अब श्री नफे सिंह राठी जी बोलें। (विघ्न)

श्री नफे सिंह राठी (बहादुरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं० 8, 10, 15 और 23 पर बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं कानून व्यवस्था की चर्चा सदन में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब से झज्जर नया जिला बना है तब से लेकर आज तक जिला झज्जर में जितने भी अपराध हुए हैं उससे पहले उतने अपराध जिला रोहतक में नहीं हुए थे। स्पीकर साहब, इन चार महीनों के दौरान जिला झज्जर में 40 आदमियों को गोली से मार दिया गया है लेकिन अब तक पूरे मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक दिन में 21 आदमियों को गोली मारी गई। गोली मारने वाले कैथल में मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार के घर में गए। स्पीकर साहब, यह बड़े ही दुख की बात है कि इस तरह से मुख्य मंत्री जी और इनके रिश्तेदार उनको शह देते हैं। **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री कपूर चन्द शर्मा पदासीन हुए।)** सभापति महोदय, वहां पर जिस आदमी का कत्ल हुआ था उसका भाई और

वहां के कई लोग मुख्यमंत्री जी से 18-4-98 को मिलने के लिए दिल्ली में गए। जिसका कत्ल हुआ था उसके भाई ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज 12 दिन हो गए हैं लेकिन उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभापित महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से बहादुरगढ़ के उन लोगों के साथ व्यवहार किया, वह बहुत ही निन्दनीय है। जब मरने वाले के भाई ने यह बात कही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे 20 मर जाएं, मैं कोई तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूं। इस तरह से इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बात कहे ये ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यह जो 4-4-98 को कत्ल हुआ, उससे एक दिन पहले 3-4-98 को बहादुरगढ़ में हरिओम नाम के लड़के को बीच बाजार में गोली मार दी गई। लेकिन आज तक कातिल नहीं पकड़ा गया। आज बहादुरगढ़ को चम्बल घाटी बना दिया गया है क्योंकि अब वहां पर बहुत बदमाश घुस आए हैं और इनको सरकार के मंत्री एवं मुख्यमंत्री के रिश्तेदार शह देते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि जो ये वहां पर निरंतर घटनाएं घट रही हैं, अगर इन पर काबू न पाया गया तो हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदायी समय आने वाला है क्योंकि दिल्ली के साथ लगते एरिया से, यू०पी० के साथ लगते एरिया से बदमाश इधर आकर शरण लेने लग गए हैं। पहले बहादुरगढ़ में बेबी किलर कांड एक नहीं बल्कि आठ-नौ हुए। आठ या नौ साल की छोटी-छोटी बच्चियों के साथ कांड करने वाले जब नहीं पकड़े गए तो वहां के लोगों ने इसके विरोध में आक्रोश में आकर प्रदर्शन किए, धरने दिए। लेकिन इन निहत्थे लोगों पर हरियाणा की अपने आपको किसानों की हमदर्द कहने वाली सरकार ने पुलिस से गोली चलवाने का काम किया। इस गोली कांड में दो लड़के मारे गए और कई लोग घायल हुए। इसकी इक्वायरी तो सरकार करवा रही है लेकिन गोली चलाने वाले अधिकारियों का आज तक वहां से तबादला नहीं किया गया है। वे आज भी वहां मौजूद हैं। इसलिए यह कैसे संभव है कि उनको न्याय मिलेगा, जांच कैसे निष्पक्ष होगी ? जो अधिकारी उस वक्त वहां मौजूद थे जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, कम से कम सरकार को उनका वहां से तबादला तो करना ही चाहिए। इस बारे में मेरे एक दो सुझाव हैं। सरकार को सर्वप्रथम तो बहादुरगढ़ को अशान्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। साथ ही बहादुरगढ़ में पुलिस स्टाफ भी बढ़ाया जाना चाहिए। वहां और पुलिस अधिकारी लगाये जाने चाहिएं। सभापति जी, आज भी बहादुरगढ़ सदर थाने में एस०एच०ओ०नहीं है। दो महीने से यह पद खाली पड़ा है फिर कैसे वहां शांति हो पाएगी ? इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ विशेष ध्यान देने की वह कृपा करे। इसके अलावा जहां तक परिवहन व्यवस्था की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ से दिल्ली लगभग 15 हजार आदमी डेली पैसेंजरी करते हैं लेकिन इस सरकार ने बहादुरगढ़ से दिल्ली आने जाने वाली हरियाणा रोडवेज की दस बसिज बंद कर दीं। जब हम इस बारे में अधिकारियों से मिले तो उन्होंने साफ मना कर दिया और यह कहा कि सी०एम० के ऐसे आदेश हैं। सभापति महोदय, अगर अपोजीशन का हल्का होने के कारण इस तरह की यातनाएं वहां के लोगों को दी जाएंगी तो वह निंदनीय कार्य है। ये बसिज वहां दोबारा से चलायी जानी चाहिएं। सभापति महोदय, बहादुरगढ़ में पिछले दिनों जमीन अधिग्रहण की गयी। जहां यह जमीन अधिग्रहण की गयी वह इलाका दिल्ली के साथ लगता हुआ है। दिल्ली में जब जमीन अधिग्रहण की जाती है तो किसानों को 12 या 13 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है लेकिन हमारी इस सरकार ने किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण करने के बदले में सिर्फ दो या अढाई लाख रुपये एकड़ के हिसाब से ही मुआवजा दिया है जो कि बहुत कम है। जो इलाका वहां सड़कों के किनारे लगता है केवल उन्हीं दस परसैंट किसानों को चार या पांच लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है लेकिन बाकी 90 परसैंट किसानों को दो या अढाई लाख रुपये एकड़ के हिसाब से ही मुआवजा दिया गया है। सभापति जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे दिल्ली में किसानों को

[श्री नफे सिंह राठी]

उनकी जमीन अधिग्रहण करने के बदले में 12 या 13 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है वैसे ही हरियाणा में भी दिया जाना चाहिए। हरियाणा के किसान के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है ? यह मुआवजा राशि बढ़ायी जानी चाहिए। इसके अलावा जिस किसान की जमीन अधिग्रहण की जाए उस किसान को एक एक प्लाट भी वहां पर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां रैजीडेंशियल प्लॉट 14.00 बजे काटे जा रहे हैं। सभापति जी, वहां के किसान बिल्कुल बर्बाद हो गये हैं क्योंकि उनके पास तो थोड़ी-थोड़ी जमीन थी और वह भी सरकार ने ऐक्वायर कर ली है। वहां जो जमीन नगरपालिका की सीमा के अंदर है जिसकी रजिस्ट्रियां सरकार 10 या 15 लाख रुपये एकड़ से कम पर नहीं कर रही है वहां दो लाख रुपये एकड़ के हिसाब से जबरदस्ती जमीन खरीद रही है मेरा यह निवेदन है कि जिनकी जमीन ली गई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, मुआवजा राशि बढ़ा दी जाए और उनको एक-एक प्लॉट भी दिया जाए। सभापति महोदय, दुख की बात यह है कि 1160 साल पहले बहादुरगढ़ बसा था। उस समय का वहां एक शमशान घाट है उस शमशान घाट को भी सरकार ने ऐक्वायर कर लिया है। मेरी गुजारिश है कि कम से कम शमशान घाट को तो ऐक्वायर न किया जाए उसको तो छोड़ा जाए। सभापति महोदय, बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बिजली तो आती नहीं है और बिल कई-कई हजार रुपये के आते हैं। बिजली के बिल थामने से पहले दिल थामना पड़ता है। जो ये कम्पयूटराईज्ड बिल आ रहे हैं वे बिल गलत है उनमें गलत आंकड़े दिए जाते हैं। लोगों को इनकी वजह से बिजली बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन कोई ठीक करने वाला नहीं है इसलिए इन कम्पयूटराईज्ड बिलों को बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन भी नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार ने आदेश दिया है कि 30 सितम्बर, 1998 तक कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा। हमारे बहादुरगढ़ में बिजली के लोहे के खम्भे काफी समय से गड़े हुए हैं वे अब नीचे से गल गए हैं और वे खम्भे केवल तारों पर टिके हुए हैं लेकिन वह भी नहीं बदले जा रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर्ज बदलवाने के लिए भी लोग कई-कई दिन से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार ने वायदा किया था कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर्ज बदले जाएंगे। सरकार अधिकारियों को आदेश दे कि ट्रांसफार्मर्ज बदले जाएं। सभापति महोदय, पूरे हरियाणा में सड़कों का बुरा हाल है। मैं बहादुरगढ़ उपमंडल की सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा। वहां की सड़कें ऐसी हैं कि लोग सड़कों की बजाय नीचे से चलना पसन्द करते हैं। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह जी छारा में गए थे। छारा बहादुरगढ़ उपमंडल का बहुत बड़ा गांव है। (घंटी) जब वे गए तो रास्ते में सड़क इतनी टूटी पड़ी थी कि कार नीचे से उतर गई और उसका चैम्बर फट गया, पैट्रोल फैल गया। फिर वे जीप में बैठकर गए। आप सरकार से कहें कि सड़कें जल्दी से जल्दी ठीक कराई जाएं।

श्री सभापति : आपका समय हो गया है, आप बैठ जाइए।

श्री नफे सिंह राठी : आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री सभापति : आपको कन्कलूड करने के लिए दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री नफे सिंह राठी : ठीक है जी। सभापति महोदय, कुछ सड़कें मार्किटिंग बोर्ड ने बनायी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मार्किटिंग बोर्ड की जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं वह सड़कें पूरी कराई जाएं। वह सड़कें हैं—कसार से नूना माजरा (विघ्न)

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक) : सभापति महोदय, ऑन ए चाईंट ऑफ आर्डर, जिन सड़कों का ये जिक्र कर रहे हैं पिछली सरकार ने ये सड़कें कम्पलीट करवाकर इनकी पेमेन्ट भी कर रखी है। हमने इसका सारा रिकार्ड तैयार कर रखा है और इस मामले की जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी।

श्री नफे सिंह राठी : अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच करवाई जाए। सभापति महोदय, मेरे हल्के में सब्जी मंडी को ट्रांसफर किया जाए। सभापति महोदय, पानी की भी वहां बहुत गम्भीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि गुड़गांव कैनाल का पानी माईनर के द्वारा बहादुरगढ़ को 30 जून, 1998 तक मिल जायेगा लेकिन आज तक उस माईनर का काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस माईनर का काम जल्दी से शुरू किया जाये ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके और पीने को पानी मिल सके। जैसा कि यहां पर पंचायत की शामलात भूमि पर नाजायज कब्जों का जिक्र आया। सौली गांव में 28 एकड़ भूमि को सरपंच ने बिना मुनादी करवाए कौड़ियों के भाव दस हजार रुपये के पट्टे पर दे दिया जिसमें 20-25 लाख रुपये का गबन किया गया है। जबकि भाव डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ था और दिया गया छः हजार रुपये प्रति एकड़। इस मामले की जांच की जाये और दोषी सरपंच या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। सभापति जी, जाकोदा गांव से कसार गांव का रास्ता नाजायज तौर से बन्द कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस रास्ते को खुलवाया जाये। (घण्टी) (विघ्न) सभापति जी, हम तो नये-नये चुनकर आये हैं बोलना भी सीख लेंगे। मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करता हूं। सभापति जी, सरकार की जो खेलों से संबंधित नीति है उस पर पुनर्विचार किया जाये। खेलों का नौकरियों में जो कोटा घटा दिया गया है मेरा सरकार से निवेदन है कि उस कोटे को बढ़ाया जाये। सभापति जी, बहादुरगढ़ क्षेत्र के नौधामाजरा गांव की प्राईमरी स्कूल की फुटबाल की टीम लगातार तीन सालों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है परन्तु उन खिलाड़ियों को कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। उनको कोई आने जाने का खर्चा भी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि खेलों के प्रति पुनर्विचार करके खिलाड़ियों को उचित सुविधा दी जाये। (विघ्न) सभापति जी, पिछले साल रेल मंत्री जब बहादुरगढ़ आये तो लोगों ने उनके सामने डिमाण्ड रखी थी कि रेलवे लाईन के पार जो 30 हजार के लगभग आबादी है, उसके आने जाने की सुविधा के लिए रेलवे लाईन पर एक पुल का निर्माण किया जाये तब उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार आधा खर्चा पुल के निर्माण के लिए दे दे तो आधा खर्चा रेल मंत्रालय दे देगा। अभी पता चला है कि रेल मंत्रालय में अस्टिमेट तैयार हो चुका है तथा उस पुल के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपये लगेंगे। अगर राज्य सरकार 20 लाख रुपये दे दे तो 20 लाख रुपये रेल मंत्रालय दे देगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पैसे को देने की व्यवस्था की जाये ताकि लोगों को रेलवे लाईन के पार आने-जाने में सुविधा हो सके। धन्यवाद।

श्री नफे सिंह (जुण्डला, एस०सी०) : सभापति महोदय, आपने मुझे डिमाण्ड नं० 2 पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वर्तमान सरकार ने चुनावों के समय बड़े-बड़े वायदे लोगों से किए थे कि बेरोजगारों को पैट्रोल पम्प या गैस एजेन्सी के परमिट दिला देंगे, जुगाड़ के रेहड़ों को लाईसैंस दिला देंगे, 24 घण्टे बिजली देंगे, 24 घण्टे के अन्दर ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन देंगे। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद बेरोजगार युवकों को रोजगार तो नहीं दिया लेकिन नशाबन्दी की आड़ में ट्रक और टैंकर भर-भर कर नौजवान युवकों से दारू बेचने का धन्धा जरूर करवाया है जिससे लाखों रुपए उन बेरोजगार नवयुवकों ने गलत तरीके से बनाए। सरकार ने शराब की

[श्री नफे सिंह]

आड़ में उन नवयुवकों को गलत रास्ते पर लगाया। सभापति जी, जब हरियाणा में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई। उसके बाद इनको शराबबंदी को खोलने का काम करना पड़ा। इनकी नाक कटी हुई। (विघ्न) जहां तक बिजली की बात है, हरियाणा प्रदेश के अन्दर आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लोगों को बिजली मिलती नहीं है। दिन-रात खेतों में लोग बिजली का इंतजार करते रहे हैं। आज हरियाणा में बिजली न आने की वजह से हर आदमी दुःखी है। सभापति जी, पिछले सत्र के दौरान भी मैंने अपने हल्के की सड़कों से संबंधित एक सवाल किया था। मेरे हल्के में बढ़ोता से जुण्डला वाया खेड़ीनरू, खेड़ीनरू से पिचौलिया वाया जानी, बस्थली से ब्रास व जुण्डला से जरीफाबाद नई सड़कें बननी थीं लेकिन मेरे हल्के का विपक्षी सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व करने की वजह से उस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये गांव आज भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सभापति जी, मेरे हल्के में निसिंग और जुण्डला में पी०एच०सीज़० हैं। मैंने पिछले सत्र में भी एक सवाल किया था कि इन पी०एच०सीज़० की बिल्डिंग्ज़ की दीवारें गिर रही हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। मवेशी उन में घूमते हैं। मैंने कहा था कि उनकी दीवारें बनाई जाएं लेकिन आज तक इस बारे में कोई गौर नहीं की गई है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में जुण्डला से चुहड़नपुर वाया जानी, खेड़ीनरू से करनाल, निसिंग से कतलाहड़ी वाया ओंगद, निसिंग से सांभली, निसिंग से डाचर, निसिंग से गोंदर, जलमाना से रत्तक वाया उपलाना, जलमाना से उपलानी, और जलमाना से ठरबा माजरा की सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि इन में गड्ढे बने हुए हैं और इन पर गुजरने वाले व्यक्ति को यह फैसला करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन से गड्ढे से होकर गुजरें जिससे कि सुरक्षित निकल जाएं। करनाल से श्री शशिपाल मेहता जी सदस्य हैं वे अब सदन में बैठे नहीं हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि करनाल शहर में रेलवे ओवर-ब्रिज और डब्ल्यू०जै०सी० के बीच में जो कैथल रोड है तथा करनाल में जो मेरठ रोड है, उनकी इतनी बुरी हालत है कि जब भी थोड़ी सी बूंदा-बांदी हो जाती है तो ये सड़कें तालाब का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री रामफल कुंडु (सफीदों) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं अपने हल्के से संबंधित दो मांगों पर बोलना चाहूंगा। एक तो मैं ड्रेन के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार द्वारा 6-7 ड्रेनें स्वीकृत की गई थी लेकिन आज तक एक ड्रेन पर भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। बिटानी लिंक ड्रेन भी पिछले साल स्वीकृत की गई थी, लेकिन इन दो सालों में किसी भी नई ड्रेन की खुदाई नहीं हुई है तथा न ही काम शुरू हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो ड्रेन स्वीकृत की गई थीं, कम से कम उन पर तो कार्य शुरू करवा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ड्रेनों की खुदाई के बारे में है। शहर के अंदर से एक सफीदों ड्रेन गुजरती है, इसको बनाने की बात हुई थी। इसको आगे व पीछे से 700 फुट तो पक्का किया जा चुका है लेकिन शहर में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है परिणामस्वरूप शहर में पानी घुस जाता है। मेरी यह मांग है कि इस को खुदवाया जाए। जब तक वह ड्रेन पक्की न हो तब तक मेरी प्रार्थना है कि शहर के अन्दर सफीदों ड्रेन का जितना पोरशन गुजरता है, उसको जल्दी पक्का किया जाए और जहां से उसकी खुदाई शुरू होती है, जहां पर ये टेल बनती हैं मैं इस बारे में अनुरोध करूंगा कि उस पर जो अवैध कब्जे हैं, उनको उठवाकर उस ड्रेन को खुदवाया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि हांसी ब्रांच के साथ सफीदों में जो डिच ड्रेन है, वह भी बन्द पड़ी है उसमें से आज तक एक कस्सी मिट्टी भी नहीं निकाली गई है। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उस डिच ड्रेन की सफाई का कार्य करवाया जाए। इसी तरह से बम्भेवा ड्रेन है उसमें इस साल सफाई के लिए ट्रैक्टर लगाए गए थे, उन ट्रैक्टर वालों की 35,000 रु० की पेमैंट बकाया है वह उस पेमैंट के लिए बार-बार हमारे से कह रहे हैं कि आपके कहने

के बाद हम उस कार्य में लगे थे लेकिन महकमा उनकी कोई पेमैंट नहीं दे रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि बम्बेवा ड्रेन पर कार्य करने की जो ट्रैक्टर वालों की पेमैंट रहती है, वह दी जाए। उस ड्रेन की खुदाई तो कर दी लेकिन जहां रास्ते बन्द थे और जो अभी वहां पाइप पड़े हैं उन पाइपों का भी तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उनके साइफन नहीं बन जाते। जब तक उन पाइपों को निकालकर ठीक ढंग से सैट नहीं किया जाता तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। ड्रेन खोदने से पहले रास्तों का होना बहुत जरूरी है। कई जगह ड्रेन की सफाई का कार्य दिखाया जाता है, ड्रेन की खुदाई दिखाई जाती है परन्तु आगे रास्ता ब्लाक होने की वजह से वह पानी आगे नहीं जा सकता। यह बात खास ध्यान रखने की है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बम्बेवा ड्रेन आगे शिवाणा मोड़ से होकर जाती है उसमें मेरे ख्याल से जमींदार 6-7 जगह बांध बनाकर, नाली बनाकर पानी अपने खेतों में ले जाते हैं। कृपा करके उनके उन बांधों को वहां से खोला जाए। इसी प्रकार एक कालवा कैलाना ड्रेन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस साल तो कोई खास बरसात नहीं हुई है। लेकिन इस बार भी कालवा भराण गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है और जब हम ने उस पानी को निकालने के लिए मोटर लगाने के लिए कहा तो अधिकारी कहने लगे कि 15 सितम्बर के बाद मोटर दी जाएगी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 15 सितम्बर तक तो फसल बरबाद हो जाती है। इस लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप हुक्म करें कि जिस एरिए में भी पानी भरा हो उसी वक्त उस पानी को निकालने के लिए मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रबन्ध किया जाए। यही हालात रजाणा कलां, रजाणा खुर्द, बुढा खेड़ा गांवों के खेतों में होती है। हमारे द्वारा चीफ इंजीनियर, डी०सी०, एस०पी० से बार-बार अनुरोध करने पर वे मौके पर जरूर चले जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। वे आश्वासन देते हैं कि कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से सभापति जी, बजट में नई नाला ड्रेन की खुदाई के काम पर खर्च दिखाया गया है। सफीदों ड्रेन से नई नाला ड्रेन निकलती है उसका कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ है। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि जब ये गठबन्धन सरकार बनी थी तो बनते ही इन्होंने पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था लेकिन आज तक गवर्नमैंट कालेज, सफीदों में पंजाबी के लैक्चरर की पोस्ट भी सैंक्शन नहीं हुई है। जो बच्चे दाखिले के समय पंजाबी विषय लेना चाहते हैं, उनको मना कर दिया जाता है। मेरे इलाके में सरदार बहुत ज्यादा रहते हैं वे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस कालेज में पंजाबी विषय की क्लासें न होने के कारण वे दाखिले से वंचित रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां यह पोस्ट सैंक्शन करके पंजाबी विषय का लैक्चरर भेज दिया जाए। मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि गवर्नमैंट कालेज, सफीदों में संस्कृत विषय की दो पोस्टें सैंक्शन हैं और दोनों ही खाली हैं। बच्चों को वहां पर इस शर्त पर ऐडमिशन दिया जाता है कि अगर संस्कृत का लैक्चरर आ गया तो आपको पढ़ा दिया जाएगा वरना आपको ये सब्जैक्ट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं 17 तारीख को गवर्नमैंट कालेज, जीन्द गया था। जो लड़के वहां 10+2 के बाद फर्स्ट ईयर में ऐडमिशन लेने के लिए गए, उन में से कुछ लड़कों का ऐडमिशन करके यह कहकर आगे एडमिशन बन्द कर दिया गया कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। यह हालात सफीदों के कालेज की है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : यदि हाउस की सैन्स हो तो हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री सभापति : हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री रामफल कुण्डू : सभापति जी, मैं गवर्नमैंट कालेज, सफीदों में गया तो वहां मुझे यह कहा गया कि अगर आप लिख कर दें कि आप यहां पर लैक्चरर भिजवा देंगे तो हम बच्चों का ऐडमिशन कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहां पर लैक्चरर भिजवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे इस तरह कहने के बावजूद भी लड़कों को ऐडमिशन नहीं दिया। फिर मैं दोबारा वहां गया तो फिर वे कहने लगे कि अगर आपके अपने हल्के के दो चार लड़के हैं तो बता दें हम उनका ऐडमिशन कर देंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लड़के पढ़ना चाहते हैं उनको ऐडमिशन जरूर मिलना चाहिए और जो लड़के ऐडमिशन से वंचित रह गए हैं उनके लिए ऐडमिशन की डेट बढ़नी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को ऐडमिशन जरूर मिलना चाहिए। सभापति जी, अब मैं सड़कों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जामनी अड्डे से पीलूखेड़ा मंडी तक की सड़क की वाइडनिंग जरूर होनी चाहिए क्योंकि उस सड़क पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड रहता है और उस सड़क पर देहात के लोगों का बहुत आना जाना रहता है। इसी तरह से सफीदों से ले कर हाट गांव तक जो कम से कम 10-12 लिंक रोड जाते हैं, उस सड़क के बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस सड़क की भी वाइडनिंग होनी चाहिए। जो शहर के अन्दर सड़कें हैं उनको बार-बार अनुरोध करने के बाद भी ठीक नहीं किया गया है। चाहे वे सड़क पीलूखेड़ा मंडी में हैं और चाहे सफीदों मंडी में हैं। उन मंडियों की सड़कों के बारे में मैंने यह रिक्वैस्ट की थी कि उन पर कच्चा रोड़ा डाल दिया जाए ताकि वे सड़कें चलने योग्य हो जाएं। मेरा अनुरोध है कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। जो लिंक रोड हैं उन पर पैच लगा देते हैं यह पता नहीं लगता कि वह पैच मिट्टी से लगता है या बजरी से लगता है या रोड़े से लगता है। महकमे वाले सड़कों पर मिट्टी डाल जाते हैं और उसका जवाब आता है कि पैच लगा दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन सड़कों की जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए। अब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि खातला से नीकलाबाद और डउबाना से मलिकपुर जो मार्किट कमेटी की सड़क है वह अधूरी पड़ी है उस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। इसी प्रकार से पीलूखेड़ा मंडी से तलोडा गांव में एक 66 के०वी०ए० का पावर हाउस लगा हुआ है उसको 132 के०वी०ए० का अपग्रेड किया जाए। सभापति जी, कल मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर बिजली के बारे में काफी कुछ बताया था कि इतने ट्रांसफारमर्ज खरीदे जाएंगे, इतनी लाईनें चेंज की जाएंगी लेकिन उसमें जींद डिस्ट्रिक्ट का कोई जिक्र नहीं था कि उस जिले की कहीं कोई लाईन बदली जाएगी या नहीं वहां के लिए कोई ट्रांसफारमर खरीदा जाएगा या नहीं और न ही यह जिक्र किया गया कि वहां पर किसी पावर हाउस की अपग्रेडिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जींद जिले में बिजली देने का पूरा प्रबंध किया जाए क्योंकि जींद जिले के गांवों में तीन-तीन दिन और चार-चार दिन तक बिजली नहीं आती है। सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शूगर फैडरेशन ने एक फैसला लिया कि जींद शूगर मिल से साढ़े तीन करोड़ रुपए भूना शूगर मिल को दे दिए जाएं, लेकिन उस बारे में किसी सलेबान ग्रोवर भाम के आदमी ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया उसके बाद शूगर फैडरेशन ने फैसला लिया कि हम साढ़े तीन करोड़ रुपए वहां पर नहीं भेजेंगे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमैंट ने 11-7-98 को अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया कि हम हमारे क्रैडिट पर भूना शूगर मिल को यह लोन दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वह साढ़े तीन करोड़ रुपया जींद शूगर मिल से निकल गया तो वहां के कर्मचारियों के लिए और वहां के जमींदारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भूना शूगर मिल के लिए सरकार पैसे का किसी और सोर्स से प्रबंध करे और जींद शूगर मिल से वह पैसा न निकाले। मैं यह भी

कहना चाहूंगा कि पैसा भी किसी लिमिट के तहत वहां से निकाला जाएगा। लेकिन मुझे पता चला है कि वह पैसा जींद शूगर मिल को गिरवी रख कर वहां से निकाला जा रहा है, अगर सरकार ने इस मिल को गिरवी रख कर भूना शूगर मिल को पैसा देना है तो सरकार कोई और चीज गिरवी रख दे लेकिन जींद शूगर मिल को गिरवी न रखें। सभापति जी, हमारे जिले के जो मंत्री हैं उनका भी इस बारे में फर्ज बनता है क्योंकि वे भी कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं यह बात उनके ध्यान में भी आनी चाहिए थी। सभापति जी, अब मैं एक और बात सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। जब यह बजट सैशन होता है तो यह हमेशा फरवरी और मार्च के एंड में होता है इसलिए यह बजट सैशन फरवरी मार्च के एंड में चलना चाहिए था। आज कल तो मानसून सैशन होता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि आयंदा सरकार इस बात का ध्यान जरूर रखे। सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा जब मैं सफीदों के गवर्नमैंट कालेज में गया तो मुझे पता लगा कि जिस किसी लड़के का किसी एक सब्जैक्ट में कम्पार्टमैंट है और जो स्कूल से जाता है उसको तो एडमिशन मिल जाता है। जो लड़का प्लस टू के स्कूल में दो सब्जैक्टस में फेल हो जाता है उसको एडमिशन नहीं मिलता है लेकिन जो लड़का प्लस टू बोकेशनल करके जाता है तथा उसकी दो सब्जैक्टस में कम्पार्टमैंट होती है तो उसको एडमिशन दिया जाता है लेकिन स्कूल से गए हुए लड़के को जिसकी दो सब्जैक्टस में कम्पार्टमैंट होती है उसको फेल समझ लिया जाता है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए यह सुविधा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी होनी चाहिए या प्लस टू वाले बच्चे को भी यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए उनसे भी वापिस होनी चाहिए। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। मैंने इस बारे में सफीदों के लिए एक क्वैश्चन भी किया था। हमारा सफीदों शहर काफी पुराना शहर है और वहां पर जो सी०एच०सी० की बिल्डिंग है वह पुरानी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सी०एच०सी० को सामान्य हस्पताल में बदला जाये। वहां की आबादी भी 30-35 हजार है। वहां पर इस वक्त न पोस्टमार्टम की सुविधा है और न एक्स-रे मशीन है। मैं चाहूंगा कि सरकार वहां पर जरूरियात की सारी चीजें उपलब्ध करवाये।

सभापति महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। हमारे यहां पर तीन चार महीने पहले एक पटवारी और कानूनगो 4 लाख 65 हजार रुपया लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक मारुती कार में बदमाश आए और बन्दूक की नोक पर वह सारा पैसा छीन ले गए। यह वारदात पीलू खेड़ा की है। वहां पर उन लोगों के लिए किसी व्हीकल्ज की सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार उनको व्हीकल्ज उपलब्ध करवाये और साथ ही सिक्योरिटी का भी इन्तजाम करे। इसी प्रकार से इसी महीने पैंशन बांटने के लिए पैंशन बांटने वाले 1 लाख 15 हजार रुपया ला रहे थे वह भी छीन लिया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी गहराई में जाए और उनकी सुरक्षा व गाड़ी आदि की व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से सफीदों के अन्दर 4 करोड़ रुपये अब तक अनाज मण्डी बनाने पर खर्च हो चुके हैं। मेरी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवा कर चालू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश जैन (पानीपत) : सभापति महोदय, आपने डिमांड पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। पानीपत शहर एक प्राचीन शहर है। मेरी कान्स्टीच्यूएंशी पानीपत शहर है। यह एक औद्योगिक नगरी है। वहां से बड़ा भारी सामान एक्सपोर्ट होता है जिससे हमें फारेन एक्सचेंज प्राप्त होता है। वहां की म्यूनिस्पिल कमेटी से लोग काफी परेशान हैं। जिसकी वजह से पानीपत शहर का बहुत बुरा हाल है। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गन्दगी फैली हुई है।

[श्री ओम प्रकाश जैन]

वहां पर पानीपत म्यूनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन और उनके दूसरे साथी हैं उन्होंने पानीपत शहर की जमीन को लुटा दिया। इस कमेटी ने यह जमीन लुटाते समय किसी की परमिशन नहीं ली चाहे वह सरकार की हो, डी०सी० की हो या खुद रैज्योल्यूशन पास करके देने की हो, किसी की कोई एप्रूवल नहीं ली और न ही परमिशन ली। यह मामला वहां की प्रिवेंलिज कमेटी के सामने भी आया। वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने पौने चार सौ प्लाट जिनकी कीमत अरबों रुपयों में थी, मिट्टी के भाव बेच दिए। यदि वह इन प्लाटों को ठीक ढंग से बेचते तो म्यूनिसिपल कमेटी को अरबों रुपया प्राप्त होता जिससे वहां की डिवैल्पमैंट बहुत अच्छी तरह से हो सकती थी। उदाहरण के तौर पर मैं एक प्लाट का जिक्र करना चाहता हूं। यह प्लाट चावला नाम के एक व्यक्ति को सस्ते भाव पर दे दिया गया। इसको देने से पहले न तो डी०सी० की परमिशन ली गई और न ही म्यूनिसिपल कमेटी ने स्वयं इसका रैज्योल्यूशन पास किया। इस तरह से प्लाट देने के मामले में वहां पर बहुत भारी अनियमितताएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करे। सभापति महोदय, पानीपत एक प्राचीन शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहां पर उद्योग ज्यादा होने की वजह से यह शहर पानीपत से काफी बाहर जाकर बस गया है, काफी बाहर तक फैल गया है। यहां से काफी माल बाहर भी भेजा जाता है इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि पानीपत शहर की जो म्यूनिसिपल कमेटी है उस कमेटी की सीमा बढ़ा दी जाये। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा बढ़ाने से कमेटी की इन्कम भी ज्यादा होगी और शहर का विकास भी होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा बढ़ा दी जाये। सभापति महोदय, पानीपत शहर में पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, पानी की जो पहली सतह है वह खराब हो चुकी है जिसके कारण वहां पानी की समस्या बहुत गम्भीर बनती जा रही है। सभापति महोदय, पिछली सरकार के वक्त में 8-10 ट्यूबवैल्ज एम०एल०ए० और एम०पी० की ग्रांट से वहां लगे थे। ट्यूबवैल्ज लगा तो दिये लेकिन उनको चालू नहीं किया गया। सभापति महोदय, वे ट्यूबवैल्ज चुनाव के वक्त लगाये गये थे, लेकिन बाद में उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, इस बारे में भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन ट्यूबवैल्ज को चालू करायें ताकि पानीपत के लोगों को पीने का पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि वे पानीपत की कुछ बस्तियों में नये ट्यूबवैल्ज लगवा दें और पीने के पानी का प्रबंध करें वरना पानीपत शहर का पीने के पानी के मामले में बुरा हाल हो जायेगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे पानीपत शहर में जी०टी० रोड पर एक हस्पताल है लेकिन उस हस्पताल की चार दीवारी टूटी हुई है जिसके कारण कुछ लोग वहां पर जबरन कब्जा करने में लगे हुए हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उस हस्पताल की चार दीवारी बनवा दी जाये ताकि कम से कम उस हस्पताल की जमीन की तो रक्षा हो सके। सभापति महोदय, पानीपत शहर में पानीपत रैस्ट हाउस के सामने एक पुल है, वह पुल बहुत तंग है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए उस पुल को दो तरफा बनाया जाये ताकि वहां से लोग आसानी से गुजर सकें और एक्सीडेंट्स भी न हों। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सरकार पानीपत में मिनी सचिवालय बनाना चाहती है, लेकिन जहां पर सरकार जमीन लेना चाहती है वह जमीन डिफैंस मिनिस्ट्री की है। जब तक डिफैंस मिनिस्ट्री से वह जमीन नहीं मिलेगी तब तक पानीपत में मिनी सचिवालय नहीं बन सकता। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सचिवालय के लिए सैक्टर-11 या सैक्टर-17 में जमीन ले लें और वहां पर यह सचिवालय बनवा दें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि पानीपत में मिनी सैक्रेटेरियेट जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अगर वहां पर जगह नहीं मिल पा रही है तो हुड्डा ने

जो जमीन छोड़ी हुई है उसको ले लिया जाए ताकि डी०सी०, तहसीलदार या दूसरे अफसरों के जो दफ्तर अभी तक अलग-अलग जगह पर हैं वे सब एक ही छत के नीचे इकट्ठे काम कर सकें और लोगों को अपने काम करवाने के लिए कुछ राहत मिले। मिनी सैक्रेटेरियेट के इलावा हमारे यहां फलाई ओवर बनाने की भी मांग थी परन्तु मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर फिलहाल फलाई ओवर नहीं बन सकता है। मैं यह चाहूंगा कि वहां पर जो बाईपास बनाया जाना है उस बाईपास के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दिया जाए। सभापति महोदय, आपने मेरी डिमाण्डज़ को सुना (विघ्न) सभापति महोदय, आज जो हमारे मुख्य मन्त्री हैं उन्होंने किसी भी एम०एल०ए० के कहने पर एक भी क्लर्क या चपड़ासी की भर्ती नहीं की, कोई सिपाही की भी भर्ती नहीं की है। जो भी क्लर्क, चपड़ासी या सिपाही भर्ती हुए हैं वे सब मैरिट के आधार पर सिलैक्ट हुए हैं किसी की सिफारिश पर उनका सिलैक्शन नहीं हुआ है। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। (विघ्न) **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)**

श्री कृष्ण लाल (असन्ध, एस०सी०) : उपाध्यक्ष महोदय, हविपा और भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब अढ़ाई वर्ष के बाद आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर 1 से लेकर 25 पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पावर के बारे में बोलना चाहूंगा। हविपा भाजपा सरकार बनने से पूर्व खासतौर से हविपा ने चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं कि हमारी सरकार आने के बाद 24 घण्टे गांवों को बिजली मिलेगी, 24 घण्टे में बिजली का कनैक्शन मिलेगा, 24 घण्टे में ट्रांसफारमर रिप्लेस किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसान की क्या हालत है यह इस सरकार को ठीक प्रकार से पता है लेकिन सरकार वास्तविक तथ्यों को छिपाती है ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ट्रांसफारमर जल जाता है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जाता है। इस बारे में बिजली बोर्ड का कोई सर्कुलर नहीं है लेकिन अगर एक ट्रांसफारमर पर 10 किसान आते हैं और उनमें से 2 ने बिल जमा नहीं कराया तो उन बाकी के आठ किसानों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि वे मजबूर करते हैं कि उनसे बिल भरवाया जाए और जब तक बिल भरवाया नहीं जाता तब तक ट्रांसफारमर रिप्लेस नहीं होता है। क्या मुख्यमंत्री जी इस स्थिति में कोई सुधार करेंगे ?**(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से मुझे भी इस बार बोलने का मौका मिला है (विघ्न) मेरा नाम तो रोज ही लिस्ट में होता था लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आज जो बोलने का समय मिला है उसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब तक 10 के 10 किसानों का बिजली का बिल जमा न हो जाए तब तक उनको नया ट्रांसफारमर नहीं दिया जाता है। दूसरी बात स्पीकर साहब, डोमैस्टिक सप्लाई और कमर्शियल सप्लाई की है। रेट के बारे में चौधरी देवी लाल के समय में चार स्लैब प्रणाली चालू की गई थी। स्लैब प्रणाली में 1 से 40 यूनिट तक बिजली के चार्जिज 52 पैसा प्रति यूनिट, 41 से 80 यूनिट तक 62 पैसे प्रति यूनिट, 81 से 140 यूनिट तक 75 पैसे प्रति यूनिट और 140 से ऊपर एक रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी कल कह रहे थे कि उन्होंने 6 लाख ऐसे बिजली कन्ज्यूमर्ज़ का पता लगाया है जिनको सरकार एक से चालीस यूनिट तक बिजली कम रेट पर सप्लाई करेगी। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा कौन सा सर्वे करवाया है ? अध्यक्ष महोदय, अगर दो बल्ब और एक पंखा चले तो ये 40 यूनिट्स 10-12 दिन में ही कन्ज्यूम हो जाते हैं सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वह बिल्कुल ही गलत दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या वह आदमी 10-12 दिन के बाद अपना मीटर बंद करेगा ? वैसे तो हरियाणा में बिजली आती ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज हविपा और भाजपा गठबन्धन वाली सरकार

[श्री कृष्ण लाल]

हो, हमारे से पहले और अब तक 15-20 सालों में किसी ने भी बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया है। मैं यह रिकार्ड की बात बता रहा हूं। 1997 में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। तब ही पानीपत के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट नम्बर 1 और 2 का काम शुरू हुआ था और 1979 के अन्दर इन यूनिट्स ने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी ने आकर के पानीपत के थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का उद्घाटन किया था। कुछ समय के बाद दूसरे यूनिट ने भी प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार से वहां का जो पांचवां यूनिट है उसका 1987 में काम शुरू हुआ था। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने खुद माना है कि अगर कोई प्लांट का काम शुरू हो तो उसको कम्पलीट होने में तीन साल लग जाते हैं। 1987 में वह काम शुरू हुआ था और 1990 में उस प्लांट ने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। यह रिकार्ड की बात है कि उस टाईम के इम्पलाईज को इन्सैंटिव भी मिला था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक छठे यूनिट की बात है, इसके लिए 1989 में चौधरी देवी लाल जी के समय में 159.6 करोड़ रुपए के वर्क के आर्डर किए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने जवाब में भी इस बात को माना है कि 80 करोड़ रुपए का सामान आ चुका था और वह रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। हमारी सरकार के जाने के बाद कांग्रेस की जो भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आई थी उस ने उस सामान को नहीं छुड़वाया। उस पर डैमरेज पड़ता रहा। उसके बाद उसके रख-रखाव के लिए बी०एच०ई०एल० ने दो करोड़ रुपए मांगे थे। अध्यक्ष महोदय, वह सामान डैमेज हो जाएगा। कुछ सामान मिट्टी में पड़ा है और कुछ रेलवे स्टेशन पर पड़ा है। लेकिन उस सरकार ने उस सामान को नहीं छुड़वाया था। अध्यक्ष महोदय, छठे यूनिट का काम 100 प्रतिशत शुरू हो गया था। आज यह सरकार केवल वहां से पानी निकलवा रही है। स्पीकर साहब, इतना ही नहीं चौधरी देवी लाल जी ने अपने शासनकाल में जितने भी बिजली के उपभोक्ता थे,उनको 24 घंटे बिजली दी थी। लेकिन इस जनाब की सरकार के वक्त में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बिजली का निजीकरण करने की बात आई। एच०वी०पी० और बी०जे०पी० की सरकार इसके लिए दोषी है। वैसे इसके लिए कांग्रेस की सरकार भी दोषी है। 1993 के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने नीरा नाम की अमरीकन कम्पनी को दो करोड़ रुपए देकर इस बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई थी। बिजली का निजीकरण कांग्रेस पार्टी भी करना चाहती थी और इसके बाद इस सरकार ने भी बिजली का निजीकरण किया है जो कि प्रदेश के हित में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद चाईना से 5 लाख बिजली के मीटर मंगवाए गए। ये मीटर घरों में लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बिजली बोर्ड की वर्कशाप में बहुत से मीटर पड़े हुए हैं लेकिन इन्होंने चाईना से मीटर मंगवाने पर पैसा खर्च किया है उस पैसे से वर्कशाप में पड़े मीटरों को रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो मौका देखती है कि किस कम्पनी से पैसा मिल सकता है और कहां-कहां से पैसा मिल सकता है ताकि उसके साथ सौदा किया जा सके। अब मैं पी०डब्ल्यू०डी० की बात करना चाहता हूं। मेरा असंध हल्का है वहां पर 1993 में भी और 1995 में भी फ्लड आया था। दोनों बार मेरा हल्का फ्लड की वजह से अफैक्टिड हुआ था। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में हम और आप अपोजिशन में बैठते थे। हमने पूरे सब्बके मार-मार कर अपनी बात कही थी लेकिन उस वक्त भजन लाल जी ने हमारी बात नहीं सुनी और इसी तरह से आज हविपा और भाजपा की सरकार भी हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अध्यक्ष महोदय, 1993 और 1995 में दो बार फ्लड आने के कारण आज तक मेरे हल्के में जितनी भी रोड्ज टूटी हुई थीं, वे रिपेयर नहीं हुई हैं। सरकार यह बताए कि मेरे हल्के में नई सड़कें और जिन सड़कों पर पैच वर्क किया है, उन पर अब तक कितना पैसा खर्च किया गया है ? स्पीकर साहब, असंध एक सब-डिविजन है सरकार इस बारे

में सर्वे करवाएं । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां की सड़कों को ध्यान में रखकर उनकी रिपेयर करवाए। स्पीकर सर, एक समय वह था जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और यदि उस समय ओलावृष्टि होती थी तो किसान से पहले चौधरी देवीलाल उसके खेत में नजर आते थे और एकदम घोषणा कर देते थे कि इतना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह स्पीकर सर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। असन्ध में जो कि सब डिवीजन है, न ही कोई 10+2 का स्कूल है और न ही वहां पर कोई कालिज है, न ही वहां पर कोई पोलिटैक्निक कालेज है। वहां पर सब डिवीजन होते हुए भी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार ने पहले कहा था कि अगर आप वहां पर जमीन उपलब्ध करवा दें और दो तीन कमरे बनाकर दे दें तो हम वहां कालेज खोलने की मंजूरी दे देंगे। लेकिन हम तो जमीन देने के साथ-साथ कालेज की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भी देना चाहते हैं इसलिए अब सरकार को वहां कालेज मंजूर कर देना चाहिए। स्पीकर सर, मतलौडा मेरा गांव है लेकिन वहां पर भी बीस कि०मी० तक कोई स्कूल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप अढाई एकड़ जमीन दे दें और दो कमरे बनाकर दे दें तो हम वहां के स्कूल को अपग्रेड कर देंगे। हम सरकार को जमीन भी देने को तैयार हैं और चार कमरे भी बनाकर देने के लिए तैयार हैं लेकिन आज तक भी सरकार की तरफ से कोई जवाब इस बारे में नहीं आया है। इसके अलावा मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के के अंदर उटना, लोहरी, आसन कलां आदि गांवों में एक बार बारिश का पानी क्लाक हुआ था तब वहां सैंट परसैंट फसल खराब हो गयी थी। उस समय इन्होंने पम्प तो लगवाए थे लेकिन चार पांच ड्रेनें ऐसी हैं जिनकी सफाई नहीं हुई। ये ड्रेनें बारिश के समय ओवर फलो हो जाती हैं। इन गांवों में पूरी कनक की फसल बर्बाद हो गयी थी और बिजाई भी नहीं हुई थी। कंवल सिंह जी, जो ग्रीवैंसिज कमेटी के चेयरमैन थे, के सामने लोग पेश हुए थे और उन्होंने यह समस्या इनके सामने रखी थी तब इन्होंने इरीगेशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों को आदेश दिया था कि इन ड्रेनों की सफाई करवायी जाए। लेकिन इनके कहने के बावजूद भी उनकी सफाई नहीं हुई। स्पीकर सर, मंत्री जी आदेश दें और फिर भी काम न हो तो फिर कैसे किसानों का काम चलेगा ? इनके आदेश के बाद भी डिपार्टमैंट ने वह काम नहीं किया। स्पीकर सर, अब मैं वन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। वन विभाग के अंदर बहुत धांधलियां हुई हैं। जब सरकार प्लांटेशन की बात करती है तो डिपार्टमैंट वाले क्या करते हैं कि प्लांटेशन करने के लिए जो अढाई या तीन फुट गड्ढे खोदने चाहिएं, उनके बजाए वे आधा फुट ही गड्ढे खोदते हैं। इन गड्ढों में 19 किलो मैटीरियल जैसे गोबर आदि आना चाहिए लेकिन वे इतना मैटीरियल नहीं डालते हैं और ऐसे ही प्लांटेशन करते हैं। विजेन्द्र सिंह जी के हल्के का एक गांव आसन कलां है वहां पर 1400 एकड़ पंचायत की जमीन है। उस गांव के लोगों ने करीब 500 या 600 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां पर 400 एकड़ जमीन पर प्लांटेशन हुई थी लेकिन उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। वहां एक रफूते के अंदर ही 500 या 600 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। स्पीकर सर, पूरे प्रदेश के अंदर ही ऐसा हाल है। मैं मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उनको इस प्रकार के नाजायज कब्जों को तुरन्त रोकना चाहिए। सर, इसी तरह से मैं अब स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। इस विभाग का भी बहुत बुरा हाल है। सारे प्रदेश में पी०एच०सीज० या सी०एच०सीज० का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। मेरे गांव के अंदर ही एक पी०एच०सी० है। सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि उसकी चारदीवारी और उसके अंदर मिट्टी भर दी जाएगी लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से बारिश के दिनों में वहां पर पानी भर जाता है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से जो रूरल एरियाज के अंदर पी०एच०सी० या सी०एच०सी० हैं वहां पर पूरे प्रदेश में कोई भी लेडी डाक्टर नहीं है। अगर इनमें दूसरे डाक्टर्ज भी हैं तो वे वहां जाते नहीं हैं इसलिए मंत्री जी को इस बारे में तुरन्त

[श्री कृष्ण लाल]
ध्यान देना चाहिए। सर, अगर आप चाहें तो पूरे प्रदेश में इस बारे में सर्वे करवा लें कि क्या कोई डाक्टर हैडक्वार्टर मेनटेन करता है या नहीं ? गांववासियों को इससे बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसके बारे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह आवश्यक कार्यवाही करे। (विघ्न) दूसरी बात मैं परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। जो रोडवेज के रूट्स पहले चलते थे, वे प्राइवेटाइज़ेशन करने के बाद बंद कर दिए गए हैं। बाद में इन रूटों पर प्राइवेट बस चलती थीं। प्राइवेट ओपरेटर जितने पैसे कवर करना चाहते थे, वे कर नहीं पाए तो अपनी मर्जी से उन्होंने रूट चेंज कर लिए। अब रोडवेज वाले कह रहे हैं कि वहां प्राइवेट बसें चल रही हैं इसलिए हम इन रूट्स पर बसें नहीं चला सकते। इससे सवारियों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप कोई ऐसे रूट्स बताएं जहां पहले रोडवेज की बसें चलती थीं और प्राइवेटाइज़ेशन के बाद वह बंद हो गई हों ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, एक रूट पर तो जनरली ऐसी शिकायत है।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, छोटे-छोटे रूट्स पर तो ऐसा आम हो रहा है। इससे सवारियों को बड़ी भारी दिक्कत है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कानून में यदि इस तरह की कोई कमी है तो उसके लिए ये अमैंडमैंट लेकर आएं। इससे लोगों को बड़ी परेशानी है। वह रूट जो 25-25 किलोमीटर वाइटल प्वाइंट पर जाकर मिलते हैं वहां से उन्होंने अपनी बसें विदड्रा कर लीं। वहां पर अब कोई बस चला नहीं सकता क्योंकि कोर्ट ने इस बारे में स्टे दिया है इससे लोगों को परेशानी हो रही है।

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक) : यह कब से है ?

श्री धीरपाल सिंह : यह लास्ट ईयर से है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, अब मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंन्ट के बारे में कहना चाहूंगा। हाउस में हर रोज पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर की ओर से यह कहा जाता है कि हर एक गांव में पीने के पानी का कनैक्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूनक खेड़ी मेरे हल्के का एक गांव है वहां आज तक वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है। इसी प्रकार से डेरा फूला सिंह, डेरा गुजराखियां, डेरा पंढोरिया जोकि सिखों के डेरे हैं, यहां भी वाटर सप्लाई के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। जो पानी ये दे रहे हैं उसके भी हमने कई गांवों के सैम्पल भरे हैं। उसमें पाया गया है कि पानी चाहे कैनाल से आता है या पम्प से आता है उसमें ये डोजिंग पम्प नहीं लगाते जबकि इनको डोजिंग करनी चाहिए क्योंकि यह प्रदेश के लोगों की लाइफ का सवाल है। जितने भी वाटर वर्क्स हैं वहां डोजिंग पम्प काम करने चाहिएं ताकि लोगों को पीने का पानी अच्छा मिल सके। (घण्टी) अब मैं सहकारिता विभाग के बारे में कहना चाहता हूं जो कि आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा विभाग है। मेरे से पहले बोलने वाले साथी ने कहा था कि एम०सी०एल० बनने के बाद चाहे किसान हैं या गरीब आदमी हैं जो एप्रोच करवा लेते हैं उनको तो लोन मिल जाता है दूसरों को नहीं मिलता है इसलिए इस पर सहकारिता मंत्री विशेष ध्यान दें। इसे आम लोग शिकायत करते हैं वह बहुत भारी समस्या है इसको सीरियसली लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की

15.00 बजे बात है, मेरे हल्के के एक मंगलराम नाम के आढ़ती से थाने से 100 मीटर की दूरी पर 85 हजार रुपये दो मोटर साईकल सवारों ने छीन लिये। आज तक पुलिस द्वारा उनको पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार एक वकील श्री सतपाल त्यागी की कार छीन ली गई जिसका आज तक कोई अता-पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत एक औद्योगिक नगर है जिसके साथ यू०पी० का एरिया लगता है। पानीपत शहर में माल को लाने ले जाने के लिए बाहर से लोग आते जाते हैं क्योंकि पानीपत में हैंडलूम का काम काफी मात्रा में होता है जिसका एक्सपोर्ट भी होता है। इस प्रकार की वारदातें पानीपत शहर में काफी मात्रा में होती है। समाचार-पत्रों में भी आपको सप्ताह में दो चार वारदातें पानीपत की ही मिलेंगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पानीपत शहर की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाये ताकि व्यापारी लोग अपना धन्धा ठीक प्रकार से कर सकें। धन्यवाद।

श्री रेलूराम : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने का समय दें।

श्री अध्यक्ष : रेलूराम जी बैठिये, मैंने सभी सदस्यों को आश्वासन दिया था कि जिस भी माननीय सदस्य को बोलने के लिए समय नहीं मिला है, उनको बोलने के लिए समय अवश्य दिया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended for one hour.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Time of the sitting is extended for one hour.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार ने ये प्राईवेट बसों के रूट्स परमिट दिए थे। उनमें से कुछ ऐसे रूट्स है जिन पर लोगों को दिक्कतें हैं, परिवहन मंत्री यह इंश्योर करायें कि जो प्राईवेट रूट्स दिए हुये हैं यदि प्राईवेट बसें वहां पर नहीं चलती हैं तो उनके परमिट कैंसिल किये जायें तथा वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जायें ताकि वहां के लोगों को कोई दिक्कत न हो।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : जैसी कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की जिज्ञासा है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कैबिनेट ने एक सब-कमेटी बनाई हुई है जिसमें चौधरी मनीराम गोदारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मैं भी उस सब कमेटी में हूं। हमने काफी एक्सर्साइज की है और जो सुझाव चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने दिये हैं, उनको भी हम एग्जामिन कर लेंगे तथा जो भी इंकार्पोरेट होगा वह हम अवश्य करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेकर आये और सारे मुद्दे उसमें होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, इस बारे में सब-कमेटी बनी हुई है और उसमें सारी बातें एग्जामिन हो रही हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्टेट सब्जैक्ट है इस पर तो सरकार अपनी पोलिसी लेकर आ सकती है कि प्राईवेटाईजेशन की क्या पोजीशन है, कितने रूटों का निजीकरण करेंगे, कितने रूटों को छोड़ेंगे ताकि लोग कोर्टस् में न जायें। लोग कोर्टस् में इसलिए जाते हैं कि उनके परमिट कैंसिल न हों। लेकिन इन बातों ने लोगों को परेशानी में जरूर डाल रखा है। इम्पोर्टेंट रूट्स पर तो बसें चलती नहीं हैं।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सब कमेटी बनी हुई है वह सभी बातों को ध्यान में रखकर रूटों के मामले को एग्जामिन कर रही है और जो भी सब कमेटी की रिपोर्ट होगी वह इस एक महीने के अन्दर इस महान सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, कुछ रूट्स खाली पड़े हुये हैं वहां पर प्राईवेट बसों वाले नहीं चलते जिसके कारण सुबह और शाम स्कूली बच्चों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बसें सुबह और शाम चलाई जायें ताकि बच्चों को आने-जाने में तकलीफ न हो।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि प्राईवेट रूट्स वालों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है, इसलिए उन रूट्स पर रोडवेज की बसें नहीं चलाई जा सकती हैं।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत (घेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 की बजट अनुदान मांग सं० 2 से लेकर 25 पर बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने के लिए 15 मिनट मिलेंगे।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा नहीं तो मैं 6 दिन से यहां पर बैठा हुआ हूं और बोला नहीं हूं। सर, सबसे पहले तो मैं बिजली के बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे कि कल मंत्री महोदय ने बताया कि बिजली का हम ने काफी सुधार किया है। जहां तक बिजली के सुधार की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई लोन देने वाली कंपनी इस सुधार को बताती है, या सरकार की प्रशंसा करती है तो इससे बड़ी बात सरकार के लिए नहीं हो सकती है। किसी प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी करके ही किसी लोन देने वाली संस्था को खुश किया जा सकता है। इसलिए इस बात से जाहिर हो जाता है कि बजट के अंदर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वे जनहित में नहीं हैं तथा जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये प्रशंसा करने वाले अगर गांव में जाकर इन लोगों की प्रशंसा करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि न तो प्रशंसा करने वाले और न ही सरकार के ये आदमी वहां से सुरक्षित वापिस आ सकते हैं क्योंकि बिजली का गांवों में इतना बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बजट नहीं बल्कि कर्जों का लेखा-जोखा है। इसमें कम से कम यह तो बताया जाना चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश की जनता पर कितने करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाया गया है और प्रतिदिन उन्हें कितने करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। यह भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार सिर्फ कर्जे लिए जा रही है और इन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इस बारे में बजट में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। जिस हिसाब से कर्जे लेकर यह सरकार खुश हो रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि यह वर्ष 1998-99 का बजट नहीं है बल्कि यह आने वाले उन सभी सालों का बजट है, जब तक यह सरकार रहेगी। सरकार अंतरराष्ट्रीय एजैंसीज की शर्तें बेधड़क होकर

मान रही है। अगर ऐसा होता रहा तो यह वास्तविक बजट न होकर उन लोन देने वाली एजैंसीज का बजट ही कहा जाएगा। इस बजट में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दो सालों से नौजवानों को बहकाया गया। जिस वक्त प्रदेश में शराबबंदी लागू थी तो लोगों को शराब की स्मगलिंग करके पैसा कमाने की छूट दे रखी थी। वह अब बंद तो हो गई है लेकिन आज उन लोगों के पास हथियार भी हो गए हैं और पैसा भी हो गया है। आज उनकी वह नाजायज आमदनी बंद हो गई है। आज सभी पढ़े-लिखे नौजवान अपराध कर रहे हैं। अगर पढ़े-लिखे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा ? वह पढ़ा लिखा है, ताकतवर है, उस में जोश भी है। वह सरकार की कमियों के कारण दुःखी होना पसंद नहीं करेगा बल्कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वह चोरी करेगा, डाका डालेगा, कत्ल करेगा और दूसरे सभी अपराध करेगा। इसलिए सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इन अपराधों को रोके। आज नौजवानों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की बात तो दूर रही, जो रोजगार के पुराने साधन थे, उन में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जहां तक अध्यापकों की बात है, आज प्रदेश में 6500 के करीब तदर्थ अध्यापक लगे हुए हैं। 1988, 1991, 1994 व 1996 में जिन कर्मचारियों की दो साल की सर्विस हो गई थी, उन की सर्विस नियमित कर दी गई थी लेकिन आज इन अध्यापकों को नियमित न करके उनकी छुट्टी की जा रही है। कुछ कला अध्यापकों को हटाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि एक तरफ तो अध्यापकों को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ नए अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। ये जितने अध्यापक पहले लगे हुए हैं उनकी योग्यता आवश्यकता से अधिक होने पर भी उनको रैगुलर नहीं किया जाता बल्कि ये नए अध्यापकों की भर्ती की बात करते हैं। इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं, सरकार की नियत ठीक नहीं है। इस लिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, उसी तरह दूसरी भर्तियों में भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर चारों तरफ आग लगी हुई है। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, व्यापारी परेशान हैं और सारे के सारे कर्मचारी आन्दोलनरत हैं लेकिन सरकार खुश होकर, चुटकी ले लेकर यह कह रही है कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। आज तक पूरा प्रदेश जल रहा है और ये हंस रहे हैं तथा विपक्ष के विरोधी सदस्यों के ऊपर ताने कस रहे हैं। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह जो वित्त मंत्री की बजट स्पीच है इस में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उनमें काफी फर्क है। इस हाउस के अन्दर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के हित में न लेकर ऐसे ढंग से लिया जाता है कि एक-एक करके हर नेता सत्ता का गुलाम बनता जा रहा है। यह सरकार कोई जनहित के कार्य नहीं कर रही है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। जहां तक किसानों की बात है, सरकार ने खुद माना है कि नवम्बर, दिसम्बर 1997 और जनवरी 1998 में 111.57 लाख टन अनाज पैदा किया गया। बरसात के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थीं पंजाब सरकार ने उन किसानों को फसलें खराब होने का मुआवजा दिया। दिल्ली में भी इसी तरह का मुआवजा किसानों को दिया गया लेकिन हरियाणा सरकार ने एक नया पैसा भी नहीं दिया। हरियाणा का किसान कहां जाए ? जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वह निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जो देश के सारे संसाधनों को निगलती जा रही है वह है जनसंख्या वृद्धि की। इस बजट के अन्दर जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने समय की हाई कमान को खुश करने के लिए, इन्दिरा गांधी को खुश करने के लिए इस प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करवाए लेकिन उसके बाद हटकर इन्होंने दोबारा ऐसा काम करने का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि वह मुद्दा गलत था। वह मुद्दा ठीक

[डॉ०बीरेन्द्र पाल अहलावत]

था। समस्या उस समय भी थी और आज समस्या उससे भी ज्यादा बढ़ी हुई है लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने बजट में भी इसके लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वह सरकार के संरक्षण में पनपता जा रहा है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां मुख्यमंत्री को एफीडैविट दिया गया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आयुर्वैदिक विभाग में वहां के डाक्टर ने बंगलौर बेस्ड फर्म से पेटेण्ट मैन नामक दवाईयां 25 लाख रु० की खरीदी। जबकि यह परम्परा रही है कि यह दवाई मुश्किल से 10 प्रतिशत खरीदी जाती है। वर्ष 80 लाख रुपये की दवाईयां खरीदी गई, 34 लाख रुपये की दवाईयां खरीदी गई जिसमें से 25 लाख रुपये की डायाफोन नामक दवाई खरीदी गई जो कि डायरिया और डायसैन्टरी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। उस बारे में एफेडेविट देने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उस कम्पनी ने स्पष्ट लिखा है कि :—

"The medicine having the same component and in same quantity, I am ready to supply to your department on 8 lacs rupees only which is less than 16 lacs."

He further stated—

"(a) Whether this medicine has been demanded by Govt. Ayurvedic College Hospital or Ayurvedic Dispensaries functioning in the State of Haryana.

(b) Whether the ratio of Diarrhoea and other diseases patients of 1997 has been collected before sending the proposal to the Govt. for the purchase of this particular medicine in such a huge quantity being used to cure only Diarrhoea patient.

(c) That 1/3 of the total budget has been spent i.e. 24 lacs, to purchase this medicine and how to provide the other medicines to cure the patients of other diseases in the State.

(d) In the year 1996-97 the medicine to cure the Diarrhoea and Dysentery was purchased only with the cost of less than one lac whereas now spent the 25 times more money on the medicines of this disease without any justification.

(e) That the medicines namely DIACONE had never been purchased by the department. Now which circumstances has compelled to purchase such a huge quantity of this medicine at one time which has never been used before this year by the department."

स्पीकर साहब, इसके अलावा नशाविमुक्ति कैपसूल और टेबलेट्स खरीदे गए। उनके बारे में भी सरकार इन्कवायरी कराए। नशाविमुक्ति कैपसूल और टेबलेट्स पांच लाख रुपए के खरीदे गए लेकिन ये चार पांच गुणा ज्यादा रेट पर खरीदे गए। इनको खरीदने के लिए जो लोएस्ट रेट कोट किया गया था, वह 315 रुपए प्रति हजार कैपसूल और 135 रुपए प्रति हजार टेबलेट्स था लेकिन खरीदे गए 1080 रुपए प्रति हजार कैपसूल और 930 रुपए प्रति हजार टेबलेटस। इनके बारे में जिन चार पांच फर्म्ज का लोएस्ट रेट था, उसको इग्नोर करके ये दवाईयां खरीदी गईं। कहां 315 रुपए प्रति हजार के रेट का

कैपसूल और कहां 1080 रुपए प्रति हजार रेट का कैपसूल यानि 8-9 गुणा ज्यादा रेट दिए गए। इसी तरह से स्पीकर साहब, एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट में हर ब्लौक के अन्दर दवाईयां खरीदी गई हैं। एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट में दवाईयां खरीदने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की दवाईयों की कीमत के बारे में जो सैंक्शंड लिस्ट है और उन कम्पनीज की जो प्राइस लिस्ट है उनकी अनदेखी की गई है यानि एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट में 6-7 गुणा ज्यादा रेट पर दवाईयां खरीदी गई हैं। उस डिपार्टमैंट के हर ब्लौक के अन्दर हर ब्लौक के अधिकारियों द्वारा वे दवाईयां खरीदी गई हैं। इसलिए उस विभाग के हर ब्लौक के अन्दर करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। सरकार इस बारे में इन्कवायरी कराए।

अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा और खास करके अपने हल्के बेरी की सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। आज तक मैंने जितनी सड़कों की चर्चा की है उन सड़कों को बनवाने के बारे में मंत्री जी ने हां भरी है और कुछ सड़कों पर काम शुरू भी किया गया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस सड़क को बनाने का काम जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी दूसरी सड़क को बनाने का काम शुरू न किया जाए क्योंकि एक सड़क पर रोड़ी डाल दी जाती है और उसको छोड़ कर दूसरी सड़क का काम शुरू कर दिया जाता है। यदि किसी सड़क पर मिट्टी डालने का काम कर दिया है तो उसको पूरा करने से पहले ही दूसरी सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। अपने हल्के की बात कह रहा हूं। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। स्पीकर साहब, एच०आर०डी०एफ० ने गवर्नमैंट को प्रॉट लोन दिया था। उस पैसे से सरकार ने किसी भी अपोजीशन के विधायक के हल्के में आज तक कोई सड़क नहीं बनाई। उस पैसे से सारे के सारे काम सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के एरियाज में हुए हैं। हम किसी अधिकारी से जा कर किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वह अधिकारी कहता है कि आप तो विपक्ष के विधायक हो, इसलिए आपके इलाके में सड़क नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सरकार की तरफ से पर्वल हिदायतें हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं रेले-वैन्द ही बोल रहा हूं। (घंटी) मैं अपने हल्के की समस्या बता रहा हूं। नारवाई से सड़कें बनाने के लिए 22 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं। पता चला है कि इन 22 करोड़ रुपये से जो 25 सड़कें बननी हैं उनमें से अकेले 22 सड़कें भिवानी में बनायी जायेंगी। यदि यह सही बात है तो यह बिल्कुल गलत होगा। मैं चाहूंगा कि ये सड़कें सारे हरियाणा में बराबर बनाई जायें। अध्यक्ष महोदय अब मैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना चाहता हूं *********

Mr. Speaker : What is being said now by Shri Virender Pal is not to be recorded. Please take your seat, now ?

श्री रेलू राम (बरवाला) : स्पीकर साहब, इस दो साल के अरसे में मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जो भी बात कहूंगा, वह अन्दर की आयेगी, बाहर की नहीं आयेगी। अब तक पढ़े लिखे सदस्य बोले हैं। मैं तो अनपढ़ हूं लेकिन जो बात कहूंगा वह सही कहूंगा। यहां पर बोलते समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा के कुछ आदमी घरेलू झगड़ों की वजह से या जहरीला दवाई आदि खा कर मर गए। मैं यह बताना चाहता हूं कि वे मरे क्यों ? हमारी स्टेट में यह चीजें होती जा रही हैं। आज हमारी स्टेट में नौकरियों के लिए छोकरों से पैसे लिए जाते हैं। जो मंत्रियों के बर्कर हैं या जो उनके एजेंट हैं, वे गांवों में घूमते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम पैसों का प्रबन्ध कर लो हम नौकरी लगवा देंगे। गांव के लोग नौकरी के चक्कर में पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और अपनी औरत की दूम गिरवी रखते हैं। ऐसे काम करके पैसा लोगों ने दिया। कुछ तो नौकरी लग जायेंगे और कुछ रह

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रेलू राम]

जाएंगे। जो रह जायेंगे उनके बूढ़े बाप कहेंगे कि मैंने तेरे को पढ़ा-लिखा दिया और ब्याह दिया। एक आध किल्ला जो उसके हिस्से का आएगा दे देगा और कहेगा कि तु अब कमा और खा। लेकिन जिसके पैसे गए हैं वो उनको लेने के लिए इधर-उधर के चक्कर काटेगा। जिसको पैसे नहीं मिलेंगे वह अपनी बहू को कहेगा कि ला अपनी टूम दे दे मैं दिल्ली जाकर और नौकरी देख लूंगा। फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती। अब फिर वह आढ़ती की दुकान पर बैठता है। आढ़ती सोचता है कि चौधरी का लड़का आया है वह दो चार दिन उसको चाय पिलाएगा फिर उससे वह छुटकारा चाहता है। फिर वह लड़का किसी चाय की दुकान पर बैठेगा चाय वाला भी दो चार दिन सोचेगा कि यह तो रोजाना आकर बैठ जाता है। बेकार है, वह भी उससे पीछा छुड़वाना चाहेगा। उसके बाद वह वापिस घर आकर रहता है। वहां पर उसे थे सारी बात याद आती है तो फिर वह दुखी होकर या तो फांसी खाएगा या फिर जहर खा कर मर जाएगा या वह बीमार हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब वह जहर खा लेता है उसके बाद आस पड़ोस के लोग उसको डाक्टर के पास ले जाते हैं। डाक्टर से अपने लड़के का ईलाज करवाने के लिए किसान अपनी बची हुई जमीन को भी गिरवी रख देता है। किसान के सारे पैसे डाक्टर ले लेता है लेकिन उसका लड़का फिर भी मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, उस गरीब किसान के पास न तो अपनी जमीन रहती है और न ही लड़का। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी कहते थे कि हम 6 महीने के अंदर 24 घंटे बिजली दे देंगे। उसके बाद बिजली मंत्री ने भी कहा कि हम एक साल में पूरे हरियाणा प्रदेश को 24 घंटे बिजली दे देंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने उसके बाद फिर कहा कि हम दो साल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय आज तक हरियाणा में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजली अधिकारी बिजली के नकली बिल किसानों के पास भेजते हैं और जब किसान उनको ठीक करवाने के लिए उनके पास जाता है तब भी वे उनको ठीक नहीं करते। अगर कोई उनको पैसे दे देता है तब तो वे उसके ये बिल ठीक कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसान को अपना बिल ठीक करवाने में 2-3 दिन या इससे भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने दिन बिजली का बिल ठीक करवाने में किसान के लगते हैं उतने दिन के किसान को पैसे मिलने चाहिएं। सरकार को दिनों के हिसाब से किसान को पैसे देने का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि बिल में तो 100 रुपये, 200 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये ही कम होते हैं जबकि किसान के इस काम में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके 2-3 दिन का काम रुक जाता है जिससे उसको इससे कहीं ज्यादा नुक्सान होता है। अध्यक्ष महोदय, एक किसान अपने सिरी को 20 किलो बीज देता है और कहता है कि इस 20 किलो बीज की 20 किल्लों में बिजाई कर दो लेकिन वह सिरी 18 किलो बीज बेच देता है और केवल 2 किलो बीज की बिजाई 20 किल्लों में कर देता है। अध्यक्ष महोदय, अगर वह सिरी 2 किलो बीज 20 किल्लों में बिजेगा तो उन किल्लों में फसल नहीं उगेगी बल्कि घास उगेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव है कि यह सरकार भी उस सिरी की तरह काम कर रही है। उस पर 50 पैसे भी नहीं लगते हैं सारा पैसा खा जाते हैं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पर 3400 करोड़ रुपये का भार पड़ा है (घण्टी)

श्री अध्यक्ष : रेलू राम जी, अब आप बैठिये। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री रेलू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (घण्टी) एक बात मैं चौधरी जगन्नाथ जी के महकमें के बारे में भी कहना चाहूंगा (घण्टी) अगर इनके महकमें में कोई काम करवाना हो तो 2% जे०ई०, 2% एस०डी०ओ० और 2% एक्सीयन को दिया जाता है।

यह पैसा पूरा मिलेगा या नहीं, यह भी सरकार बताने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डिमाण्ड नं०-4 पर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सन् 1986 में जब मैं रैवन्यू मन्त्री था और चौधरी साहब मुख्य मन्त्री हुआ करते थे उस समय भी यह सोचा गया था कि किसानों के लिए पास बुक्स बनाई जाएं। 1991 में रैवन्यू डिपार्टमैंट फिर मेरे पास था। उस समय भी किसानों के लिए पास बुक का केस फिर शुरू हुआ था और पहली नवम्बर 1993 से रोहतक से इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना था लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस कारण से उस समय नहीं हो पाया। पास बुक बन जाने से किसानों को बहुत फायदा है। इसके होने से किसानों को गिरदावरी करवाने के लिए और फर्द के लिए बार-बार पटवारी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास बुक दिखा कर किसान को बैंक से लोन भी मिल सकेगा। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस पास बुक को किसानों के लिए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरे नम्बर पर मैं डिमाण्ड नं०-8 जो कि रोड्ज़ के बारे में है, बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का हरियाणा में सबसे बड़ा है जिसमें पिलखनी, इस्माइलपुर, दाभापुर धमतौर का 77 किलोमीटर का एरिया है। यहां पर करीब 350 किलोमीटर रोडज का जाल फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह एरिया फलुड एफैक्टिड ऐरिया है इसलिए जो रोडज़ बनाई जाती है वे हर साल टूट जाती हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि रोड्ज़ की रिपेयर के लिए इस हल्के में ज्यादा फण्डज़ दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, टांगरी नदी पर एक पुल बनना था, इस पुल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गई थी। इस पुल के बनने से पटियाला से ले कर हमारे एरिया तक बहुत बड़ा ऐरिया एक हो जाएगा। यह मेरे हल्के की सबसे बड़ी मांग है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एजूकेशन और उसके साथ ही स्पोर्ट्स के विषय पर भी बोलना चाहूंगा। हमारे पूरे हरियाणा में शहरों की बजाए गांवों में पढ़ाई का स्तर बहुत ही नीचा है और खास कर बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्ज का स्तर बहुत ही नीचा है। टीचर्ज को पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है जिसके कारण हरियाणा के बच्चे कम्पीटिशन्ज़ में पिछड़ते जा रहे हैं। जहां तक इस बारे में सरकार का ताल्लुक है, सरकार द्वारा टीचर्ज की जो पोस्टें खाली पड़ी हुई थीं, उनको भरने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और भी टीचर्ज की भर्ती की जाएगी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि टीचर्ज के स्तर की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बोलते हुए यह कहा था कि जब तक शिक्षा को टैलीविज़न से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि टैलीविज़न के माध्यम से शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पंचायत घरों में टैलीविज़न उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। टैलीविज़न के माध्यम से हमारे बच्चों को दुनिया और देश के बेहतरीन टीचर्ज से शिक्षा प्राप्त हो सकती है और बेहतरीन लैक्चरर्ज उनको उपलब्ध हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मन्त्री श्री राम विलास जी ने इस बात से मना कर दिया है कि बच्चों को पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। मेरी यह रिक्वैस्ट है कि पहली क्लास से अंग्रेजी शुरू की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है लेकिन आज पूरा विश्व अंग्रेजी के साथ जुड़ा हुआ है जब तक बच्चों को अंग्रेजी का पूरा ज्ञान नहीं होगा उनका नॉलेज अधूरा रहेगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा में हर प्रकार का नॉलेज और अच्छी बुक्स उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्पोर्ट्स पर कुछ कहना चाहूंगा। स्पोर्ट्स के हमारे पास जो शिक्षक हैं जिनको हमारी सरकार मोटी-मोटी तनख्वाह देती हैं, वे ग्राउन्ड में ही नहीं जाते हैं। हमारी सरकार को उनसे पूछना चाहिए कि वे कितने बच्चों को खेल-कूद की शिक्षा दे रहे हैं।

[श्री निर्मल सिंह]

इसके बाद मैं डिमाण्ड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिजली के स्लैब सिस्टम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा में बिजली का स्लैब सिस्टम लागू किया। मुख्यमंत्री जी सबको एक नजर से देखते हैं। इस स्लैब सिस्टम के बारे में विरोधी पक्ष के भाईयों को नाराजगी थी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : यह जो भागी राम जी ने कहा है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भेद-भाव किया जा रहा है। ये जो मर्जी कह लें। हम कुछ कहें तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार के भेदभाव की मिसाल देना चाहता हूं। हमारी गैलरी में तो पीने का गर्म पानी है और इनकी गैलरी में ठण्डा पानी है।

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, आप स्लिंग साईड की गैलरी से भी पानी पी सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्लैब सिस्टम लागू करने से कोई सरकार लोन नहीं माफ कर सकती है क्योंकि नाबार्ड, आर०बी०आई० और बाकी दूसरे बैंकर्स ऐतराज करते हैं। इस सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू करके किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। जहां पहले हमारे इलाके में किसानों को बिजली के बिल्ज के रूप में 13-13 सौ रुपए देने पड़ते थे वहीं अब उनको 400 रुपए ही देने पड़ेंगे। मुख्य मंत्री जी का यह एक बहुत ही सूझबूझ वाला कदम है। हमारे एरिया में जो ट्यूबवैल्ज हैं, वे 400-400 फुट गहरे हैं पहले इनका 600-600 रुपए का बिल आ जाता था। इस स्लैब प्रणाली के लागू होने से सढ़ौरा, अम्बाला और नारायणगढ़ के इलाके में किसानों को बहुत ही फायदा हुआ है। इस बारे में हमें भी पहले कंफ्यूजन था लेकिन अब नहीं है। स्पीकर सर, पहले ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट वालों ने पुराने स्लैब रेट उठाकर बिजली विभाग को दे दिए लेकिन चौधरी साहब ने आदेश कर दिए कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट वाले इस बारे में दोबारा सर्वे करें। स्पीकर सर, जब दोबारा सर्वे हो जाएगा तो अम्बाला के आसपास के लोगों को रियायत मिलनी शुरू हो जाएगी और यह रियायत लागू भी एक मई से होगी। जिन्होंने पहले फालतू बिल भरे हैं वह आगे कट जाएंगे। इसके लिए हम चौधरी साहब के बहुत ही आभारी हैं। स्पीकर सर, वैसे तो सरकार ने हमारे हल्के के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किया है और कई स्कीमज वहां के लिए बनायी हैं। हमारे यहां से एक नहर गुजरती है उसमें जब तक साईफन नहीं लगाया जाएगा तब तक पानी टांगड़ी नदी में नहीं गिरेगा। स्पीकर सर, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगी। हम चौधरी साहब के नोटिस में भी यह बात लेकर आए थे कि जो फलडज एफैक्टिड एरियाज हैं उनमें किसानों के लिए कोओपरेशन डिपार्टमैंट से तालमेल करके लम्बी अवधि के लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको आठ या दस साल तक की अवधि के लम्बे कर्जे देने चाहिएं ताकि उनका गुजारा चलता रहे। इसके साथ ही उनके खेतों में प्लांटेशन भी होनी चाहिए। ऐसा होने से उनको फल्ड से बचने में भी सहायता मिलेगी और उनके खाने-पीने का काम भी चलता रहेगा। जब आठ या दस साल के बाद यह प्लांटेशन कट जाएगी तो इससे उनको इंकम भी होगी और वे अपना लिया हुआ कर्जा भी लौटा सकेंगे। इसलिए इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से यहां पर एस०वाई०एल० कैनाल

** चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की चर्चा आयी थी। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० कैनाल हम हरियाणवीयों के लिए एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसके लिए हम सब पोलिटिकल पार्टीज को राजनीति से ऊपर उठकर कोशिश करनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमें कोई पोलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। स्पीकर सर, कोओपरेशन, ऐग्रीकल्चरल या फौरेस्ट डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। आज नये बीजों को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। ऐसे उन्नत किस्मों के बीज लाने चाहिएं ताकि पानी की भी खपत कम हो और पैदावार भी बढ़े। इसी तरह से प्लांटेशन को भी पूरे हरियाणा में बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे जमीन ताकतवर होती है और आमदनी भी ज्यादा होती है। स्पीकर सर, अम्बाला पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जहां से बहुत सारी नहरें गुजरती हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने नंगल इरीगेशन स्कीम अम्बाला जिले को दी। जब बरसात होती है तो फल्ड उस एरिया में बहुत नुकसान करती है। पहले वहां पर वैलो ट्यूबवैल्ज होते थे लेकिन वे अब खत्म हो चुके हैं इसलिए अब वहां पर पीने के पानी की भी समस्या है। इसके अलावा इरीगेशन के लिए भी वहां पर चार-चार सौ फुट नीचे से पानी निकालना पड़ता है। अब वहां पर दो या ढाई लाख रुपये ट्यूबवैल्ज के लिए चाहिएं। इसी तरह से टांगड़ी और मारकंडा नदी के पानी की भी बात वहां पर आयी थी। हम इनका पानी आज तक कंट्रोल नहीं कर सके हैं। इस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर कई जगह लिफ्ट करके बांटा जा सकता है और दो या ढाई महीने पानी की जरूरत पूरी की जा सकती है। आज भी टांगड़ी नदी में पानी चल रहा है लेकिन हम इसका कंट्रोल नहीं कर सके हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से एक मसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है जिसके लिए सरकार ने एक करोड़ रुपया तो दे दिया लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी पैसा भी इसके लिए मिलना चाहिए। यह 27 क्यूसिक की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है। मुझे पूरी आशा है कि यह स्कीम जल्दी ही पूरी हो जाएगी। स्पीकर सर, बिजली के बारे में हमारे विपक्ष के साथियों में जो कंफ्यूजन है उसको चौधरी साहब ने दूर करने की कोशिश की है। इनकी बात का सारे हरियाणवी विश्वास भी करते हैं। वे जानते हैं कि चौधरी साहब जिस बात को कहते हैं वह पूरी करते हैं। कल जो स्पीच चौधरी साहब ने दी और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो एक-एक आंकड़ा यहां हाउस में दिया, वह बहुत ही काबिले तारीफ था। इसके बाद उन्होंने सभी विपक्षी साथियों का कंफ्यूजन दूर कर दिया है। हमें आशा है कि इसके बाद अम्बाला जिले में भी एक या डेढ़ साल बाद पूरी बिजली आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्पीकर सर, आज वहां फ्रिक्वैन्सी और ट्रांसमिशन का सिस्टम कमजोर है। टेकड़ा और मोड़ा में दो बिजली घर सरकार ने बनाने मंजूर किए हैं मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको एक साल में ही कम्पलीट किया जाए ताकि आने वाले समय में वहां के लोगों को बिजली का सही रूप में फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, ऐमीनल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट के द्वारा काफी समय पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में पौलीक्लीनिक मंजूर हुआ था लेकिन किन्हीं कारणवश वह दूसरे जिलों में ले जाया गया। उसके लिए वहां की पंचायत ने जमीन भी दे दी है और वह जमीन ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट के नाम भी चली गई है अतः मेरा निवेदन है कि इस पौलीक्लीनिक को पूरा किया जाए। अब मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे से पूर्व बोलते हुए वीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही, उससे भी मैं इस बारे में सहमत हूं। मेरे हल्के में मन्यौला में भी 5 बसों को रूट परमिट दिए गए थे जिनमें से अब केवल रूट्स दो ही रह गए हैं और उसमें से भी कोई बस खराब हो जाए तो सवारियों को बड़ी भारी परेशानी हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो वहां सवारियां बहुत ज्यादा हैं और केवल दो रूट्स हैं तथा दूसरी तरफ रोडवेज वाले मजबूर हैं कि वहां बस भेज नहीं सकते। मेरा भी वीरेन्द्र सिंह जी की तरह निवेदन है कि इस बारे में लॉ में कोई अमैंडमैंट होनी चाहिए, कोई बिल इस बारे में आना चाहिए ताकि रोडवेज वाले भी वहां बसें चला सकें और लोगों की परेशानी दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मैंने आपको आश्वासन दिया था कि अभी तक किसी भी सदस्य को यदि बोलने का उचित समय न मिला हो तो मैं उसे बोलने का पूरा मौका दूंगा। अब यदि विपक्ष या पक्ष का कोई भी सदस्य यह महसूस करता है कि उसे समय नहीं मिला तो I invite him to speak. अगर अब तक किसी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है तो he is invited.

श्री मनीराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, आप बैठें आपको बोलने का मौका दिया जा चुका है। कट मोशन पर I request Shri Khurshid Ahmed to speak.

श्री खुर्शीद अहमद (नूंह) : स्पीकर सर, जितनी भी डिमांडज हैं उन पर हमारे बहुत से साथियों ने कट मोशंज दिए हुए हैं इसलिए इनके बारे में सभी मैम्बर्ज को बोलने का थोड़ा-थोड़ा समय दिया जाए जिससे वे अपनी बात कह सकें और उनका नजरिया हाउस के सामने आ जाए। वैसे अब बोलने के लिए रह तो कोई नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : 8 आदमियों ने कट मोशंज दी हैं और दो आदमी बोल चुके हैं एक तो सम्पत सिंह और दूसरे सतविन्द्र राणा। खुर्शीद अहमद जी, आपको पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाता है।

श्री खुर्शीद अहमद : सर, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हमारे सामने डिमांड्ज आई हैं। मैं सबसे पहले इंडस्ट्रीज की डिमांड को रैफर करूंगा। डिमांड नं० 16 में शुरु में जब यह असैम्बली इलैक्ट हो कर आई थी, उस वक्त मैंने चाइंट उठाया था कि स्टेट की इकम को मोपअप किया जाए और उसे सरकार अपने हाथ में ले तो हमारे बहुत से टैक्सेज जो हमने लोगों पर लगाए हैं, वह बच जाएं। जो हमारे हाथ में उस दिन रिसोर्सिज थे, बजाय इसके कि कोई यह कहे कि पिछली सरकारों ने यह किया, मौजूदा सरकार की चाल उनसे भी ज्यादा टेढ़ी निकली है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक दफा माइंज और मिनरल्ज के बारे यह बात आई थी तो मैंने कहा था कि माइंज एण्ड मिनरल्ज में बहुत बड़ा स्कैण्डल चल रहा है और बिल्कुल निराधार तरीके से बड़े-बड़े लोगों को लीजिज़ मेजर मिनरल्ज के नाम पर दी गई हैं। माईन्ज-मिनरल्ज को लम्बी अवधि के लिए लीज पर लेने का तो बहाना है। मेजर मिनरल्ज वहां नहीं है। वहां किसी भी चीज का नाम लेकर लाईसैंस दिया गया है चाहे वह सिलका के नाम पर दिया गया हो या चाईना के नाम पर दिया गया है। इसमें शब्दों का अन्तर है। वास्तव में उनके नाम पर लम्बी अवधि की लीज दी गई है जबकि वहां पर निकलता है सिर्फ स्टोन मैटल्ज जोकि लोक निर्माण मंत्री जी के विभाग की सड़कें बनाने के काम आता है, स्टोन क्रेशर वालों के काम आता है या बजरपुर वालों के लिए पत्थर से बजरी बनाने के काम आता है। सरकार की एक संस्था एच०एम०एल० नाम की थी जो मिनरल्ज का काम करती थी जिससे स्टेट को काफी आमदनी होती थी। परन्तु उस संस्था के साथ भी अन्याय हो रहा है। वहां पर प्राईवेट लीज होल्डरों ने कब्जा किया हुआ है। उसकी एक मिसाल में इस सदन के सामने रखता हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में जब यह सरकार बनी, उस समय एक प्राईवेट लीज होल्डर ने फरीदाबाद में एक डिस्प्यूट डाल दिया कि मेरी डिमारकेशन दोबारा कराई जाये। उसकी लीज तो 1983 में हुई थी लेकिन उसको रिडिमारकेशन के लिए 1996 में जरूरत महसूस हुई। रिडिमारकेशन उस एरिया से कराई गई जहां

से बजरपुर निकल सकता था और एच०एम०एल० को आमदनी होती थी। झूठी डिमारकेशन बनाकर एच०एम०एल० की डिमारकेशन को रद्द कर दिया गया। जब एच०एम०एल० की तरफ से चेलेंज किया गया कि यह डिमारकेशन गलत की गई है क्योंकि इसमें फरीदाबाद और बल्लबगढ़ का एरिया दिल्ली में दर्शा दिया गया है। जहां पर बजरपुर निकलता था, उस सड़क को हरियाणा में दर्शाया गया है फरीदाबाद और बल्लबगढ़ की सड़क हरियाणा में होने के बजाय दिल्ली में दर्शायी गई। एच०एम०एल० ने जब कहा कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और जब दोबारा डिमारकेशन हुई तो गुड़गांव और फरीदाबाद के रास्ते में एक फर्लांग ऊपर जाकर हरियाणा का रकबा दिल्ली में चला गया। 1997 में दिसम्बर में जब रिडिमारकेशन हुई तो यह बात इस सरकार के सामने आई कि एच०एम०एल० को कब्जा नहीं दिया गया इसलिए कि वह सही डिमारकेशन के बेसिज पर था और इससे प्राईवेट लैसी की आमदनी पर फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है कि जिस दिन डिमारकेशन हुई थी उस दिन एच०एम०एल० की रिटर्न 710016 मीट्रिक टन बजरपुर सैंड थी और जब 1996 में कब्जा हुआ तब घटकर 341980 मीट्रिक टन हो गई। अब यह घटती ही जा रही है। अब यह घटकर 57299 मी० टन हो गई है। इसमें क्या हो सकता है कि पड़ोसी लैसी की जो पहली रिटर्न थी जब तक उस पर कब्जा नहीं हुआ था उस समय रिटर्न 14,64,768 मी० टन थी जो एक साल के लिए थी फिर जब यह कब्जा हो गया तो पहले साल में उसकी आमदनी लैंड एक्सकावेज़न का रेट बढ़ने से 14 लाख से बढ़कर 1759475 मी०टन हो गई है और आज बढ़कर 2086479 मी० टन तक पहुंच गई है। जो सरकार का लैसी है जोकि सरकार की इंस्टीच्यूशन है उसको खत्म कर दिया गया है और उसकी आमदनी घटकर 52 हजार मी० टन हो गई है। प्राईवेट लैसी की आमदनी 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है जिसमें हेराफेरी हुई है। आज एच०एम०एल० इतनी मुश्किल में पड़ी हुई है कि उसके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं रह गये हैं और प्राईवेट लैसी को इतना प्रोफिट हो रहा है कि एक ट्रक पर उसको 1500/- रुपये बचते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पता चलता है कि सरकार ने एक आदमी को कितना एडवांटेज दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्राईवेट लैसी है, मैं उस का नाम नहीं लूंगा। फिर ये कहेंगे कि नाम लिया है। (विघ्न) अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं कि वह * * * * एम०पी० है। (विघ्न) मेरा जिगरी मित्र और आपका परम मित्र। आज जब दोबारा डिमारकेशन होकर के आई है, जो पिछले साल दिसंबर में ही हो गई थी, अब तक उस का कब्जा नहीं लिया गया है। अब मैंने लेटेस्ट बात सुनी है कि इन दोनों के बीच रिकंसीलिएशन के लिए डायरैक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की ड्यूटी लगाई गई है। वह तय करेगा। इसको एक साल के लिए अगर वह ले गया तो फिर आप देखिए कि एच०एम०एल० को उस में कितना मुनाफा अथवा नुक्सान होगा। पिछली सरकारों के स्कैंडल छोटे पड़ जाते हैं जब इतने बड़े-बड़े स्कैंडल इस सरकार के समय में हो रहे हैं। जो डिमारकेशन की गई है उसका मेरे पास लेटैस्ट नक्शा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल-107 के तहत उसको आपको दे देता हूं। आप इसकी वैरीफिकेशन करा सकते हैं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर। खुर्शीद अहमद जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये पार्लियामैंट में भी रहे हैं और विधान सभा में भी रहे हैं। कई मरतबा ये मंत्री रह चुके हैं। चूंकि * * * इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। ये इस वक्त लोकसभा के सदस्य हैं। (विघ्न) रिकार्ड क्लीयर हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस **** की खुर्शीद अहमद जी बात कर रहे हैं उनका बड़ा भाई प्रताप सिंह पिछले 35 साल से कायदे-कानून के मुताबिक यह कार्य कर रहा है।

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री खुर्शीद अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि लीज़ नहीं ले रहे हैं। लीज़ तो 1983 से ली गई है।

श्री रामविलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * का नाम सदन की कार्यवाही से डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो नाम श्री खुर्शीद अहमद ने लिया है, उसे सदन की कार्वाही से डिलीट किया जाए।

श्री खुर्शीद अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इन का नाम लेना ही नहीं था। मुझे तो नाम लेने के लिए इन्होंने मजबूर किया है। (विघ्न) इस हाऊस में एक एश्योरैंस भी दिया गया था कि इस निगम को कैसे बचाया जाएगा ? इसके लिए हाऊस की एक सब-कमेटी भी बनी थी तथा उस कमेटी में वही लोग लिए गए जिन की वजह से यह आमदनी घट रही है। उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है वह आज तक गुप्त रखी गई है। उस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हाऊस को भी पता नहीं है। वह प्राईवेट लैसी जिसको एडवांटेज मिला है, भी उस कमेटी का एक मैंबर था। (विघ्न)

श्री करतार सिंह भडाना : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ खुर्शीद अहमद जी ने हाऊस के अंदर बताया है, उस में कुछ सच्चाई तो है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सरकार को रैवेन्यू का लौस हुआ हो। इस बारे में मुझे ज्ञान है इसलिए मैं बता रहा हूं। जहां तक रैवेन्यू की बात है वह अब 3 गुना हो गया है। लेकिन डिमारकेशन का काम तो रैवेन्यू विभाग का है, इसको वह देखेगा। इस में सरकार का कोई काम नहीं है। (शोर)

श्री खुर्शीद अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मूल बात का तो समर्थन किया है कि उस में औकुपेशन व डिमारकेशन का झगड़ा है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि यह तो रैवेन्यू डिपार्टमैंट का काम है। यह रैवेन्यू विभाग श्री सूरजपाल जी के पास है, इसलिए यह भी तो सरकार का काम हो जाता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 16.00 बजे एच०एम०एल० को इन लोगों से बचाने की कोशिश करे, उसका हक उसे दिलाएं, उसकी आमदनी जो 7 लाख रुपये से घटकर 57 हजार हो गई है उसको वापिस करवाएं और जो लाभ लीज होल्डर ले रहे हैं वे किसी भी तरीके से रैस्टोर होने चाहिएं। मेरी रैवन्यू मिनिस्टर से भी और सरकार से भी दरखास्त है कि जल्दी से ये एच०एम०एल० को रैस्टोर करवा दें। इसमें पिछली सरकार का कोई हाथ नहीं है। यह एक ऐसा धब्बा है जिसको आपकी सरकार धो सकती है।

श्री करतार सिंह भडाना : जो डिमारकेशन है वह सैन्टर गवर्नमैंट का मसला है और इसमें स्टेट गवर्नमैंट का हाथ नहीं है। हमारी सरकार का चाहे यह रैवन्यू डिपार्टमैंट है या कोई और डिपार्टमैंट है इसमें किसी का दोष नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश किए कि इसकी सैन्टरल गवर्नमैंट डिमारकेशन करेगी।

श्री रामपाल माजरा (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमाण्ड्ज पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम डिमाण्ड नं० 17 पर 1-2 बातें कहूंगा। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। जिस प्रदेश के किसान दुःखी हों वह कैसे तरक्की कर सकता है ? कर्ण सिंह दलाल को सबसे ज्यादा इस बात को महसूस करना चाहिए कि पंजाब में बिजली के बिल माफ हैं अगर वहां ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो सेलज़ टैक्स 2 प्रतिशत लगता है, जबकि हरियाणा में यह साढ़े 4 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में डेढ़ प्रतिशत और

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चण्डीगढ़ में 2 प्रतिशत सेलज टैक्स लगता है। अगर ट्रैक्टर का कोई स्पेयर पार्ट खरीदने चाहें तो हरियाणा में 10 प्रतिशत, पंजाब में 2 प्रतिशत और राजस्थान में 4 प्रतिशत सेलज टैक्स लगता है। हरियाणा के किसानों को ट्रैक्टर कुछ कम रेट पर मिलने चाहिएं। अगर इन पर सरकार की तरफ से 5000 से 7000 रु० की सबसिडी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस तरफ सरकार ध्यान दे। हरियाणा में वाटर लैवल भी नीचे चला गया है। जब किसान कुएं में मोटर का पट्टा डालने के लिए जाते हैं, तो जहरीली गैस के कारण या बिजली का करंट लग जाने से वे मर जाते हैं। कई किसानों के नौजवान बच्चे इसलिए भी मर जाते हैं कि किसी को सांप काट जाता है या किसी पर आसमानी बिजली गिर जाती है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसे किसानों को पूरा मुआवजा देने का कोई बिल पास करे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कल एक लिस्ट पढ़ रहे थे कि किसान कर्जदारी के वक्त में कैसे मरे उन्होंने बताया कि इनमें से बहुत से जाट थे। जगभूनाथ जी बड़े खुश हो रहे थे कि जाट हैं ये तो मरेंगे ही। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजकुमार पुत्र मामन, जाति हरिजन, वासी सीवन, उम्र करीब 30 साल ने बयान दिया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं और मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। मैं शादीशुदा हूं। मेरे पास एक लड़का और एक लड़की यानी दो बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी से मेरा घर का खर्चा नहीं चलता इसलिए मेरे पास काफी देनदारी हो गई थी। देनदारी वालों की टोका टकाई से मैं तंग आ गया था अतः मैंने आत्महत्या करने के लिए गेहूं में रखने वाली गोलियां जो कि मैं काफी दिन पहले कैथल से लाया था और जिन्हें मैंने घर में छुपा कर रखा हुआ था, खा ली। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरे पास पोस्ट मार्टम की और डाईंग डिक्लेयरेशन की रिपोर्ट्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मेहनत करता है वह किसान है लेकिन जो वह हरिजन मरा है वह किसान से भी आगे है। आप कह रहे हैं कि वह किसान नहीं है। इसने भी आत्महत्या की है। यह मेरे पास इसकी पोस्टमार्टम और उसकी डाईंग डिक्लेयरेशन की रिपोर्ट्स है। क्या हरिजन इन्सान नहीं होता क्या हरिजन मरने के लिए है ? उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत बुद्धिमान शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 1991 की सैंसस के मुताबिक हमारे प्रदेश में लिट्रेसी रेट बहुत कम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1991 की सैंसस के मुताबिक विश्व का लिट्रेसी रेट 77.4 परसैंट है, भारतवर्ष का 92.21 परसैंट है, हरियाणा का 54.85 परसैंट है चण्डीगढ़ का लिट्रेसी रेट 77.81 परसैंट है और दिल्ली का 79.25 परसैंट है। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात यह कही थी कि गवर्नमैंट स्कूल का प्लस टू का एक छात्र प्रथम स्थान पर आया है। मैं उनको कहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन को स्ट्रैंथन करने की जरूरत है। मिडिल स्कूलों के परीक्षा परिणामों की 10 स्कूलों की लिस्ट मेरे पास है इन स्कूलों में एक भी बच्चा प्रथम नहीं आया। इसलिए प्राइमरी एजूकेशन को स्ट्रैंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे माननीय सदस्य श्री निर्मल सिंह जी ने कहा था कि शिक्षा को टी०वी० के साथ चोड़ा जाना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने गांव गांव के स्कूलों में टी०वी० दिए थे लेकिन बहुत से स्कूलों में बिजली का कनैक्शन ही नहीं है वहां पर टी०वी० क्या काम करेगा ? वे टी०वी० टीचर्ज के घरों में रखे हुए हैं। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि हमारे शिक्षाविद मंत्री जी शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। आज हर गांव की चौपालों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इसलिए सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है जबकि प्राइवेट स्कूल के मास्टर की तनखाह कम है और उस प्राइवेट स्कूल में दूसरी सहूलियतें भी नहीं हैं। गवर्नमैंट स्कूलों में मास्टरों की तनखाह भी ज्यादा है और सहूलियत भी ज्यादा है लेकिन हमारे गवर्नमैंट स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर बंदिश लगाए। किसी प्राइवेट स्कूल की 62 हजार साल की फीस है और किसी की 21 हजार रुपए महीना है। आज बच्चों के अभिभावक यह समझते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख

[श्री रामपाल माजरा]

जाएं, हमें मम्मी डैडी कहना सीख जाएं इसलिए वे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस दे कर अपना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब प्रदेश की तर्ज पर हमारे यहां पर भी आप पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दें ताकि बच्चों का पब्लिक स्कूलों की तरफ यानि प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान कम हो और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वे भी गवर्नमैंट स्कूलों में जा कर अंग्रेजी पढ़ने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिन गवर्नमैंट स्कूलों के परिणाम बहुत नीचे चले जाते हैं उन स्कूलों का बी०डी०ओ० और डी०पी०आई० कभी भी जा कर निरीक्षण नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करवाएं और शिक्षा में सुधार लाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ज्यादा फुर्ती के साथ काम नहीं कर रहा है। देखने में आया है कैथल में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की जमीन पर रातों रात दुकानें बन गई। इसी तरह से वहां पर मार्किट कमेटी की पुरानी अनाज मंडी के अन्दर 12 दुकानें रातों रात आ गईं। यदि फुर्ती के साथ काम किया जाता तो कोई नाजायज काम नहीं होते। वह करोड़ों रुपये की जमीन है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं मांग नं० 15 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उस वक्त की सरकार द्वारा 1977 के अन्दर थीन डैम से गोविन्द सागर में 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी डालने की बात कही गई थी। यह पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए आना था। उस वक्त लोक दल की सरकार थी। हमें एस०वाई०एल० कैनाल का 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था लेकिन वह पानी हमें देने की बजाय सिरसा की तरफ ले गए, हिसार की तरफ ले गए जबकि हमारा इलाका उसका हकदार था। यह इलाका इस पानी से वंचित हो गया। इस पानी की वजह से सिरसा व हिसार जिलों में तो सेम हो गई जबकि हमारे यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनकी टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंच पाता। खालें बना दी गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज बना दी गई लेकिन पानी नहीं दिया गया। हमारा इलाका सूखा पड़ा है। हमारे वहां पर पीने के पानी की समस्या है। मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 111 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रेन बनायेंगे और इसके द्वारा फालतू पानी इधर लायेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आज महेन्द्रगढ़, पटौदी, मेवात या उस तरफ का दूसरा जो एरिया है उसमें पानी नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो वायदा चुनाव में किया था उसके बारे में इनको कुछ सोचना चाहिए। सरकार इस काम के लिए 1858 करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है। जबकि हमारे सर छोटू राम जी ने इसलिए बनियों की बहियां फड़वा दी थी, उनको जलवा दिया था क्योंकि उन्होंने जमींदारों को कर्ज दिया हुआ था। जबकि ये कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। जो ये कर्ज ले रहे हैं उसका 14 परसेन्ट इन्ट्रस्ट के हिसाब से 350 करोड़ रुपया इनको ब्याज का देना पड़ेगा जबकि पानी से फिर भी हम वंचित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नरवाना ब्रांच, भाखड़ा मेन लाईन जो है इसमें से हमें 2700 क्युसिक्स पानी कम मिल रहा है, हमारे इलाके को कम पानी मिल रहा है, उसकी डिसिल्टिंग नहीं हो रही जिस वजह से कुछ पानी तो पंजाब ले जाता है और कुछ पानी हिसार या सिरसा की तरफ चला जाता है। पानी का सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि हिसार व सिरसा में तो सेम आ रही है जबकि हमारे यहां पर लिफ्ट की जो कैनाल हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है। चौधरी बंसी लाल जी लिफ्ट कैनाल की बात करते हैं, 1.8 मिलीयन एकड़ फीट पानी की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश से पानी लाने की बात करते हैं। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर लिफ्ट की जो स्कीमें थीं, उनकी 30 प्रतिशत से ज्यादा मोटरें खराब हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। हमारे यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें टेल एण्ड

तक पानी नहीं जाता। उनमें गाद्द व्या गये हैं। उनकी पूरी तरह से सफाई नहीं हो रही। मैं चाहूंगा कि इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की मौके पर जा कर निरीक्षण की जाये और उनकी सफाई कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज के लिए हमारे लोक दल के इन भाईयों ने करोड़ों रुपये लगाकर हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की और उस जमीन पर दिल्ली को बचाने के लिए मसानी बैराज बनाया गया। चौधरी बंसी लाल जी जब विपक्ष में बैठा करते थे तब कहा करते थे कि मैं कृष्णावती, दोहान और साहबी नदियों का पानी हरियाणा में लाने के लिए, हरियाणा सरकार को राजस्थान सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन आज ये इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में नदियों का पानी ज्यादा हो जाता है तो वे इस पानी को हमारे इलाके में छोड़ देते हैं, जिससे हमारे इलाके की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा इसी हाउस में आश्वासन दिया गया था कि हम मसानी बैराज पर शटर्ज लगायेंगे लेकिन अभी तक वहां पर शटर्ज नहीं लगे हैं, उसका पानी वहां पर तबाही मचाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बैराज के बनाने के लिए जो जमीन किसानों से ली गई थी उसके लिए उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इस बैराज की एक 6 फुट ऊंची दीवार बना दी है जिसके कारण उन बेचारे किसानों के मकान और खेत डूब जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय गंगा का पानी हरियाणा में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इनसे यह कहता हूं कि आप गंगा के पानी की बात तो छोड़िये, आप एस०वाई०एल० कैनाल बनाकर ही हमें हमारे हिस्से का पानी दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इस बजट के अंदर एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में बहुत ही मामूली तरीके से बात कही गई है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज मेरे लायक दोस्त कैप्टन साहब के इलाके में है, इस बैराज में शटर्ज तो तभी लगाये जा सकते हैं जब इसमें पानी आता हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब से पूछता हूं कि क्या ये मसानी बैराज को एप्रूव करते हैं, क्या इसके बनने के बाद से उसमें कभी पानी आया ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, 1995-96 में मसानी बैराज में पानी आया, लेकिन इस बार अब तक भी उसमें पानी नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, साहबी नदी पर बांध बनने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस नदी पर 3 बांध पीछे बना लिये, इसलिए उधर का पानी तो इधर आता नहीं है। यह जो मसानी बैराज बना है चाहे किसी भी सरकार के दिमाग की उपज हो, इसका कोई भी उपयोग नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जब राजस्थान में पानी फालतू हो जाता है तो वे अपने इलाके को तो डूबने नहीं देते, बल्कि उससे पहले ही अपने उन बांधों को तोड़ देते हैं, उनके बांध कच्चे बने हुए हैं जिसके कारण हमारे इलाके में बाढ़ आ जाती है। मैं इरीगेशन मंत्री से कहना चाहूंगा कि जब बरसात के दिनों में जमुना और जे०एल०एन० कैनाल के अंदर ज्यादा पानी होता है तब आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जे०एल०एन० कैनाल का एक छोटा सा हिस्सा भी मसानी बैराज से जोड़ दें तो यह फालतू पानी मसानी बैराज में जा सकता है और वहां इसका उपयोग हो सकता है। उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा।

श्री वीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट इरीगेशन मंत्री की रिप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं कि 1977 या इससे पहले साहबी नदी में कई बार 30-40 हजार क्यूसिक फुट पानी डेली आता रहा

[श्री धीरपाल सिंह]

है। मंत्री जी को उस इलाके के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। बाहली, झज्जर, रिवाड़ी और पटौदी वगैरह का जो इलाका है, उस में इस नदी से भयानक तबाही होती थी इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए मसानी बैराज की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन इसको बनाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस नदी पर अपने यहां बांध बना लिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, चौधरी बंसी लाल जी तो इस समय बैठे नहीं हैं लेकिन जब ये विपक्ष में हमारे साथ बैठते थे और उधर चौ० भजन लाल जी बैठते थे तो ये बार-बार यह कहते थे कि राजस्थान सरकार पर दबाव डालकर जो राजस्थान की भूमि पर उन्होंने बांध बनाये हुए हैं, उन बांधों को हटवाया जाये और इस साहबी नदी के पानी में हमारा जो हिस्सा है, वह हमें दिलवाया जाये। लेकिन अब इन्होंने पानी का वह हिस्सा तो लिया नहीं और बेवजह की गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की सुलैच प्रणाली का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप दो मिनट में कन्क्लूड करें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, सुलैच सिस्टम पहले सरकार ने खत्म किया और फिर उसको दोबारा लागू भी किया गया है। सरकार यह बताए कि यदि इस सिस्टम को दोबारा लागू करना ही था तो फिर खत्म किस लिए किया गया था और क्या इसको दोबारा लागू करने से पहले सरकार ने किसी किस्म का कोई सर्वे करवाया है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय राम बिलास शर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं इन्हें उस इलाके के बारे में पूरा ज्ञान है कि वहां पर जो ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं वे 70 या 80 फुट की गहराई से स्टार्ट होते हैं। हमारे इलाके की समस्या यह है कि हमें उन इलाकों के साथ ईक्वेट कर दिया गया है जहां पर चार-चार फसलें साल में होती हैं। हमारे इलाके में तो सारे साल में एक ही फसल होती है। (घण्टी) हमारे वहां पर नहरों का पानी नहीं लगता है और लोग वहां पर सिंचाई के लिए केवल ट्यूबवैलों पर ही निर्भर करते हैं। जहां पर नहरें हैं वहां पर आबियाना 20 रुपये है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने सुलैच सिस्टम के बारे में शायद पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले के लोगों ने कहा है कि यह सिस्टम किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ और लोहारू के ऐरिया के किसानों को बिजली बोर्ड से चिट्ठियां आई हैं कि जिन लोगों ने बिल ज्यादा जमा करवाए हैं या जिन्होंने जितना अधिक बिल पे किया है, वे अब उस बिल को या तो अगले बिलों में एडजस्ट करवा लें या अगर वे चाहें तो ज्यादा जमा करवाया गया पैसा उनको वापिस मिल सकता है। इस स्कीम से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय जिस सर्वे की ये बात कर रहे हैं वह भी हो रहा है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, *********

Mr. Speaker : Now I request Capt. Ajay Singh to take his seat. (Interruptions). Nothing is to be recorded.

** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर सर, मैंने बजट डिमाण्डज़ 1998-99 में डिमाण्ड नं० 2, डिमाण्ड नं०-4, डिमाण्ड नं०-8, डिमाण्ड नं०-10, डिमाण्ड नं०-15 और डिमाण्ड नं०-21 पर कट मोशन्ज़ दी हुई हैं। इन डिमाण्डज़ पर मैं दो-दो मिनट्स अपने विचार रखना चाहूंगा। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कट मोशन पर बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय 1977 में जब हम पहली बार विधान सभा में चुन कर आए थे, उस वक्त तनख्वाहों पर टोटल बजट का 36 पैसे का खर्च होता था।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 30 minutes.

Voice : Yes.

Mr. Speaker : Time of the sitting is extended by 30 minutes.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त इम्पलोईज़ की सैलरी पर तथा जो भत्ते हम उनको देते थे, पर टोटल बजट का 36 पैसे इस मद पर खर्च होता था लेकिन आज फिगर्ज़ रिवर्स हो गई हैं। आज यह फिगर 36 की बजाए लगभग 63 हो गई है। मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मेरा अनुभान है कि यह फिगर लगभग 63 हो गई है। और कई महकमे तो ऐसे हैं जिनके बारे में यदि यह कहा जाए कि दाढ़ी से मुछ भारी तो कोई गलत बात नहीं है। इरीगेशन डिपार्टमैंट में जो पैसा डिवैल्पमैंट के काम के लिए रखा गया है वह बहुत ही कम है क्योंकि उस पैसे का 72 प्रतिशत हिस्सा तो तनख्वाह में ही चला जाता है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। आज आप किसी भी दफ्तर में जाकर देख लें, एक आदमी की जगह पर 4-4 आदमी काम के लिए लगा रखे हैं। कोई एक आध आदमी ही सीरियसली किसी दफ्तर में काम करता होगा वरना कई तो ऐसे हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे मिलेंगे। उनमें से अगर किसी को कोई काम कह दिया जाए तो वह कहेगा कि यह मेरा काम नहीं है यह फलाने का काम है और दूसरे के पास जाओ। जब दूसरे के पास जाओगे तो वह भी यही कहेगा कि यह मेरा काम नहीं है। आज कोई भी सीरियसली काम नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, आई०ए०एस० के कैडर में 64 पोस्टें ऐसी हैं जो एच०सी०एस० से परमोट करके भरी जाती हैं लेकिन आज इनमें से 30 भरी हुई हैं और 34 खाली पड़ी हुई हैं। कांस्टीच्यूएशन में मैंडेटरी है कि हर साल डी०पी०सी० की मीटिंग होनी चाहिए और जो सीनियर एच०सी०एस० हैं उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए। पिछले चार साल से जिसमें दो साल भजन लाल जी की सरकार के थे और अब दो साल इस सरकार को आए हुए हो गए हैं, इस बारे में इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ये जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उसके बारे में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन तभी दे सकती है जब यह सरकार उन आफिसर्ज पर भरोसा करे। सरकार के जो मुखिया हैं जो सरकार को चलाते हैं, ऐसे करीब 30 से ऊपर एफ०सीज० और सैक्रेटरी रैंक के ओफिसर्ज हैं। उनमें से 16 ओफिसर्ज तो ऐसे मिलेंगे जिनको ऐसी जगह पर लगा रखा है जहां पर कोई काम नहीं है। उनको कहते हैं कि आओ, बैठो, चाय पियो और अपने घर चले जाओ। जबकि किसी-किसी औफिसर को तो चार-चार आदमियों का काम दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, सभी ओफिसर्ज एफिशियंट होते हैं हर कोई अच्छा काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

32 सालों में हरियाणा बनने के बाद हमारे यहां पर एक सिस्टम डवैल्प हुआ है कि हम अधिकारियों को ग्रुप के हिसाब से देखने लग गए हैं कि फलाना अधिकारी किसी खास के साथ जुड़ा हुआ है और फलाना आदमी उसके साथ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहता हूं कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर अधिकारी पर विश्वास करना पड़ेगा। जो अधिकारी धोखा देगा या देता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और उसके खिलाफ जो भी सजा बनती हो वह उसको दी जाए। यह तो मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने खर्चों को कम करने के लिए भी एक कमेटी बनाएं। फोरसुनेटली लीडर आफ दी हाउस भी यहां पर बैठे हुए हैं। आज सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने कर्मचारियों के रिटायरमैंट की उम्र 58 से 60 साल तक कर दी है। मैं यह बात साफ करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर सरकारी अधिकारियों के रिटायर होने पर कम से कम 25 हजार नौकरियां उनकी जगहों पर दी जाती हैं। अगर सरकार यहां भी इस उम्र को बढ़ा देती है तो बहुत से नौजवान नौकरियों से वंचित हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 58 साल की उम्र के व्यक्ति को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह में तो तीन नए नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी तो हम सरकार से यह आश्वासन चाहेंगे कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जबकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही हो तो सरकार 58 साल से 60 साल उम्र बढ़ाने में कोताही बरतेगी और केन्द्र सरकार को इस मामले में फॉलो नहीं करेगी। स्पीकर सर, बहुत सी स्टेट्स ने इस बारे में मना कर दिया है कि हम यह उम्र 58 साल से 60 साल नहीं करेंगे ताकि नौजवानों को नौकरियां मिल सकें। इसके अलावा मैं इरीगेशन के बारे में अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में नरवाना डिवीजन और हिसार डिवीजन से सिंचाई व्यवस्था का प्रबन्ध होता है। इनमें से एक डिवीजन का एस०ई० कैथल में बैठता है। हमारे यहां पर एक ही डिवीजन के अंदर दो तरह के सिस्टम हैं जैसे अभी यहां पर स्लैब सिस्टम की बात आयी थी। वैसे ही हमारे यहां भी दो तरह की सिंचाई की व्यवस्था के सिस्टम हैं। स्पीकर सर, पिछले साल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और लीडर ऑफ दी हाउस ने मेरी बात को ठीक मानते हुए यह कहा था कि हम इसको दिखवाएंगे। स्पीकर सर, एक रजबाहा तो हमारे यहां महीने में आठ दिन चलता है और 21 दिन वह बंद रहता है और इसी के साथ-साथ दूसरी नहरों में पानी 15 दिन चलता है और 15 दिन बंद रहता है। मैंने यह कहा था कि हमारे साथ यह डिसक्रिमिनेशन पिछले आठ-नौ साल से हो रहा है।

श्री बंसी लाल : तब आपकी ही सरकार थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अगर हमारी सरकार ने कोई गलती की है तो हम अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको ठीक करें। अगर आप भी उनको ठीक नहीं करते तो हम यह समझेंगे कि हममें ही कोई कमी है या हमने कोई गुनाह किया है। स्पीकर सर, उस रोटेशन सिस्टम को ठीक किया जाए और दूसरी नहरों की व्यवस्था की तरह हमारे यहां की नहरों में भी 15 दिन पानी चलना चाहिए और 15 दिन बंद रहना चाहिए। स्पीकर सर, हमारे यहां धमतान और सुदकन दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं इनमें से एक नरवाना विधानसभा क्षेत्र को फीड करती है और दूसरी उचाना विधानसभा क्षेत्र को फीड करती है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस गलती को ठीक किया जाए ताकि किसानों को वहां पर पूरा पानी मिल सके और किसान वहां दो फसल ले सके इससे किसान वहां अन्न भी ज्यादा पैदा कर सकेंगे। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब टांगड़ी, मारकंडा या घग्गर नदी पर हम बैराज बनाने की बात करते हैं तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि पिछले लोकसभा के चुनावों में दड़वा कलां

कॉंस्टीच्यूएंसी में कम से कम दो दर्जन गांवों वालों ने इन इलैक्शन का बायकाट किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि हम किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहां के 24 गांवों में पिछले कई सालों से सेम की समस्या गंभीर होती जा रही है लेकिन अब तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। स्पीकर सर, यह समस्या राजस्थान के सूरतगढ़ में बड़ा भयावह रूप धारण कर रही है। स्पीकर सर, मेरी आपसे यह सबमिशन है कि एक तरफ तो हम सेम की समस्या सिरसा, हिसार के हल्कों में पैदा कर रहे हैं। यदि आगे राजस्थान के लोगों ने इस पानी को रोक दिया तो हमें इसको संभालने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी वहीं दूसरी तरफ हम टांगड़ी, मारकंडा और घग्गर जैसी नदियों पर बैराज बनाने की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेम की समस्या के समाधान हेतु टांगड़ी, मारकंडा और घग्गर नदियों पर बैराज बनाने की इस स्कीम को शुरू करना चाहिए। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इरीगेशन डिपार्टमैंट एक तरफ तो एम०आई०टी०सी० को स्कलटन के रूप में रखना चाहता है वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जो किसानों के पक्के खाले बने हुए थे, वे आज टूट रहे हैं। इन पक्के खालों को तो आप मिट्टी से ठीक नहीं कर सकते। इनकी रिपेयर तो आपको करवानी ही पड़ेगी।

श्री बंसी लाल : बरसौला माईनर किस क्षेत्र में है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : बरसौला माईनर उचाना, जींद और नारनौंद के कुछ गांवों को इरीगेट करेगा लेकिन मैंने तो इस माईनर का जिक्र नहीं किया। अगर आप कुछ काम करेंगे तो हम आपको दाद देंगे, आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम पिछले 25 सालों से चिल्ला रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। जब कभी भी हमारी सरकार बनती थी तो हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे पड़ौसी उसी महकमे के मंत्री होते थे। आपने यह काम बहुत अच्छा किया है और वहां के लोग आपकी इस बात के लिए बहुत आभारी हैं (घंटी) अब मैं ऐग्जिस्टिंग चैनल्ज के बारे में कहना चाहूंगा। उनमें डिसक्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट के बारे में कहना चाहता हूं पिछले 30-32 साल में बल्कि देश की आजादी के बाद कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट ने हर गांव में बहुत असैट्स डिवैलप किए हैं। इस डिपार्टमैंट ने हरिजन चौपाल, बी०सी० चौपाल, पंचायत घर के अलावा स्कूलों की बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कीं, गलियों को पक्का किया, जिनकी बहुत वैल्यू है लेकिन कोई पंचायत उनकी मेन्टीनैंस के लिए कुछ नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप वह स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाए हैं, वे आने वाले 10 साल में धराशाही हो जाएंगे और फिर लोग डिमांड करेंगे कि पंचायत घर बनाओ, पटवारखाने बनाओ, चौपालें बनाओ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा फौजियों का इलाका है हर गांव में अच्छी संख्या में आपको एक्स-सर्विसमैन मिलेंगे। उनकी आप लैंड फोर्स बनाएं और जिन गांवों में ये असैट्स क्रिएट हुए हैं उनको मेनटेन करने की जिम्मेदारी उनको दी जाए। अगर वे पंचायत घर से हटकर हों तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह से मैं पी०डब्लू० डी० मिनिस्टर से कह रहा था कि इसी तरह की जिम्मेदारी आप वहां लगाओ जैसे कि किसी गांव में बीच में से सड़क निकली है, उस सड़क की रेजिंग के हिसाब से दोनों तरफ नाली बने। इनका कहना ठीक था कि नाली का रख रखाव नहीं होगा तो उसके रख रखाव का काम भी लैंड फोर्स कर सकती है इससे जो करोड़ों अरबों रुपये के असैट्स खड़े कर दिए हैं, उनका रख-रखाव कर सकने में हम सक्षम हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, अब आप बैठ जाइए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में भी कहना चाहूंगा। प्रश्न काल के दौरान मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ ऐसे बड़े गांव जिनकी आबादी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

5 हजार से ऊपर है, को टेकअप कर रहे हैं। जिन वाटर वर्क्स से इनको पानी मिलता है आप उसकी मात्रा बढ़ाएं। अगर वहां पानी की मात्रा बढ़ेगी तो हम प्राइवेट कनैक्शन भी देंगे। यह अच्छी बात है लेकिन अगर आप ने उस पानी की निकासी का पूरा इंतजाम नहीं किया तो वे गांव नर्क बनकर रह जाएंगे। आप देखें कि जहां भी टूटियां लगी हुई हैं, स्टैण्ड पोस्ट लगे हैं वहां गलियां सड़ती हैं। मेरा सरकार से यह कहना है कि आप जिस गांव को भी इस लेवल पर टेकअप करो और यदि उसके पानी को 70 लीटर से 110 लीटर में परिवर्तित करना हो तो उसका कंपोजिट प्लान होना चाहिए। हर गांव में दो लाख रुपये मंत्री महोदय दे आते हैं कि गलियां बनाओ। अब उस गांव के सरपंच की मर्जी है कि वह किस गली को बनाने के लिए छांटता है। वह ऊपर से गली बनाना शुरु कर देता है इससे जो पिछली गली बनी हुई थी, वहां सारा पानी खड़ा हो जाता है। जैसे आपने सौ गांव, पचास गांव या पांच सौ गांव छांटे हैं तो उसका टोटल कंपोजिट मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा। जिसमें स्ट्रीट लाइट, गलियों को पक्का करना, सीवरेज की फैसिलिटी देना और स्कूलों का कुछ करना चाहिए। राम विलास जी बैठे नहीं हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि राम पाल माजरा जी ने जो बात कही है, वह ठीक है आज लोगों का रुझान पब्लिक स्कूलों की तरफ है। हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है क्योंकि स्कूल का जो टीचर होता है वह साल में पांच महीने पढ़ाता है और सात महीने छुट्टी करता है। उस टीचर के ये सात महीने युटीलाईज करने के लिए या तो उसको कोई रिफ्रेशर कोर्स कराया जाये या फिर कोई ओरियंटेशन कोर्स कराया जाये ताकि वह अच्छी क्वालिटी की ऐजूकेशन बच्चों को दे सके। मेरे अपने गांव में जो स्कूल हैं उसमें विद्यार्थी तो 95 हैं लेकिन टीचर 22 हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो सिर्फ वह गरीब ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो पब्लिक स्कूलों की फीस अदा नहीं कर सकते। चाहे सरकारी स्कूलों में ऐजूकेशन की क्वालिटी कुछ भी हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह स्कूलों को अपग्रेड करने की बजाय ऐजूकेशन की क्वालिटी में सुधार करे क्योंकि डिग्री देने मात्र से तो प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाना है। बढ़िया ऐजूकेशन देने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 30 minutes.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Time of the sitting is extended by 30 minutes.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने डिमाण्ड की कट मोशन पर नोटिस दिया हुआ है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No please. you are requested to take your seat.

Shri Sampat Singh : Speaker, Sir, I want your ruling.

Mr. Speaker : I would not allow you to speak now. You have already spoken today.

Shri Sampat Singh : It is against the Rules. Speaker Sir,* * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद कहा है कि डिमांड्स पर अगर कोई सदस्य बोलने से रह गया हो तो वह बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि जिस सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है, वह बोल सकता है। मैं अब भी इस बात पर स्टैंड करता हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक हैं। पहले हालात कुछ और होते थे क्योंकि पहले डिमांड्स पर चर्चा 2-3 दिन तक होती थी लेकिन अब डिमांड्स पर चर्चा एक दिन ही रखी गई है। The Speaker has the privilege to apply guillotine. प्रोसीजर यह है कि पहले गलोटीन आती है, उसके बाद डिमांड्स पर चर्चा होती है। लेकिन यहां तो गलोटीन आने से पहले ही चर्चा खत्म कर दी गई है।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1993-94 की डिमांड्स अलग थीं और इस वर्ष 1998-99 की डिमांड्स अलग हैं। शुरू में ही आपने सारे सदन को यह कहा था कि जो माननीय सदस्य एक बार भी सदन में नहीं बोला हो, आज चाहे रात हो जाए, लेकिन उस को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। इन्होंने ही डिमांड्स पर बोलना प्रारम्भ किया था।

Shri Birender Singh : If you put any demand to the vote of the House then you would also put the cut motion and on that opportunity we should be allowed to speak. That is the practice.

श्री अध्यक्ष : आप भी कट मोशन और डिमांड्स दोनों पर बोल चुके हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी श्री सम्पत सिंह बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी अगर नहीं मानें तो बात और है लेकिन आपने तो इनको पहले यह कहा था कि ये जितना समय लेना चाहते हैं वह चाहे कट मोशन पर ले लो या डिमांड्स पर ले लो।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप अपनी पार्टी के समय को टोटल कर के देखें तो पता लगेगा कि आप लोग कितने समय बोल चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य को बोलने के लिए अनुमति देना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आप चाहें तो लिखे हुए को भी कटवा देंगे। आप तो कानून बनाने वाले हैं। हम आपकी रूलिंग चाहते हैं। आप अपने फैसले को फौरन बदल देते हो। हम आपकी रूलिंग चाहते हैं कि जिन लोगों ने कट मोशन दिए हैं, क्या आप उनको बोलने देंगे अथवा नहीं ? आप तो कानून बनाने वाले हैं। (विघ्न)

**Not recorded as ordered by the Chair.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कट मोशन पर बोलने की बात कर रहा हूं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड्ज़ पर बोल चुके हैं। जब कट मोशंज़ आएंगी तो वोटिंग करा लीजिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम तो टैक्नीकल बात में पड़ गए हैं। पांच माननीय सदस्यों के कट मोशंज़ डिमांड्ज़ पर ही हैं। उनकी डिमांड्ज़ पर एक रुपये का कट लगाने की बात थी। इन पांच सदस्यों में श्री खुर्शीद अहमद, रामपाल माजरा व श्री अशोक कुमार भी थे। जिन में से 4 माननीय सदस्य तो कट मोशन पर बोल चुके हैं। (विघ्न) आप सब डिमांड्ज़ व कट मोशन पर इकट्ठे बोले हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज डिमांड्ज पर बड़ी संजीदा बहस हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। सम्पत सिंह जी बहुत अधिक तैयारी से बोले हैं। उन्होंने हमारी बात की ताईद की है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आज के दिन 863 मैगावाट बिजली पैदा होती है। हमने भी यह बात बार-बार कही कि 863 मैगावाट बिजली हरियाणा की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, कम पड़ती है। इसलिए आने वाले समय के लिए 1523 मैगावाट बिजली अतिरिक्त उपलब्ध करना हमारा लक्ष्य है। सतबिन्द्र राणा जी ने कानून और व्यवस्था की बात की। खुर्शीद अहमद जी द्वारा भी कल बेरोजगार नौजवानों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। मैंने पहले भी बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने मनीराम गोदारा जी की अध्यक्षता में इस बारे में एक कमेटी बनाई हुई है जिसके सदस्य ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हम हैं। काफी एक्सरसाईज करके सदन में जो बातें आई हैं उनको ध्यान मे रखकर हम जल्दी ही इसका निर्णय करने जा रहे हैं। राव नरेन्द्र सिंह ने अटेली के बारे में बात कही। रामपाल माजरा ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि शिक्षा का जो स्तर है उसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यह बात सही है कि जब तक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी और तब तक बच्चे की आगे की पढ़ाई में रुचि नहीं बनेगी। पहले हमने प्राथमिक शिक्षा 4 जिलों में चलाई जब तक उन 4 जिलों में प्राथमिक शिक्षा की अच्छी परफोरमैंस आई तो तीन अतिरिक्त जिलों में हमने प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी। कुछ साथियों ने एक बात यह भी कही कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से पढ़ाने का प्रावधान किया जाए। यह एक मौलिक सी बात है। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसा मानता हूं कि बच्चे को शुरू में अपनी मातृ भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। अब तक जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या जो शिक्षा के सम्बन्ध में चिन्तक और दार्शनिक हुए हैं उन सब की भी यही मान्यता है कि पहले 5-6 साल बच्चे को मां के दूध की भाषा में शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो वह बच्चा सरलता से और प्राकृतिक रूप से उनको ग्रहण करता है। यह प्रकृति का नियम है। आजादी से पहले यह गलत फहमी नहीं थी लेकिन आजादी के बाद देश में जो टाई-फाई हुई है उसके बारे में बड़े-बड़े लोगों में गलत फहमी बैठ गई कि अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक लोगों की भाषा है इसलिए अंग्रेजी अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। जबकि यह गलत धारणा है। क्योंकि गौरवाच्योव अंग्रेजी नहीं बोलता था, जापान में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। जर्मनी के रेलवे स्टेशन या बस स्टैण्ड पर आप भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे यदि आप वहां पर अंग्रेजी में पानी मांगोगे क्योंकि कोई भी आपको पानी नहीं देगा। अंग्रेजी में रास्ता पूछोगे तो कोई आपको रास्ता नहीं बताएगा। (शोर)

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : डा० वीरेन्द्र पाल जी, आप पहले ये बताएं कि प्वायंट आफ आर्डर किस चीज पर होता है उसके बाद ही आप प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना। (विघ्न) डा० साहब आप बैठें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, डा० बीरेन्द्र पाल जी ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से पशु चिकित्सा में डौक्टरेट किया है। ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। शिक्षा का मामला हर आदमी के बस का नहीं है। यह बहुत गहन बात है। जहां तक बच्चों के मनोविज्ञान की बात है वह बहुत सूक्ष्म होता है, बड़ा कम्पलीकेटिड होता है, बड़ा डैलीकेटिड होता है। इसके बारे में पूरी दुनिया में बहस चल रही है और विचार किया जा रहा है कि बच्चों के बस्तों का बोझ कैसे कम किया जाए। भारत की जो गुरूकुल प्रणाली की पद्धति थी, आज पूरी दुनिया उस पर विचार कर रही है। आज स्कूलों में भी नर्सरी, के०जी०, यू०के०जी० की कक्षाएं शुरू कर दी जाएं तो इससे बच्चों का मूल विकास रुक जाएगा। पब्लिक स्कूलों में नर्सरी, के०जी०, यू०के०जी० की क्लासिज शुरू करने से बच्चों का मूल विकास रुक गया है। आज पूरी दुनिया मानने लगी है कि बच्चों को पोनी बना दिया गया है इसलिए हम इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए इस बात को पसंद नहीं करते कि पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। हम हरियाणा प्रदेश में बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के हक में नहीं हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं राम बिलास जी से एक बात पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले दिन से ही यह अनाउंस कर दिया था कि हम पहली जमात से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का समर्थन नहीं करते तो यह बात आपकी बी०जे०पी० के लिए कम्पलीकेशन क्रिएट करेगी क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने प्रदेश में पहली जमात से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी है और वहां पंजाब सरकार का बी०जे०पी० समर्थन कर रही है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, पंजाब की बात पंजाब वाले जानें लेकिन हरियाणा प्रदेश में पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का हमारा विचार नहीं है। स्पीकर साहब, राजीव गांधी ने पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ी थी इसलिए वे अणु विस्फोट नहीं कर सके लेकिन हमारे प्रधान मंत्री बाजपेयी जो गुरुकुल में पढ़े थे इसलिए उन्होंने अणु विस्फोट कर दिया। स्पीकर साहब हम अपनी शिक्षा प्रणाली को, अपनी संस्कृति को दुनिया की शिक्षा प्रणाली से हीन नहीं मानते। स्पीकर साहब, सदियों से भारतवर्ष ज्ञान 17.00 बजे विज्ञान का केन्द्र रहा है। जो नालन्दा और तक्षशिला अखण्ड भारत के विश्वविद्यालय थे, उनमें पूरी दुनिया के आदमी पढ़ने के लिए आते थे। चीन के भी होंगसांग और फिहांग दार्शनिक यहां पर आए थे उन्होंने लिखा है कि इस देव भूमि को देखने का हमारा 20 साल की जिन्दगी का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने भारत के बारे में जो इतिहास लिखा, वह अलग बात है। हम प्राचीन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में बच्चों पर पहली कक्षा से अंग्रेजी नहीं थोपना चाहते। जो मौजूदा पढ़ाई है यदि उसको पढ़ लिया जाए तो बहुत है। स्पीकर साहब, मेरे कुछ साथी जिनमें रिसाल सिंह जी एवं हुड्डा जी थे, ने एक बात कही कि सोसायटियों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। रामपाल माजरा जी ने स्कूलों के निरीक्षण की बात कही। हमारे सभी अधिकारी चाहे खण्ड शिक्षा अधिकारी हों, सब डिवीजनल शिक्षा अधिकारी हों, जिला शिक्षा अधिकारी हों या प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हों, सभी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। हमने उनको आदेश दिए हुए हैं कि उनके अन्तर्गत जितनी संस्थाएं आती हैं उनका छः मास के अन्दर एक बार निरीक्षण अवश्य करें और उसकी रिपोर्ट करें। हमारे यहां पर बच्चों को नैतिक शिक्षा देने बारे जब भी बातचीत होती है तो उसमें हम खण्ड शिक्षा अधिकारी तक को शामिल करते हैं और उस समय इन सारी बातों पर विचार होता है। एक साथी ने सढौरा में 10+2 का स्कूल बनाने की बात कही क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं है वहां पर प्राईवेट संस्था ही है। असंध में भी इसी तरह का स्कूल बनाये जाने की बात यहां पर कही गयी। एक दो जगह से और भी इस तरह की मांग आई। मैंने उनको कहा कि 10+2 का स्कूल

[श्री राम बिलास शर्मा]

अपग्रेड करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अगर आप उनको पूरा करवा दें तो हम आपकी इन बातों पर विचार कर लेंगे। यहां पर कुछ साथियों ने जिनमें वीरेन्द्र पाल जी भी थे यह भी कहा कि विश्व बैंक से कर्जा क्यों ले रहे हैं। विकास के लिए कोई सरकार भारत सरकार से कर्जा लेती है कोई किसी और संस्था से कर्जा लेता है। कर्जा देने वाला भी देने से पहले यह देखता है कि जिसको कर्जा दिया जा रहा है क्या वह वापस चुकाने की स्थिति में है या नहीं ? तभी जाकर वह कर्जा देता है। हमने विश्व बैंक से एच०एस०ई०बी० के लिए जो कर्जा लिया उसमें विश्व बैंक ने देखा कि यह बोर्ड कर्जा चुकाने की स्थिति में है या नहीं। इसके बाद ही उसने कर्जा दिया। वे इस बात को अच्छी तरह से देखते हैं कि कर्जा लेने वाला ईमानदार है और सिंसियर है या नहीं इसके बाद ही वे कर्जा देते हैं। यहां पर किसानों की पास बुक देने की बात भी कही गई। इस बारे में हमारे राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि इसे जल्दी ही लागू करेंगे। खुर्शीद अहमद जी ने कहा कि रामचन्द्र बैन्दा को सरकार ने कुछ लीज पर जमीन दी है। हमने उनको कुछ लीज पर नहीं दिया। उनका 30 साल पुराना कारोबार है। यहां पर मसानी बैराज की बात कही गई। इसी प्रकार से दोहान एवं कृष्णावती नदियों की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि रिवाड़ी के इलाके के और उसके आसपास के इलाके को पानी नहीं मिल पा रहा है और इन नदियों में 15 वर्षों से पानी बिल्कुल नहीं आया। कुछ साथी कहते हैं कि इनमें पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि राजस्थान वालों ने इनमें बांध बना लिए। इस बारे में 2-3 बार हमारी उनसे बातचीत हुई है। भैरो सिंह जी से मेरी भी बात हुई है। वे कहते हैं कि हमने इन नदियों पर कोई पक्का बांध नहीं बांधा। इसलिए आप एक बार जाकर मौके पर देख लें कि कहां-कहां पर बांध बनाए हुए हैं, फिर उन पर बैठकर एक ज्वायंट मीटिंग कर लेंगे। इस ज्वायंट मीटिंग के बारे में तो सी०एम० साहब ही बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संबंधी जो मुद्दे यहां पर उठाये गए थे, उनके बारे में मैंने आपके सामने निवेदन कर दिया है, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, डिमांडज के ऊपर आज जिन-जिन बातों पर चर्चा हुई उनमें से चौ० संपत सिंह जी ने शायद एक बात यह भी कही कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट में 210 मेगावाट का छटा प्लांट जो हम लगाने जा रहे हैं उसका इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बजट में इसका प्रोविजन इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली बोर्ड अपने साधन खुद जुटाता है। इसके ऊपर 634 करोड़ रुपये लगेंगे जिसमें से 320 करोड़ रुपये का लोन पावर फाईनांस कारपोरेशन से मंजूर हो चुका है और 117 करोड़ रुपये पब्लिक से लोन की शक्ल में बिजली बोर्ड ने रेज कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, चौ० संपत सिंह और इनकी सरकार 1989 में जब मशीनरी खरीद के डाल गये थे तो इसके बक्से को इनकी खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि पैसे लगते लेकिन उस मशीनरी को अब हमने खोला है। उस मशीनरी की कीमत 82 करोड़ रुपये थी और उसके ऊपर उन्होंने 90 करोड़ रुपये ब्याज मांग लिया। हमने उनसे कहा कि इसका ब्याज कम कर दो। उनकी बहुत समय से पेमेंट रुकी पड़ी थी और कोई पेमेंट वापिस नहीं कर रहा था इसलिए उन्होंने कहा अगर आप लोग ब्याज और रकम एक साथ हमें दे देंगे तो हम यह ब्याज कम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने उनको 82 करोड़ रुपये रकम के और 35 करोड़ रुपये ब्याज के एक साथ दिये। यह पैसा हमने पब्लिक से रेज करके दिया। इसके अलावा जो बाकी कसर रहेगी, वह भी बिजली बोर्ड पब्लिक से ही रेज करके पूरी करेगा, इसलिए बजट में इसका प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि इस छठे प्लांट पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इन भाईयों में थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये चीज के नजदीक से निकल जाते हैं और वह चीज इन्हें दिखाई नहीं देती तो इसमें मेरा क्या कसूर है ? अध्यक्ष महोदय, इस प्लांट का कूलिंग टावर बनने लग रहा है उस पर बड़ी तेजी से काम चालू है

और बी०एच०ई०एल० वालों ने मौके पर टरबाईन और बायलर पर काम चालू कर दिया है, एम०आई०टी०सी० भी टावर्ज पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्लांट पर 14 टावर्ज बनने हैं और हर टावर की ऊंचाई 110 फुट होगी। इनमें से 4 टावर 110-110 फुट ऊंचे बनकर तैयार हो गये हैं लेकिन अगर चौ० संपत सिंह को ये दिखाई नहीं देते तो मैं इसमें क्या करूं, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिविल वर्क भी इस प्लांट पर बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, 1988-89 के एच०एस०ई०बी० के जो एनुवल फाइनेनशियल स्टेटमेंट बजट अस्टीमेट्स हैं, इसमें आप बतायें कि क्या आपने एक भी नये पैसे का प्रोविजन इसके लिए रखा है ? चाहे आप पब्लिक से लोन लें, चाहे पब्लिक फंड रेज करें या चाहे बाहरी इन्स्टीच्यूशनज से फंड लें अगर आपने ओन गोईंग स्कीम में कहीं पर भी छठे यूनिट का जिक्र किया है तो आप बतायें ? (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर ये सुनेंगे तो ही मैं बताऊंगा, आप इन्हें कहें कि ये ध्यान से सुनें। अध्यक्ष महोदय, हम आशा करते हैं कि हमारा यह छठा यूनिट अगले साल दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। इन्होंने यह भी कहा कि यूनिट एक से चार तक 100 करोड़ रुपये में ठीक होकर तैयार हो जाते हैं मगर एच०एस०ई०बी० ने इसका 400 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने यह ठेका बड़ी छानबीन करके दिया है। इसके लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई और उस सब कमेटी ने सबको बुलाया। इसमें एच०एस०ई०बी० को भी बुलाया, दूसरी सब कम्पनीज को भी बुलाया। यह एक ग्लोबल टैंडर था। बाद में यह टैंडर जर्मनी की ए०बी०बी० कंपनी को दिया गया है। इसमें 300 करोड़ रुपये के करीब खर्चा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें इसका मोर्डेनाईजेशन भी हो जायेगा, रिफर्निसींग भी हो जायेगी, लाईफ एक्सटैंशन भी हो जायेगी यानी सब काम हो जायेंगे। जब ये चारों प्लांट्स हमारे तैयार हो जायेंगे तो यह 300 करोड़ रुपये का खर्चा हमारा एक साल में ही पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अब ये चारों प्लांट्स 26 से 30% प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहे हैं लेकिन ए०बी०बी० की कंपनी इनको मिनीमम 80% प्लांट लोड फैक्टर पर इनको चलाकर देगी। इस तरह से हमारी बिजली 250 से 270 मेगावाट बढ़ जायेगी। इसके अलावा 110-110 मेगावाट के हमारे जो 4 प्लांट्स हैं वे 118-118 मेगावाट के हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको बताया कि यह काम ग्लोबल टैंडर से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने कहा कि यमुना नगर के प्रोजैक्ट के लिए इस साल बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि कम रखा गया है। मैंने शायद 22 या 28 करोड़ बताया था जो कि कम है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इंडिपैंडैंट तौर पर ग्लोबल टैंडरज़ मांगे हैं और ग्लोबल टैंडरज़ की कार्यवाही अब से पहले शुरू हो चुकी है। कण्डीशन्ज़ के मुताबिक ग्लोबल कार्यवाही शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि किसानों के 12 हजार ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन्ज़ घट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी दो तीन बातें हैं। कुछ आदमी तो इन भाईयों के चक्कर में आ गए और बिजली के बिल जमा नहीं करवाए जिसके कारण उनके कनैक्शन्ज़ कट गए। अब ये उन्हें कहते हैं कि कुण्डी लगा कर काम चलाओ। दूसरी बात इनके घटने की यह है कि कुछ लोग डीज़ल के इन्जन ले आए और वे डीज़ल के इंजन पर डिपैंड हो गए क्योंकि हमारे यहां बिजली कम मिल रही है और तीसरे इनमें घटने की वजह यह भी है कि कुछ ऐसे किसान हैं जैसे कि अहीरवाल के एरिया के लोग हैं उन्हें पूरे साल बिजली की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी अब मिनिमम पैसा देना

[श्री बंसी लाल]

पड़ेगा, वे लोग 3-4 महीने बिजली इस्तेमाल करते हैं। अध्यक्ष महोदय अब हम उनको सुविधा दे रहे हैं कि मर्जी आए तो मीटर लगवाओ मर्जी आए तो मीटर कटवा दो हम फसल के समय उनको दोबारा मीटर लगा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ कनैक्शन्ज इस लिए भी कट गए हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अहीरवाल में झज्जर जिले का कुछ ऐरिया है और मेरा हल्का बादली भी सेम से अफैक्टिड ऐरिया है। झज्जर सब-डिवीज़न कोसली का इलाका सेम से प्रभावित है वहां पर सेम की जमीन है। (विघ्न) मैं यह चाहता हूं कि जिस-जिस इलाके में मार्च और अक्तूबर के बीच में बिजली की खपत नहीं है, वहां पर भी यह सुविधा प्रदान करें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन इलाकों में भी हम यह सुविधा दे रहे हैं। अगर किसान अपने ट्यूबवैल के लिए मीटर लेना चाहता है तो उसको मीटर लेने की सुविधा है इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है और मीटरज़ लगाए भी जा रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, हमारा ट्रांसमीशन तथा डिस्ट्रिब्यूशन का सिस्टम बहुत कमजोर हैं उसको स्ट्रैंथन करने के लिए मैंने आपके जरिये कल भी सदन को बताया था, आज फिर उसको दोहरा देता हूं। 1999-2000 तक ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन्ज़ देने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा था कि लाईन लौसिज़ 60% हैं (विघ्न) मगर हमारे लाईन लौसिज़ 33% हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पूरी सप्लाई चालू हो जाएगी तो इसमें सुधार हो जाएगा। हमने कन्ज्यूमर्ज़ की चैकिंग का कम्पैन चलाया हुआ है और हमने 6,55,615 कंज्यूमर्ज की चैकिंग की है। इसमें भी हमने ज्यादातर इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र की चैकिंग की है जहां पर थैफ्ट ज्यादा होती है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया है कि लाईन लोसिज़ 33% हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद माना है कि बिजली के मामले में किसानों का कनैक्टिड लोड 29% है जबकि इन्होंने इस साल 43% बिजली की खपत दिखाई है। 29 प्रतिशत हमारा कनैक्टिड लोड है लेकिन उसके बाद हम उसको इस्तेमाल नहीं करने देते हैं क्योंकि रेट बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक बी०एच०पी० पर एक ऐडिशनल हार्स पावर की मोटर मिल जाए तो उसको पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है। स्पीकर साहब, इसका मतलब है कि वह कनैक्टिड लोड से फालतू बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वह पकड़ा जाता है तो 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना उसको लगा दिया जाएगा। स्पीकर साहब, इस तरह से उसके एक तिहाई दिन ऐसे होंगे जो अन-यूटिलाईज हो जाएंगे और दो तिहाई दिन ही यूटिलाईज रहेंगे फिर तो अपने आप ही बिजली की चोरी होगी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने थैफ्ट के 14,566 केसिज डिटैक्ट किए हैं जिसमें 11,782 केसिज में एफ०आई०आर० लॉज की हैं। हमने 14 करोड़ 87 लाख रुपये की पैनल्टी इम्पोज की है। मई 1996 से मार्च 1998 तक हमने दो लाख बिजली के नए मीटर्ज इन्स्टाल किये हैं और अगले 2 सालों में साढ़े चार लाख और नए मीटर्ज हम लगा देंगे जोकि थैफ्ट प्रूफ होंगे। हम मोटे तौर पर लाईन लौसिज़ का ब्रेक अप लगाते हैं। हाई टैन्शन लैवल पर 10 प्रतिशत टैक्नीकल लोस, लो टैन्शन लैवल पर 8 प्रतिशत टैक्नीकल लोस और थैफ्ट में हम 15 प्रतिशत टैक्नीकल लोस लगाते हैं। जो यह थैफ्ट का टैक्नीकल लोस है, वह 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने एक बात कही कि मैं इनके वक्त में केवल 55 मैगावाट बिजली ही छोड़ कर गया था बाकि तो सब इन्होंने ही लगाई है। इस बारे में मैं इनको बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 18-4-79 को

8-8 मैगावाट के दो हाईडल प्रोजैक्ट्स चालू हुए थे जो कुल मिलाकर 16 मैगावाट बनते हैं। इसके अलावा इनके वक्त में पानीपत थर्मल प्लांट का 210 मैगावाट का पांचवा यूनिट आया था जिसका प्रोडक्शन चौधरी भजन लाल के वक्त में शुरू हुआ था और मेरे वक्त में भी चलता रहा था। इसके अलावा इनके टाईम का मुझे और तो कुछ मिला नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्त में मैं 236 मैगावाट की इन्स्टाल कपैस्टी छोड़ गया था। उसमें 16 मैगावाट के दो हाईडल प्लांट्स, 55-55 मैगावाट के दो प्लांट्स फरीदाबाद में और 110 मैगावाट का एक प्लांट पानीपत थर्मल प्लांट में छोड़ कर गया था। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इनका जोड़ लगाएं तो यह 236 मैगावाट बनता है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये हमें यह बता दें कि जनरेशन किस के वक्त में आई थी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये भी मुझे यह बता दें कि 13-6-86, 1-6-87, 22-11-74, 6-3-76 और 11-1-87 को मुख्य मंत्री कौन था ? आप सच्ची बात तो मान लिया करें। आप अपना भाषण कितना लम्बा दें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है लेकिन आप सच्ची बात मान लिया करें। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी ने कह दिया कि सात सौ करोड़ रुपये की सबसिडी का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं इनका ध्यान मैमोरैन्डम ऑफ एक्सप्लानेटरी नोट ऑन बजट की ओर केन्द्रित करना चाहता हूँ। आप इसमें पेज नम्बर 51 पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि :—

> "During 1997-98 subsidy of Rs. 679.94 crore was provided to the Board. During the year 1998-99, the State Govt. is contemplating to provide Rs. 700 crores as Rural Electricity subsidy out of which Rs. 364 crores have been provided as cash subsidy."

श्री सम्पत सिंह : फिर यह बिजली बोर्ड ने झूठ का पुलिन्दा क्यों छाप रखा है ? आप बिजली बोर्ड का ऐस्टीमेट देख लें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह 700 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड ने नहीं देना है बल्कि यह स्टेट गवर्नमैंट को देना है।

श्री सम्पत सिंह : स्टेट गवर्नमैंट का इसमें कुछ और लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ लें।

श्री बंसी लाल : आप इसको घर जाकर पढ़ लेना।

श्री सम्पत सिंह : जो पैसा स्टेट गवर्नमैंट ने दिया, वह भी इसमें लिखा हुआ है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक जो हम बिजली दे रहे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 22-7-98 को हमने 427.60 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को 356.15 लाख यूनिट बिजली दी। इसी तरह से इस साल 23 तारीख को हमने 442.59 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 380.10 लाख यूनिट बिजली दी। इसी प्रकार से 24-12-98 को हमने 433.67 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 390.49 लाख यूनिट बिजली दी। इसी तरह से इस साल 25 तारीख को हमने 430.05 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 380.33 लाख यूनिट बिजली दी। इसी प्रकार से इस साल 26 तारीख को हमने 434.69 लाख यूनिट्स बिजली दी और पिछले इसी तारीख को हमने 383.17 लाख यूनिट बिजली दी और 27-7-98 को यानी कल हमने 423.92 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले

[श्री बंसी लाल]

साल इसी तारीख को हमने 398.05 लाख यूनिट बिजली दी। अध्यक्ष महोदय, हम पूरी मुस्तैदी से बिजली दे रहे हैं, पूरी कोशिश से हम इस बारे में लगे हुये हैं। लेकिन जो ढांचा ये लोग और पहले वाली सरकार छोड़कर गयी थी, उसको सुधारने में हमें कुछ समय लगेगा। कुंआ खोदने के बाद तो वह मुश्किल से ही भरता है। मैं इनका खोदा हुआ कुंआ भरने में लगा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। श्री नफे सिंह राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हत्यारों को संरक्षण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से जब दिल्ली में एक प्रतिनिधि मंडल मिला था तब मैंने कहा था कि चाहे बीस आदमी मर जाएं मैं क्या ठेकेदार हूँ। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मैं या मेरा कोई भी रिश्तेदार किसी मुलजिम को कभी नहीं छिपाता। यह काम तो इनका ही है। ये ही ऐसा काम करते हैं। मेरे पास एक डैपुटेशन जरूर आया था। उससे पहले वाले दिन शाम को इन्होंने डी०आई०जी० (सी०आई०डी०) को टेलीफोन किया था कि हमारे मुलजिम को सी०एम० या सी०एम० के लड़के ने अपने घर में छिपाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब उनका टेलीफोन हमारे पास आया, उससे पहले ही वह मुलजिम हम शिमला में गिरफ्तार कर चुके थे। जबकि वह इनको मेरे घर बता रहे हैं। बाद में मेरे पास दस या बारह आदमियों के साथ एक लम्बा चौड़ा आदमी भी आया था और मेरे से मिलने के बाद वे सीधे चौधरी देवीलाल जी और चौटाला जी के घर गए। लेकिन उनमें से दो या तीन आदमी फिर अगले दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे से गलती हो गयी। हमने एम०एल०ए० और उस लम्बे चौड़े आदमी सरपंच के बहकाने से ऐसा कह दिया था। परन्तु अब हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जितना * * * होता है वह सब यही सिखाते हैं क्योंकि इनका काम यही है और इनको कोई काम है ही नहीं। इसके अलावा असैम्बली के दूसरे मैम्बर्ज ने और भी बातें कहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * लफ्ज क्या पार्लियामेंट्री है। ये जो चाहें कह दें तब तो ठीक है लेकिन रामबिलास जी की हमारी इस बात पर भी आपत्ति है कि गुमराह शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाए जोकि उर्दू का लफ्ज है। लेकिन ये हमेशा सारे * * * * की बात करते रहते हैं।

श्री बंसी लाल : कोई बात नहीं इस शब्द को निकाल दो।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री बंसी लाल : मैम्बर साहेबान ने भी कई बातें उठाई हैं जो बातें इन्होंने उठाई हम उन सबके ऊपर गौर करेंगे और जो बातें जायज हैं उनको हम करेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आप आर्डर है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया बहादुरगढ़ के 20 आदमियों का एक प्रतिनिधिमंडल इनसे दिल्ली में दिनांक 18-4-98 को मिला था। उस प्रतिनिधि मंडल में हरियाणा विकास पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, भी शामिल थे, पूर्व मंत्री भी शामिल थे और भाजपा के लोग भी शामिल थे।

श्री अध्यक्ष : इसमें प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वह असत्य है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by one hour.

Voice : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by one hour.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now the demands and cut motions will be put to the vote of the House.

First of all, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demand to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,84,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 2,88,36,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 1–Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 2 of Rs. 1,61,42,11,000/- on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 99,56,89,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 58,64,79,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 2–General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 4,47,77,91,000/- on account of Home be reduced by Rs. 1,00,000/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,76,30,73,000/- for revenue expenditure and Rs. 10,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,53,58,44,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 3–Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 4 of Rs. 97,17,80,000/- on account of Revenue be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.31,14,23,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs.66,03,55,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No.4–Revenue.

The motion was carried.

Demand Nos. 5 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.19,58,84,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs.22,88,18,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No.5–Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs.2,75,91,06,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs.2,64,41,92,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No.6–Finance.

That a sum not exceeding Rs. 3,16,08,18,000/- for revenue expenditure and Rs. 9,33,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 4,32,97,58,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No.7–Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 8 of Rs. 4,94,13,45,000/- on account of Building and Roads be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 2,04,85,49,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,53,61,45,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 99,85,03,000 and capital expenditure amount of Rs. 34,73,48,000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 8– Building & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद) : स्पीकर सर, हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। चण्डीगढ़ कैपिटल के बारे में बार-बार जिक्र आता है कि हम फलां एरिया लिए बगैर चण्डीगढ़ को नहीं देंगे। एक-एक करके अलग-अलग एमैंडमेंट भारत सरकार से आते हैं जिनकी वजह से हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। मैं सिर्फ ऐजुकेशन के बारे में जिक्र करूंगा। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, डी०पी०आई० और विधानसभा के दो सदस्य सीनेट के मैम्बर चुने जाते थे। अब भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"The Ministry of Home Affairs, Government of India vide a Gazette notification dated October 27, 1997 (copy enclosed) has amended the Panjab University Act. Vide above notification, the membership of the Panjab University Senate in respect of the following has been permanently terminated."

जो ये मैंने ऊपर नाम बताये हैं उन सदस्यों के नाम रजिस्टर्ड काऊंसिल के लिए डिलीट कर दिये गये हैं जिसके कारण पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा प्रदेश की दखलअंदाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या वर्तमान सरकार ने इसके बारे में कोई एतराज किया है ? क्योंकि केन्द्र में गृह मंत्री अभी तो अडवाणी जी हैं क्या उनको इस बारे में कोई रिप्रेजंटेशन दिया है उनको कोई रिक्वैस्ट की है कि हमारा क्लेम खत्म हो गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ठीक कह रहे हैं। इस तरह का एक कम्यूनिकेशन हमारे पास भारत सरकार का आया है उसके बाद 25 तारीख को मैं भारत सरकार के गृहमंत्री जी से मिलकर आया हूँ तथा अगली चार तारीख को हम प्राईम मिनिस्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार को लिखा है। हमने अपना प्रोटैस्ट दर्ज करा दिया है और मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इस मुद्दे को दुरूस्त करा लेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 13,78,48,17,000/- on account of Eudcation and Roads be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.7,50,93,02,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 6,27,55,10,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 9–Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

श्री सम्मत सिंह (फतेहाबाद) : स्पीकर सर, मैं लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाहता । मैं होस्पीटल्ज में दी जाने वाली कंसेशनल मैडीसन्ज के बारे में जिक्र करूंगा। वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए जो 8 करोड़ रुपये का प्रोवीजन रखा है उसके हिसाब से यह हरियाणा की दो करोड़ जनता को 4 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आता है। इसमें डाक्टर्ज के अपने जानने वाले रिश्तेदार भी हैं और हमारे जैसे बी०बाई०पीज० लोग भी हैं। फिर आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि इतने थोड़े बजट में गरीब आदमी के हिस्से में तो कुछ भी दवाई नहीं आयेगी। ये लोग ही बहुत बड़ी मात्रा में मैडीसन ले जायेंगे और आम आदमी के हिस्से में कुछ भी नहीं आयेगा। गरीबों को मैडीसंज न मिलने से प्राईवेट होस्पिजल्ज वाले गरीब लोगों के शरीर को चीर-फाड़ कर छोड़ देंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि चार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मैडीसन के लिए बजट में रखना नाकाफी है।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 10 of Rs. 7,72,75,77,000/- on account of Medical and Public Health be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,54,07,70,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,09,77,73,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,57,11,47,000 and capital expenditure amount of Rs. 51,63,27,000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 10–Medical & Public Health.

The motion was carried.

Demand No. 11

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 11 of Rs. 51,59,97,000/- on account of Urban Development be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.31,94,64,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 19,65,33,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 11–Urban Development.

The motion was carried.

Demand No. 12

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.34,09,98,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 29,21,79,000/- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 12–Labour & Employment.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 13 of Rs.2,69,98,86,000/- on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,81,17,15,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,78,36,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 85,11,71,000 and capital expenditure amount of Rs. 51,63,27,000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 13–Social Welfare & Rehabilitation.

The motion was carried.

Demand No. 14

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.9,26,54,000/- for revenue expenditure & Rs.91,83.79,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,21,17,000 and capital expenditure amount of Rs. 3,96,84,47,000 already voted on account) in respect of charges under Demand No.14–Food & Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker : Sampat Singh ji, would you like to speak on it ?

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद) : जी हां, अध्यक्ष महोदय, हम ने जो कट मोशन नं० 9 डिमांड नं० 15 पर दिया है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। यह सिंचाई विभाग का कट मोशन है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 12 मई, 1994 को एक लम्बे अर्से से चले आ रहे झगड़े पर यमुना वाटर समझौता हुआ था। जब यह यमुना जल समझौता हुआ था तो इसका आपने भी विरोध किया था और हम ने भी विरोध किया था। हम ने क्या-क्या किया होगा, वह बात अलग है लेकिन चौधरी बंसी लाल जी ने उस वक्त जो कुछ कहा था, वे सारी बातें अखबारों में छपी थीं। चौधरी बंसी लाल ने उस वक्त कहा था कि यमुना जल समझौता करके भजन लाल ने हरियाणा के साथ विश्वासघात किया। फिर ये बोले कि यमुना समझौता हरियाणा के हित में नहीं है and Bansi Lal demanded Bhajan Lal's sack. भजन लाल के शासनकाल में हरियाणा के हितों की बलि, यमुना जल समझौते से हरियाणा के हितों को आघात पहुंचा, At that time Bansi Lal had stated that Bhajan Lal has sold Haryana's interest, फिर इन्होंने यह भी कहा था कि यमुना जल समझौते के विरोध में हरियाणा विकास पार्टी असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। 5 जून को चौधरी बंसी लाल का जवाब आया था कि खुराना की धमकी के आगे भजन लाल ने घुटने टेके। अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरा एक अतारांकित प्रश्न भी था कि क्या यमुना जल समझौता हुआ,है तो क्या वह हमारे हित में हुआ है ? इस पर मुख्यमंत्री महोदय, ने हां में जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त तो भजन लाल जी ने घुटने टेक दिए थे, क्या अब इन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जो काम पिछली सरकार कर लेती है, वह अगली सरकार पर लागू होते हैं क्योंकि गवर्नमैंट एक कंटीन्यूड प्रोपैस है। 5 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्ज ने बैठकर जो फैसला कर लिया हो, जो एग्रीमैंट उस समय हो गया हो, उससे हम अब बैक आउट कैसे कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 15,32,44,38,000/- on account of Irrigation be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.2,33,37,38,000/- for revenue expenditure & Rs. 3,38,78,28,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs.5,74,47,00,000 and capital expenditure amount of Rs. 2,47,81,72,000 transferred from Demand No. 25 already voted on account) in respect of charges under **Demand No.15–Irrigation.**

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 16 of Rs. 62,91,82,000/- on account of Industries be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 29,53,18,000/- for revenue expenditure and Rs. 14,92,17,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,34,24,000/- and capital expenditure amount of Rs. 4,11,83,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No.16–Industries.**

The motion was carried.

Demand No. 17

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कट मोशन के माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान 3-4 ऐसे मामले जहां बड़े मेजर स्तर पर सब स्टैण्डर्ड दवाईयां और खाद सरकारी महकमों के द्वारा हरियाणा के किसानों को दिए गए की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिनमें से कुछ की इन्कवायरी करवाई गई। कुछ आफिसर्ज के खिलाफ इस बारे में इन्कवायरी रिपोर्ट भी आ गई है। जीन्द में भी इस तरह का एक मामला था जहां पर किसानों को तिलहन की फसल के लिए जिप्सम सबसीडाइज्ड रेट पर मुहैया नहीं करवाया गया। चन्द लोगों ने जब इस बारे में इसकी शिकायत की तो ए०डी०सी०, जीन्द ने 17-4-97 को उसकी इन्कवायरी करवाई जिसमें ये शिकायत सच पायी गयी। ए०डी०सी०, जीन्द ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसकी चन्द लाईने मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि "उपरोक्त विवरण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समाचार पत्र में इस बारे में प्रकाशित समाचारों में लगाए गए आरोपों में सच्चाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिले में तिलहन फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की 90 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम किसानों को वितरित करने की योजना सही रूप से क्रियान्वित नहीं हुई है। अधिकांश लाभार्थियों के नाम पर या तो जिप्सम झूठा वितरित किया गया है या उनके नाम से प्राप्त करके उनके खेतों में प्रयोग न करके दूसरे किसानों के खेतों में प्रयोग हुआ है। इसके साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा योजना के अन्तर्गत अनुदान पर जिप्सम प्राप्त करके

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

भी तिलहनी फसलों के लिए उपयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पाया है।" सर, इसमें कई लाख रुपयों की हानि हुई। मैंने इस सारे मामले के बारे में इस इन्कवायरी रिपोर्ट के साथ एक पत्र लिखकर 6 जून 1998 को मुख्यमंत्री को भेजा था लेकिन आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। 3-4 ऐसे मामले हैं जिनके एफीडैविट मेरे पास हैं और जिनके बारे में सरकार को लिखा गया है। लेकिन आज तक भी दोषी ओफिसर्ज के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 17 of Rs. 2,51,87,51,000/- on account of Urban Development be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.1,53,66,67,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 98,09,34,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 17–Agriculture.**

The motion was carried.

Demands Nos. 18 to 20

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.51,51,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs.48,17,01,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 18–Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs.5,33,76,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 2,84,07,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 19–Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs.60,00,54,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditureamount Rs. 22,29,61,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 20–Forest.**

The motion was carried.

Demand No. 21

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 21 of Rs. 1,28,47,31,000/- on account of Urban Development be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs.82,13,54,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount Rs. 46,32,92,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 21–Community Development**

The motion was carried.

Demands No. 22

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 22 of Rs. 39,75,13,000/- on account of Co-operation be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 11,80,10,000/- for revenue expenditure and Rs.11,15,38,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 13,43,98,000/- and capital expenditure amount of Rs. 3,35,62,000/ already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 22–Co-operation.**

The motion was carried.

Demand No. 23

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 23 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। जो रिवाड़ी का बस अड्डा है उसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। उस पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने बेरोजगारों को रूट परमिट्स देने का वायदा किया था लेकिन रिवाड़ी जिले के किसी भी बेरोजगार नौजवान को पिछले दो साल के अन्दर एक भी रूट परमिट नहीं दिया गया है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो मैक्सी कैब चल रही हैं वे बिना टैक्स भरे चल रही हैं। लगभग 10 हजार मैक्सी कैब ऐसी हैं जो बिना टैक्स दिए सड़कों पर घूम रही हैं और उनसे बहुत ज्यादा एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। सरकार ने यह खुद माना है कि 2597 मैक्सी कैब को रूट परमिट दिए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े नेता हैं उनकी वे मैक्सी कैब चल रही हैं। ये बाकायदा बी०जे०पी० के कार्यकर्ताओं की चल रही हैं। (शोर) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो डीलक्स बसिज हैं उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बार-बार कहा है कि आप डीलक्स बसिज की सीट्स अच्छी बनाएं और कम्फोरटेबल बनाएं। लोग इनमें किराया दे कर सफर करते हैं लेकिन उनकी सीटें कम्फोरटेबल न होने के कारण लोग उनमें नहीं बैठते हैं बल्कि वे दूसरी बसों में बैठते हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That Demand No. 23 of Rs. 5,46,31,11,000/- on account of Transport be reduced by Re 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,86,45,35,000/- for revenue expenditure and Rs.29,59,33,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,11,30,66,000/- and capital expenditure amount of Rs. 18,95,67,000/ already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 23–Transport.**

The motion was carried.

Demand Nos. 24 & 25

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 95,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,88,67,000/0 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 53,75,000/- and capital expenditure amount of Rs. 1,34,33,000/- already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24–Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 2,47,81,72,000/- out of Rs. 6,05,71,90,000/- already voted on account for capital expenditure be transferred to Demand No. 15 to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 under that demand & balance amount of Rs. 3,57,90,18,000/- already stands voted on account under **Demand No. 25–Loan and Advances by State Government for the year 1998-99.**

The motion was carried.

बिल्ल

(i) हरियाणा सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker : Now the Co-operation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1998 and he will also move the motion for its consideration.

Co-operation Minister (Shri Narbir Singh) : Sir, I introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1998.

Sir, I also move—

That, the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Co-operation Minister will move that the Bill be passed.

Co-operation Minister (Shri Narbir Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, इस संबंध में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सिक कोओपरेटिव सोसायटीज हैं, उनको सरकार पहले खुद संभालने की कोशिश करें क्योंकि इनको सीधा प्राईवेट सैक्टर में देना उनके व सरकार के हित में नहीं होगा।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker : Now, the Town & Country Planning Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

शहरी संपदा मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

> कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1998 पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की दो अमैंडमैंट्स पर मेरा ओब्जैक्शन है एक तो मेरा आब्जैक्शन इस बिल की सैक्शन 2 की कलॉज चार पर है इसमें दिया है कि—

> "Commissioner" means the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

पहले कमिश्नर मीन्ज कमिश्नर अम्बाला डिवीजन था और अब इसकी जगह कमिश्नर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग चण्डीगढ़ किया है। इस बिल के स्टेटमेंट आफ औब्जैक्टस् एण्ड रीजन्ज में जो दिया गया है उससे बड़ी हैरानी होती है। इसमें लिखा है कि—

"The persons aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner-cum-Director, Town & Country Planning, Haryana may prefer an appeal to the Commissioner of the Ambala Division. However, it has been experienced that in the absence of expert advice, the Commissioner of the Division is not able to fully appreciate the provisions of the Act and the Rules."

पहली बात इसमें यह है कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके पास कोई असिस्ट करने वाला ही नहीं है। कमिश्नर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग जो आया है, उसकी पोस्टिंग भी तो अम्बाला हो जाएगी और वह भी अम्बाला से यहां आ जाएगा इसका उसके पास कोई ऐसी असिसटैन्स या उसके पास कोई एक्सपर्ट या उसकी अपनी कोई ओपीनियन नहीं है बल्कि यहां वाले कमिश्नर का ज्यादा ओपीनियन होगा। दूसरा इसमें लिखा है कि—

"Moreover, the aggrieved persons have to go to Ambala for filling appeals. Hence there is a case to make the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning, Department, the appellate authority instead of Divisional Commissioner by amending section 2(4) of the Act."

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से अम्बाला दूर है या चण्डीगढ़। ये कह रहे हैं कि उनके लोगों के लिए वहां जाकर अपील दायर करना मुश्किल होता है इसलिए अपील फाइल करने के लिए अप्रोप्रियट जगह अम्बाला ही ठीक है बजाय चण्डीगढ़ के। चण्डीगढ़ तो 50 कि०मी० और आगे है। (विघ्न एवं शोर)

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह चण्डीगढ़ के लिए है, यह चण्डीगढ़ के नजदीक है और यह चण्डीगढ़ से 16 कि०मी० अंदर रहेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह इलाका तो हमारा है, जो हमारा पैरीफैरी एरिया है आप उसके लिए ही कह रहे हैं और उसी के लिए मैं भी कह रहा हूं। (विघ्न एवं शोर) Speaker, Sir, I would like to quote Section 13A of Clause 8, which is proposed to be inserted, which says as under :—

"Bar of jurisdiction-No civil court shall have jurisdiction to entertain or decide any question relating to matters falling under this Act or the rules framed thereunder."

अध्यक्ष महोदय, क्या सिविल कोर्ट की जुरीशडिक्शन से भी इसको निकाल रहे हैं ? एक आदमी जिसका यह फण्डामेंटल राईट है और अगर वह वहां न जाये तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इस बारे में जो क्लॉज है अगर उस को सेठ जी नहीं मानते तो वे यह मान लें और इस क्लाज को निकाल दें। (विघ्न एवं शोर)

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, लोग इसे नाजायज बनाते हैं, कोर्ट में जाकर 10-10 साल तक उसका फैसला नहीं होने देते। अध्यक्ष महोदय, दीवानी की कोर्ट्स में इस तरह के केसिज का 10-10 साल तक फैसला नहीं होता है और लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें कहां बीच में फंसा दिया।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या और अपीलें कोर्ट में नहीं जाती ? जब और अपीलें कोर्ट में जाती है तो फिर यह अपील क्यों नहीं जा सकती या फिर दूसरी सारी अपीलें वापिस ले ली जाएं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control, (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Question is—

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister for Town & Country Planning will move that the Bill be passed.

नगर एवं आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस बिल की सैक्शन 11 की क्लॉज पांच की तरफ दिलाना चाहूंगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि कन्वर्शन चार्जिज़ के पेमेंट पर परमिशन दे दी जाएगी चेन्ज ऑफ लैण्ड यूज़ की जो इसमें पहले नहीं थी। सर, इसमें 2 बातें हैं। एक बात पंजाब न्यू कैपिटल पैरीफेरी कन्ट्रोल एक्ट है यह फिस्कल स्टैच्यूट नहीं

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

18.00 बजे है और जो फिस्कल स्टैच्यूट नहीं है उसमें से आप छोड़ सकते थे क्योंकि इस प्रकार का फीका प्रावधान पहले ही है, वह आप कर सकते थे इसलिए इस स्टैच्यूट का बेसिक परपज़ पैसा कमाना नहीं है। अब जो मन्त्री जी ने अमैंडमैंट की है उसके माध्यम से यह अख्तियार एग्जैक्टिव को दिया गया है कि किसी प्रकार की कन्वर्शन ऑफ लैंड यूज़ में परमिशन दे कर अपने मनमाने रेट पर पैसा इकट्ठा किया जाए। मेरे विचार से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं आपका ध्यान स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज के पैरा-4 की तरफ दिलवाऊं तो उसमें साफ लिखा है—

> "...Since there is no enabling provision in the Act to levy conversion charges, for converting the land use within the controlled area, a suitable provision to levy conversion charges in the first part of Section 11(1) is required."

सर, आपको याद होगा कि सरकार पिछले सत्र में पंजाब शैडयूल्ड रोड्ज के अन्दर भी इसी प्रकार की अमैंडमैंट ले कर आई थी उस अमैंडमैंट की वैधता भी आज अण्डर चैलेंज है। नॉन फिस्कल स्टैच्यूट को अगर आप पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बनाएंगे और दूसरे अगर आप सरकार को यह पूर्ण हक देंगे कि वह किसी प्रकार की लैण्ड यूज़ गेन करके उसमें से पैसा बनाएं तो मेरे विचार से न यह प्रान्त के हित में होगा और न ही इस सदन को यह बात माननी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 29th July, 1998.

*6.03 P.M. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 29th July, 1998)